



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 2017/अग्रहायण 17, 1939

No. 324]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2017/ AGRAHAYANA 17, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2017

(अंतिम जांच परिणाम)

**विषय:** चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "चाकूओं और प्रसाधन मदों को छोड़ कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

**फा. सं. 14/05/2016-डीजीएडी:** यतः ऑल इंडिया पोटरी मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) और इंडियन सेरामिक सोसाइटी (जिसे आगे याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) ने संबंधित अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए चीन जनवादी गणराज्य(जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "चाकूओं और प्रसाधन मदों को छोड़ कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर" (जिसे आगे सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 13 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 14/05/2016-डीजीएडी द्वारा अधिसूचना जारी की जिसमें पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

3. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम के माध्यम से दिनांक 04 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या 14/05/2016-डीजीएडी जारी की है जिसमें वर्तमान जांच में अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई और दिनांक 15 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या 14/05/2016-डीजीएडी के माध्यम से एचएस कोड में सुधार करते हुए उपर्युक्त प्रारंभिक जांच

परिणाम का एक शुद्धि पत्र भी जारी किया। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 12 जून, 2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 27/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की।

#### ख. प्रक्रिया

4. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी को उक्त नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर उत्पादों के पाटन का आरोप लगाया गया है।
- ii. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- iii. प्राधिकारी ने जांच को उचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा दायर पर्याप्तसाक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध जांच की शुरुआत करने का निर्णय लिया। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।
- iv. प्राधिकारी ने भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रों के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध वस्तु के आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को जांच शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी है और उनसे जांच शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया है।
- v. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को भेजी थी।
- vi. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिनके व्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) से संगत सूचना मंगाने के लिए उन्हें निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं और उन्हें अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अवसर दिया है:-

- क. कांगफू सेरामिक मेनुफेक्चरिंग कंपनी
- ख. चांगसा जोयसेंट डिशवेयर कंपनी लिमिटेड
- ग. जिबो टाइमस्टोन इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
- घ. शंघाई फाइन-वी होमवेयर एंड गिफ्ट्स इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
- ङ. वीआरटी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- च. होजिआंग सेरामिक शेनझेन कंपनी लिमिटेड
- छ. शेनझेन गोल्डनवाल सेरामिक कंपनी लिमिटेड
- ज. किनहुआंगडो एचडीटी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- झ. कारोसा चाइनावेयर (शेनझेन) कंपनी लिमिटेड
- ञ. जिंगडेझेन एमशन पोर्सलेन कंपनी लिमिटेड
- ट. हनडन फेंगफेंग शेनगुआन सेरामिक कंपनी लिमिटेड
- ठ. लेता इंटरनेशनल ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ड. लिंटन इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड (रिझाओ)
- ढ. गुआंगसी युलिन सिटी जिआचाओ सेरामिक कंपनी लिमिटेड

vii. जांच शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना के संबंध में चीन के किसी निर्यातक/उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है।

viii. हल्के औद्योगिक उत्पादों और कला – शिल्प के आयात एवं निर्यात के लिए चीन चैंबर ऑफ कॉमर्स (सीसीसीएलए) तथा मैसर्स वालमार्ट इंडिया प्रा. लि. ने मूल समय-सीमाओं के समाप्त होने के बाद उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय विस्तार

की मांग की जिसे विधिवत इस प्राधिकारी द्वारा 19 दिसंबर, 2016 तक मंजूर किया गया था। आयातक ने समय की विस्तारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत किया जबकि सीसीसीएलए ने केवल कानूनी अनुरोध दायर किया। परंतु इसके किसी भी सदस्यों ने दी गई विस्तारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

ix. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक प्रश्नावली भेजी।

- क. के. एस. ओवरसीज
- ख. ईस्ट कोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
- ग. राज एजेंसीज
- घ. वाईएसआर इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
- ङ. वाल-मार्टइंडिया प्राईवेट लिमिटेड
- च. वाइटगोल्ड ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
- छ. आईसीसी रियल्टी (आई) प्राईवेट लिमिटेड
- ज. फ्यूचर रीटेल लिमिटेड
- झ. कृष्णा एंटरप्राइजेज
- ञ. कर्मा ट्रेडिंग

x. मैसर्स वालमार्ट इंडिया प्रा. लि., एक आयातक ने दी गई विस्तारित समय सीमा में आयातक की प्रश्नावली का उत्तर और कानूनी अनुरोध दायर नहीं किया था। मैसर्स हैमिल्टन हाउसवेयर प्रा. लि. ने 10 अप्रैल, 2017 को क्षति संबंधी अनुरोध दायर किया और 02 मई, 2017 को आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया जो उत्तर प्रस्तुत करने के लिए इस प्राधिकारी द्वारा दी गई समय अवधि अर्थात् 28 नवंबर, 2016 तथा 19 दिसंबर, 2016 तक बढ़ाए गए समय से काफी आगे था। इन अनुरोधों को सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया है और इस जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से इसका समाधान भी किया गया है।

xi. जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना की प्रति याचिकाकर्ताओं सहित विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात भारतीय उत्पादकों/एसोसिएशनों को भी भेजी गई थी।

xii. प्रत्युत्तर में निम्नलिखित ने याचिका के समर्थन में अपने पत्र प्रस्तुत किए हैं:

- क. यशवी एंटरप्राइजेज
- ख. अनिल फाइन सेरामिक्स
- ग. सम्राट सेरामिक्स
- घ. रघुवीर (इंडिया) लिमिटेड
- ङ. मारवल सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
- च. शी शेल सेरामिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
- छ. मुद्रिका सेरामिक्स (इंडिया) लिमिटेड
- ज. शान टेबलवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
- झ. फेदर टच सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
- ञ. ओसिस सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
- ट. टाटा सेरामिक्स लिमिटेड

xiii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच हेतु रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर अंतिमजांच परिणाम में विचार किया गया है।

xiv. गोपनीय आधार पर हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितवद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें और उसे नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।

xv. आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई। जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।

xvi. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन लागत और उसे निर्मित करने तथा उसकी बिक्री करने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत निर्धारित की गई है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xvii. यह जांच 1 अप्रैल, 2015 से शुरू होकर 31 मार्च, 2016 (जांच की अवधि) की अवधि में की गई थी। तथापि, क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2012 – मार्च, 2013, अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015 और जांच की अवधि (पीओआई) को शामिल किया गया है।

xviii. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच की अवधि समेत पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के व्यौरों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आकड़ों पर भरोसा किया है।

xix. प्रारंभिक जांच परिणाम 4.05.2017 को जारी किए जाने के बाद, हितवद्ध पक्षकारों से यह कहा गया था कि वे प्रारंभिक जांच परिणाम के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

xx. प्रारंभिक जांच परिणाम के जारी किए जाने के बाद, निम्नलिखित हितवद्ध पक्षकारों ने उक्त जांच के संबंध में अनुरोध प्रस्तुत किया और उसकी सिफारिशें भी प्रस्तुत कीं:

1. ब्लू माउंटेन इम्पैक्स (पी) लि.
2. के. एस. ओवरसीज
3. देवनो इंटरनेशनल
4. रागाश्री इम्पैक्स प्रा. लि.
5. डेको प्राइड इंडिया प्रा. लि.
6. विजय एक्जिम
7. अक्षिता इंटरप्राइजेज
8. व्हाइट गोल्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.
9. मैसर्स हैमिल्टन हाउसवेयर प्रा. लि.
10. हल्के औद्योगिक उत्पादों और कला – शिल्प के आयात एवं निर्यात के लिए चीन चैंबर ऑफ कॉमर्स
11. भारत में चीनी दूतावास

xxi. हल्के औद्योगिक उत्पादों और कला – शिल्प के आयात एवं निर्यात के लिए चीन चैंबर ऑफ कॉमर्स और भारत में चीन के दूतावास ने प्रारंभिक जांच परिणाम अथवा याचिका पर टिप्पणी करते हुए केवल अनुरोध प्रस्तुत किया गया और कोई मात्रा बताए जाने योग्य तथा सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा, चीन के किसी निर्यातकों ने कोई सूचना, अनुरोध अथवा निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

xxii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों को 13 जुलाई, 2017 को आयोजित मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी प्रदान किए। दूसरी सार्वजनिक सुनवाई निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन को देखते हुए 31 अक्तूबर, 2017 को आयोजित की गई। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 07.01.2011 की सिविल अपील संख्या 2006 की 949 में ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में निदेश दिया गया था। उन पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने

विचार प्रस्तुत किए थे, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें और उसके बाद प्रत्युत्तर को प्रस्तुत करें।

xxiii. इस सुनवाई में घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादक, आयातक, चीन चैंबर ऑफ कॉमर्स और चीन के दूतावास उपस्थित हुए। चीन के किसी निर्यातकों ने मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लिया और न ही आयोजित सुनवाई के परिणामस्वरूप कोई सूचना प्रस्तुत की।

xxiv. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों और सूचना का उनके साक्ष्यसे समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिमजांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उचित ढंग से विचार किया गया है।

xxv. जहां कहीं भी किसी हितवद्ध पक्ष ने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है या जांच में काफी बाधा डाली है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितवद्ध पक्षकार माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणामों को रिकार्ड किया है।

xxvi. एक प्रकटन विवरण 29.11.2017 को जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्य शामिल थे जिसमें प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने के लिए 06.12.2017 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने उपयुक्त रूप से हितवद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर विचार किया है।

xxvii. इस अंतिम जांच परिणाम में \*\*\* चिह्नकिसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

xxviii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनायी गई विनिमय दर 1अमरीकीडालर= 65.91रुपयेहै।

#### **ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

##### **घरेलू उद्योग के विचार नीचे दिए अनुसार हैं:**

5. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. विचाराधीन उत्पाद चीन जनवादी गणराज्यके मूल के अथवा वहां से निर्यातित चाकू और प्रसाधन मदों को छोड़कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर है।

ii. मिट्टी के बर्तन, बोन चाइना, स्टोनवेयर और पोर्सिलेनवेयर सभी सेरामिक उत्पाद हैं और इसलिए विचाराधीन उत्पाद में सेरामिक के किचनवेयर और टेबलवेयर शामिल हैं।

iii. शेपिंग और उसके बाद गैर धात्विक खनिज की फायरिंग द्वारा निर्मित विभिन्न कठोर, ब्रिटल, ताप-रोधी और जंग-रोधी सामग्री जैसे क्ले, उच्च ताप पर सेरामिक्स होते हैं। बोन चाइना को कैल्शियम फॉस्फेट (बोन एश), क्ले, फेल्सपार और क्वार्ट्ज पाउडर से विनिर्मित किया जाता है।

iv. टेबलवेयर, किचनवेयर, सर्व वेयर, कुक वेयर ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग इस व्यापार के दैनिक क्रियाकलाप में एक-दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है।

v. घरेलू उद्योग के संघटक विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन कर रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं। ये सभी वस्तु सेरामिक की व्याख्या के अंतर्गत आते हैं। विशेष रूप से, घरेलू उद्योग के संघटक बोन चाइना, पोर्सिलेन और स्टोन के टेबल वेयर और किचनवेयर का उत्पादन करते हैं।

vi. उत्पाद में विभिन्न विशेषताएं जैसे शक्तिशाली हाइड्रोफोबिक और ओलियोफोबिक विशेषताएं काफी नान-स्टिक विशेषता सेरामिक सतह के लिए स्वच्छता संरक्षण काफी एब्रेशन रोधी कम समय में सूखना, प्रयोग के बाद तुरंत स्टोर किया जा सकता है, तापमान परिवर्तन रोधी कमरे के तापमान पर सूखना, रासायनिक और एब्रेसन रोधी, मितव्ययी प्रयोग के जरिए उच्च कार्यक्षमता, खाद्य सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल, पूरी तरह से फ्रास्ट मुक्त हैं।

vii. संबद्ध वस्तु का उपयोग टेबल वेयर, किचन वेयर, सर्व वेयर और कुक वेयर आदि के रूप में सर्व करने, खाने, खाना बनाने और पीने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है।

viii. विनिर्माता उपभोक्ताओं में बोन चाइना शब्द के बारे में समझ और जागरूकता को देखते हुए अधिकांशतः विपणन की दृष्टि से उपयोग करते हैं। क्षेत्रीय कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, कच्चे माल और इसकी संरचना में समय-

समय पर थोड़ा परिवर्तन किया जाता है और उत्पादकों एवं बिक्री के माध्यमों ने नए बोन चाइना अथवा पोर्सिलेन अथवा स्टोन वेयर आदि के रूप में भी एक नया शब्द विकसित किया है।

ix. कच्चे माल में परिवर्तन मूल रूप से उपलब्ध कच्चे माल के माध्यम से वैसे ही रासायनिक लक्षणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उपयोग, उत्पादन, सेल्फ के जीवन के मामले में सभी एक समान हैं और इन्हें सामान्य रूप से सेरामिक्स के रूप में जाना जाता है।

x. सेरामिक टेबल वेयर, किचन वेयर और सर्विंग वेयर में तकनीकी लक्षणों के मामले में कोई अंतर नहीं है। एक मात्र अंतर कुछ मर्दों का विशिष्ट अंतिम उपयोग हो सकता है (उदाहरण के लिए एक चम्मच का उपयोग वहां नहीं किया जा सकता है जहां एक सॉसर की जरूरत होती है)। यह नाम इन मर्दों के उपयोग पर निर्भर करता है।

xi. दैनिक बाजार की बातचीत में, किचन वेयर और टेबल वेयर के बीच अंतर की पहचान करना मुश्किल है। पक्षकार टेबल वेयर शब्द का उपयोग विभिन्न प्रकार के सेरामिक टेबल वेयर, किचन वेयर और सर्विंग वेयर के पर्याय के रूप में करते हैं।

xii. टेबल वेयर और किचन वेयर के बीच अंतर बहुत अधिक सूक्ष्म है। यह बिना कोई व्यापारिक अंतर के केवल एक प्रकार की समझ है। उदाहरण के लिए केसोरोल, हांडी, बेक वेयर, कुक और सर्व वेयर आदि जैसे उत्पादों का टेबल वेयर तथा किचन वेयर दोनों के रूप में उल्लेख किया जा सकता है।

xiii. किचन वेयर में कुक वेयर की सभी मर्दें शामिल होती हैं जिसमें कुकिंग वेसल, सॉस पेन और फ्राइंग पेन आदि जैसे किचन में उपयोग किए जाने वाले बर्तन शामिल होते हैं। अन्य प्रकार से भी बहुत कम चुनिंदा मर्दें होती हैं जिनका वर्गीकरण अन्य रूप से टेबल वेयर अथवा किचन वेयर के रूप में किया जा सकता है। इनमें से अधिकांश उत्पादन एक सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

xiv. फायर क्ले को इस उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सेरामिक वेयर की श्रेणी के अंतर्गत पड़ता है और इसका आयात सेरामिक के नाम से किया जाता है। घरेलू उद्योग उसी का उत्पादन करता है। पहले मौखिक सुनवाई के दौरान एक नमूना भी प्रस्तुत किया गया था। फाइल क्ले सेरामिक वेयर की श्रेणी में आता है और इसका आयात सेरामिक के नाम से किया जाता है।

xv. जहां तक सब्लिमेशन कप का संबंध है, उसका उत्पादन घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा किया जा रहा है। घरेलू उद्योग न केवल प्लेन कप का विनिर्माण करते हैं बल्कि कोट किया हुआ कप तथा कोट किये हुए सफाई वाले कप का भी उत्पादन करते हैं। उसकी बिक्री का बीजक प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

xvi. प्राधिकारी ने (प्रथम) मौखिक सुनवाई के समय सही ही कहा था कि कथित कुक वेयर का आयात एक आयातक द्वारा इस उत्पाद को कुक वेयर और सर्व वेयर के रूप में कहते हुए किया गया था। इस प्रकार से यदि हितवद्ध पक्षकार किसी उत्पाद की बिक्री कुक वेयर और सर्व वेयर के रूप में कर रहे हैं तब यह माना जा सकता है कि इस उत्पाद का वर्णन करने में व्यापारियों अथवा आयातकों द्वारा किसी वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाया गया है।

xvii. बोन चाइना, स्टोन वेयर और पोर्सिलेन वेयर सभी सेरामिक उत्पाद होते हैं। यही दृष्टिकोण यूरोपीय आयोग द्वारा उसी उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में चीन के विरुद्ध पाटनरोधी जांच में अपनाया गया था।

xviii. घरेलू उद्योग ने आयात संबंधी आंकड़ों में उपलब्ध सूचना के आधार पर इस उत्पाद के आयातों का विश्लेषण किया है और यह पाया है कि कोई मानक, वैज्ञानिक अथवा सतत पद्धति को आयातकों द्वारा भारत में इस उत्पाद के आयात की सूचना देने में नहीं अपनाया गया है। आयात संबंधी आंकड़े एक वैश्विक रूप से स्वीकार किए जाने वाले और वस्तु पर परिभाषा को इन सामानों को अनुमोदित करते समय इन आयातकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न व्याख्याओं पर विचार करते समय उत्पाद के अलग-अलग प्रकारों को अलग-अलग करने के लिए दर्शाते हैं। आयात संबंधी आंकड़ों में आयातों को विभिन्न प्रकारों में अलग-अलग करने के लिए कोई विशिष्ट विशेषताएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए यह माना जा सकता है कि ये सभी उत्पाद अर्थात् बोन चाइना, पोर्सिलेन और स्टोन वेयर को सेरामिक वेयर के रूप में ही कब्जे में लिया जा सकता है और ये संबद्ध वस्तुओं के एक ही परिवार के हैं तथा इनकी सूचना अलग-अलग नहीं दी गई।

xix. उसी उत्पाद रूप का उपयोग किचन वेयर, सर्व वेयर अथवा टेबल वेयर के रूप में किया जा सकता है। किचन वेयर और टेबल वेयर, दोनों की पहचान सीमा शुल्क के अंतर्गत 6911 और 6912 के अंतर्गत आने वाले सेरामिक वेयर की रूप में की गई है। किचन वेयर में कुक वेयर की सभी मर्दें शामिल हैं जो कुकिंग वेसल, सॉस पेन और फ्राइंग पेन आदि जैसे किचन में उपयोग किए गए बर्तन शामिल हैं। इन उत्पादों में से अधिकांश सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

xx. अधिकांश आयात की सूचना इस बात की पहचान किए बिना की गई है कि क्या आयात किया गया उत्पाद बोन चाइना, पोर्सिलेन अथवा स्टोन है। घरेलू उद्योग भी कई बार इस बात का उल्लेख नहीं करते हैं कि क्या बेचे जा रहे उत्पाद बोन चाइना, पोर्सिलेन अथवा स्टोन है जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उत्पादक इस बात का उल्लेख किए बिना इस उत्पाद की बिक्री कर सकते हैं कि क्या वह बोन चाइना, पोर्सिलेन अथवा स्टोन है।

xxi. आयात की कीमत स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि पोर्सिलेन वेयर और सेरामिक वेयर के आयातों के बीच कीमत में अंतर बहुत अधिक अलग नहीं है। उसी प्रकार से प्रचलित समझ की तुलना में, स्टोन वेयर के आयात की कीमत पोर्सिलेन के आयात की कीमत से बिल्कुल तुलनीय नहीं है। वास्तव में, पोर्सिलेन वेयर और स्टोन वेयर का आयात बोन चाइना के आयात से बहुत अधिक कीमत पर होता है।

xxii. बोन चाइना अथवा पोर्सिलेन वेयर अथवा स्टोन वेयर के उत्पादन की लागत में बहुत अधिक अंतर नहीं है। वास्तव में, बोन चाइना के कारण लागत उत्पादन की कुल लागत के मामले में इतना कम हो जाती है कि विभिन्न प्रकारों के उत्पादन की लागत में परिणामी अंतर बहुत कम होता है।

xxiii. विभिन्न सेरामिक उत्पादों के आकारों, स्टाइल और बनावट में केवल अंतर का यह मतलब नहीं होता है कि इन उत्पादों में अलग-अलग तकनीकी लक्षण हैं। इस कारण से विचाराधीन उत्पाद को स्टाइल और आकारों के आधार पर अलग-अलग नहीं माना जाना चाहिए, सभी उत्पादों का अंतिम उपयोग वही होता है।

xxiv. संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण विभिन्न सीमा शुल्क उप शीर्षक जैसे 6911 10, 6911 90, 6912 00 आदि के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 69 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से प्रस्तावित जांच के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

xxv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और भारत में आयात किया जा रहा विचाराधीन उत्पाद एकसमान है तथा घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आवेदक के उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है और ये दोनों भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

xxvi. आवेदकों का यह दावा कि उनकी गुणवत्ता काफी अच्छी है, का पुरजोर खंडन किया गया है। प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग सर्वोत्तम मशीनों से युक्त है अर्थात् रोलर हेड्स, आटो कप प्लांट और अत्याधुनिक, ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल किलन से सुसज्जित है। किलन फर्नीचर, सेगगर, कच्ची सामग्री, चाइना क्ले आदि की सर्वोच्च गुणवत्ता तत्काल उपलब्ध है। वास्तव में भारत में उत्पादित किलन फर्नीचर और कच्ची सामग्री गुणवत्ता में इतनी अच्छी है कि उसका निर्यात विभिन्न देशों को किया जाता है। गुणवत्ता में अंतर किसी उत्पाद को बाहर रखने का पर्याप्त औचित्य नहीं हो सकता है जैसा डीएसएम आईडेमिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माना है और माननीय सेसटेट द्वारा उसका समर्थन किया गया है।

xxvii. विचाराधीन उत्पाद का दायरा व्यापक नहीं है बल्कि ओपेल ग्लासवेयर, मेलामाइन उत्पादों, सेरामिक इंसुलेटर्स जैसी अन्य जांचों के समान है। इसके अलावा, यूरोपीय यूनियन, जिसने समान उत्पाद में जांच की, ने उसी तरीके से विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित किया।

xxviii. विश्व व्यापार संगठन के निर्णय के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित समझे गए तरीके से विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित कर सकते हैं।

xxix. यदि आयातित वस्तु बेहतर रंग और डिजाइन की हैं और अधिक नवोन्मेषी हैं तो उसकी कीमतें घरेलू उत्पादकों से बेहतर होनी चाहिए परंतु वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।

xxx. घरेलू उत्पादों को अस्वीकार करने संबंधी आरोप बिल्कुल निराधार हैं। वालमार्ट अब भी घरेलू उत्पादकों से सेरामिक टेबलवेयर लेता है।

xxxi. घरेलू उद्योग स्टूडियो पॉटरी का विनिर्माण कर रहा है और फ्यूचर ग्रुप (बिग बाजार), लाइफस्टाइल, गुड अर्थ, शापर्स स्टाप आदि जैसी अनेक भारतीय रिटेल श्रृंखलाओं को उनकी आपूर्ति कर रहा है।

xxxii. प्रारंभिक अधिकरण पत्र में किचन वेयर के संदर्भ का अभाव केवल असावधानी से की गई टंकण संबंधी त्रुटि है। टेबल वेयर और किचन वेयर शब्द का उपयोग इस व्यापार में दैनिक क्रियाकलाप में एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है। यह

महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ताओं के उद्देश्य और आंकड़ों तथा सूचना, जिसका उपयोग याचिका को संग्रह करने में किया गया है, पर नजर डाली जाए।

xxxiii. जहां तक जांच प्रारंभ करने के लिए अधिकरण पत्र की आवश्यकता का प्रश्न है, अधिकरण पत्र आवेदन के प्रपत्र का हिस्सा भी नहीं है और न ही प्रपत्र द्वारा कोई अधिदेश दिया गया है। इसमें दी गई सभी सूचना के सही होने और पूरा होने की आवश्यकता है और घरेलू उद्योग ने बहुत अच्छे तरीके से आवेदन के प्रपत्र में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के संबंध में सभी सूचना प्रदान की।

xxxiv. याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना स्पष्ट रूप से उनके उद्देश्य को सिद्ध करती है और उन उत्पाद को भी सिद्ध करती है जिनकी मांग वे पाटनरोधी शुल्क के लिए कर रहे थे। आयातों के संबंध में याचिका में निहित सूचना, पाटन का साक्ष्य, क्षति और लागत की सूचना का साक्ष्य टेबल वेयर और किचन वेयर दोनों के संबंध में है। अधिकरण पत्र का उद्देश्य केवल पाटनरोधी शुल्क के लिए अनुरोध व्यक्त करना है। यह त्रुटि बाद के चरण में विधिवत ठीक कर ली गई थी और सभी याचिकाकर्ताओं ने सही अधिकरण पत्र प्रस्तुत किया।

xxxv. अधिकरण पत्र जांच शुरू करने का कोई आधार नहीं है। अंततः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति उत्पन्न करने वाले पाटन के होने की पर्याप्त प्रथम दृष्टया जांच के बाद अन्वेषण शुरू किया। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसे बाद के चरण में उठाई गई आपत्ति यह दर्शाती है कि उनका उद्देश्य केवल विलंब करना है तथा वर्तमान जांच को पूरा होने में बाधा उत्पन्न करना है।

xxxvi. याचिकाकर्ताओं ने आयातों की पूर्णतः (स्रोत – डीजीसीआईएंडएस) का विश्लेषण किया है और इसके आंकलन के आधार पर आयातों की पहचान विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद के रूप में की गई है। आयातकों के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा की गई विशिष्ट टिप्पणी पर, इन आंकड़ों को पुनः देखा गया है और जहां भी आवश्यक हुआ, इसमें सुधार किया गया है। हालांकि, यह अंतर इतना मामूली है कि उससे आयात की मात्रा, आयात की कीमत, कीमत में कटौती, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

6. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है:-

- i. आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति उत्पाद के बीच भारी गुणात्मक अंतर हैं। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए पीयूसी की गुणवत्तास्तरीय नहीं है।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद बिल्कुल मूलभूत हैं जबकि आयातित उत्पाद सभी मशीन निर्मित हैं और उनमें काफी अच्छी फिनिशिंग है। घरेलू आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु को अनेक बार अस्वीकार किया गया है और घरेलू उद्योग की पैकिंग काफी घटिया है।
- iii. घरेलू आपूर्तिकर्ता एक ट्रक से कम वस्तु की आपूर्ति नहीं करते हैं जिससे मालसूची में वृद्धि होती है और वाल-मार्ट के विहितमानकों से अधिक संभलाई के दिन बढ़ जाते हैं।

iv. चीन से वस्तुओं का आयात करने के कारण निम्नलिखित हैं:-

- घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं
- घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के पास उचित मशीनरी उपलब्ध नहीं है।
- वस्तुओं की गुणवत्ता कोर्डराइट, सैगर, सेटर और नाइट्राइट बांडेड सिलिकान कार्बाइड किलन फर्नीचर का उपलब्ध नहीं होना।
- प्राकृतिक गैस जैसे सस्ते ईंधन की अनुपलब्धता।

v. प्राधिकारी को उत्पाद के कार्य क्षेत्र पर एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। विचाराधीन उत्पाद बहुत व्यापक है और इसमें अनेक प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। लेन-देन वार आयात आंकड़ों के अनुसार सेनिटरी वेयर और टॉयलेट शीट को विचाराधीन उत्पाद के रूप में माना गया था।

vi. स्पाइस मिल्स और सेरामिक ग्राइंडिंग पाटर्स को उत्पाद के कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इन मिलों का उपयोग कप और प्लेट जैसे मानक टेबल वेयर के लिए नहीं किया जाता है। घरेलू आपूर्तिकर्ता “स्टूडियो पोर्ट्री” प्रदान करने में सक्षम नहीं है और इस कारण से इसे उत्पाद के कार्य क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।



vii. हीट प्रेस प्रिंटिंग ट्रांसफर के लिए सब्लिमेशन मग, कोट किया हुआ कप ब्लैंक (इमेज कप) को वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र से बाहर किया जाना उचित है क्योंकि इसमें रासायनिक कोटिंग के साथ लेयर बना हुआ है और इसे तैयार उत्पाद के रूप में अर्हक होने के पूर्व आगे प्रसाधित किया जाता है। यह एक गहन ग्राहक अनुकूल प्रक्रिया के बाद ही तैयार उत्पाद बन पाता है। इसका उपयोग अधिकांशतः नियमित किचन वेयर की मद की तुलना में उपहार के रूप में किया जाता है। “इमेज कप” का निर्यात मूल्य चीन के कुल निर्यात मूल्य का एक तिहाई होता है, भारत में प्रसंस्करण के द्वारा वास्तविक मूल्य प्राप्त किया जाता है। इस कारण से, पाटनरोधी शुल्क का इस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

viii. कुक वेयर को उत्पाद के कार्य क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि याचिका के प्रारंभिक जांच परिणाम में कहीं भी कुक वेयर को शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू उद्योग ने आयात संबंधी आंकड़ों में गैर विचाराधीन उत्पाद के रूप में सेरामिक कुक वेयर को चिन्हित किया है।

ix. कुछ सेरामिक कुक वेयर, जो फायर क्ले के बने होते हैं, को भी विचाराधीन उत्पाद की सूची से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि कच्चा माल अलग-अलग होता है, उत्पाद की विशेषताएं भी अलग-अलग होती हैं और भारत में फायर क्ले का कोई निर्माण नहीं किया जाता है।

x. उपयोग किए गए कच्चे माल, उत्पाद की विशेषताएं और फायर क्ले उत्पादों का अंतिम उपयोग अलग-अलग होता है। भारत में समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्थापन योग्य मद का कोई निर्माण नहीं होता है। घरेलू उद्योग का दावा है कि ये फायर क्ले उत्पादों का विनिर्माण कर सकते हैं, खोखला है क्योंकि उनकी पहुँच फायर क्ले कुक वेयर का निर्माण करने के लिए अपेक्षित कच्चे माल तक नहीं है क्योंकि इस उत्पाद का निर्माण करने के लिए अपेक्षित क्ले भारत में उपलब्ध ही नहीं है। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा दर्शाए गए नमूने एक टेराकोटा कुक वेयर उत्पाद था और न कि एक फायर क्ले उत्पाद। वास्तव में फायर क्ले और टेरा कोटा उत्पाद, दोनों उत्पाद के कार्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में फायर क्ले कुक वेयर का निर्माण नहीं किया है। घरेलू उद्योग द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उन्हें इसका निर्माण करने के लिए दस दिनों का समय दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने विगत में फायर क्ले कुक वेयर का उत्पादन कभी नहीं किया है और न ही जांच की अवधि के दौरान इसका उत्पादन किया है। याचिका में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि सेरामिक कुक वेयर के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और इसका उल्लेख विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही नहीं किया गया है।

xi. पोर्सिलेन को विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी विनिर्माता पोर्सिलेन का उत्पादन नहीं करता है। एक मैसर्स अंबरटो सेरामिक्स इंटरनेशनल प्रा. लि. ने यह उल्लेख किया है कि वे पोर्सिलेन का निर्माण करते हैं परंतु वे न तो आवेदक हैं और न ही वर्तमान याचिका के समर्थक हैं।

xii. घरेलू उद्योग प्रमुख रूप से बोन चाइना बनाते हैं और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित पोर्सिलेन की मात्रा बहुत कम है। दूसरी ओर आयात प्रमुख रूप से पोर्सिलेन के लिए किया जा रहा है।

xiii. बोन चाइना, स्टोन अथवा पोर्सिलेन को छोड़कर किसी अन्य संघटक से बनी संबद्ध वस्तु को स्वतः विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए जिसका केवल वह प्रमुख संघटक बोल क्ले है, कैल्शियम फॉस्फेट, क्वार्ट्ज, काओलाइन अथवा मिश्रण को विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।

xiv. विचाराधीन उत्पाद का कार्य क्षेत्र आवेदकों द्वारा जारी किए गए विशिष्ट अधिकरण से आगे तक बढ़ाया गया है क्योंकि आवेदक उत्पादकों द्वारा जारी किया गया अधिकरण केवल “सेरामिक टेबल वेयर” और न कि “किचन वेयर” के लिए जांच प्रारंभ करने की मांग के लिए है।

xv. यह जांच उचित अधिकरण पत्र को जारी किए बिना शुरू की गई थी। उत्पाद का कार्य क्षेत्र टेबल वेयर से टेबल वेयर और किचन वेयर तक बढ़ाया गया था और यह आवेदकों द्वारा जारी किए गए कुछ अधिकरण की परिधि से बाहर था।

xvi. अनेक अन्य उत्पादकों ने उसी प्रकार का पत्र प्रस्तुत किया और टेबल वेयर और न कि किचन वेयर की जांच शुरू करने का समर्थन किया।

xvii. यह जांच प्रारंभन उचित नहीं था, यद्यपि यह केवल टेबल वेयर के लिए थी क्योंकि टेबल वेयर के लिए अधिकरण दिया गया था और आंकड़े टेबल वेयर और किचन वेयर दोनों के लिए दिए गए थे।

xviii. परामर्शदाता टेबल वेयर और किचन वेयर, दोनों के लिए नियम 5 के अंतर्गत याचिका दायर कर सकते थे जब अधिकरण केवल टेबल वेयर से संबंधित था। मिस. निब्रो लि. बनाम नेशनल इंश्योरेंस कारपोरेशन लि.।

xix. याचिकाकर्ता का यह दावा कि उन्होंने प्रारंभिक जांच परिणाम के जारी होने के बाद एक संशोधित अधिकरण पत्र

दायर किया है, इस समस्या को दूर नहीं कर सकता है। कानून इस याचिका के दायर किए जाने के बाद अधिकरण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस याचिका को दायर कर दिया गया है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'चाकू और प्रसाधन मदों को छोड़कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर' (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु या पीयूसी भी कहा गया है) है।
8. यह नोट किया जाता है कि बोन चाइना, स्टोनवेयर और पोर्सलेन-वेयर सभी सेरामिक उत्पाद हैं और इसलिए विचाराधीन उत्पाद में बोन चाइना, स्टोन और पोर्सलेन के किचन वेयर और टेबलवेयर शामिल हैं। सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर उत्पाद का प्रयोग खाना खाने, पानी पीने और खाना और पेयों को परोसने और घरों और होटलों में सजावट के लिए भी किया जाता है।
9. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध लागत में भारी अंतर वाले विभिन्न विनिर्देशों में उत्पादित नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे चम्मच, कटोरी, प्लेट आदि को कैल्शियम, क्वार्टज, फेल्सपास और चाइना क्ले के मिश्रण से उत्पादित किया जाता है। विभिन्न प्रकारों के उत्पादन का अर्थ केवल इस मिश्रण को वांछित आकार देना है। इसलिए इन सभी मदों को एक व्यापक शीर्षक 'सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर उत्पाद' में वर्गीकृत करना उचित समझा गया है। 'सभी प्रकार के ओपेल ग्लासवेयर' और मेलामाइन टेबलवेयर और किचनवेयर उत्पादों नामक उत्पाद के लिए इसी प्रकार के मामले रहे हैं।
10. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ उत्पादों को शामिल किए जाने और मात्रा का निर्धारण केवल आयात के मूल्य का प्रतिवाद किया है। यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों को अपनाया है और इसका विश्लेषण किया है। यह नोट किया जाता है कि चीन के उत्पादकों ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है। यदि चीन के उत्पादक ने सहयोग किया होता तब वे भारत में किए गए निर्यात के संबंध में अधिक सटीक सूचना देते। चीन की सरकार अथवा चीन का एसोसिएशन अथवा आयातक ने भी भारत में इस उत्पाद की कुल मात्रा और आयात की कीमत के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। उनके सहयोग के अभाव में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े एक मात्र उपलब्ध सूचना हैं और उसको इस प्रयोजन से अपनाया गया है।
11. सब्लिमेशन मग, इमेज कप (हीट प्रेस प्रिंटिंग ट्रांसफर के लिए कोट किया हुआ कप ब्लैंक) के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वह टेबल वेयर और किचन वेयर का हिस्सा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने विशिष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि वे इन उत्पादों के प्रकारों का उत्पादन कर रहे हैं और उसकी बिक्री कर रहे हैं तथा उसका सत्यापन याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा मौके पर सत्यापन करते हुए किया गया था। इस कारण से, विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र से सब्लिमेशन/इमेज कप को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।
12. स्टूडियो पोर्ट्री के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है और उन्होंने उसकी आपूर्ति के लिए साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। जहां तक कुक वेयर का प्रश्न है, कुक वेयर शब्द का उपयोग व्यावहारिक बातचीत में टेबल वेयर अथवा किचन वेयर के स्थान पर परस्पर किया जा सकता है। चूंकि, आयातकों अथवा व्यापारियों द्वारा कुक वेयर अथवा सर्व वेयर अथवा किचन वेयर अथवा टेबल वेयर के रूप में इस उत्पाद का वर्णन करने में कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं अपनाई गई है। इस कारण से, प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र से स्टूडियो पोर्ट्री अथवा कुक वेयर को बाहर करने का कोई कारण नहीं है।
13. कुछ उत्पादों को बाहर करने की मांग करते समय, हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है कि किस प्रकार से ये उत्पाद सेरामिक के टेबल वेयर अथवा किचन वेयर बन जाते हैं। चूंकि चीन के उत्पादकों अथवा निर्यातकों ने प्राधिकारी को कोई सहयोग नहीं किया है। अतः कोई विशिष्ट तकनीकी सामग्री इन उत्पादों को अलग-अलग करने के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार के अंतर के लिए वस्तुपरक वैज्ञानिक आंकड़ों के अभाव में, प्राधिकारी आयातकों की इस मांग से संतुष्ट नहीं है और इस कारण से बाहर करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है।
14. हितबद्ध पक्षकारों ने बिना कोई मात्रा योग्य अथवा सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान किए बिना यह प्रतिवाद किया है कि चीन और घरेलू उद्योग के उत्पाद की गुणवत्ता में भारी अंतर है और घरेलू उद्योग के उत्पाद की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि कोई मात्रा बताने योग्य अथवा सत्यापन योग्य दावा नहीं किया जाता है तब उसे स्थापित नहीं किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अथवा बेची गई वस्तु आयात किए गए उत्पाद की वस्तु के समान नहीं है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि गुणवत्ता के मामले पर प्राधिकारी द्वारा तथा विगत में सेसटेट द्वारा विचार किया गया है और यह माना गया है कि जब तक यह सिद्ध नहीं किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए और आपूर्ति किए गए उत्पाद आयात किए गए उत्पाद की एक समान वस्तु है, एक संगत विचार नहीं हो सकता है। इन नियमों के तहत, घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित है कि वह आयात किए गए उत्पाद के समान वस्तु की पेशकश करे। यह भी नोट

किया जाता है कि घरेलू उद्योग का आरोप उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है और सामान्य मूल्य के अनुमान पर विचार करते हुए, इन वस्तुओं को उस कीमत पर बेची गई यह जो सामान्य मूल्य से कम है और आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी हद तक कटौती हो गई थी। यदि यह उत्पाद अपेक्षाकृत उच्च कोटि का है, तब आयात उस कीमत पर नहीं किए जाने की आवश्यकता है जो घरेलू उद्योग की कीमतों से कम हो और इससे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होने की जरूरत नहीं है।

15. इस प्रतिवाद के संबंध में कि चीन का उद्योग ट्रक लोड से कम पर वस्तु की बिक्री नहीं करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वहां पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है और साथ ही घरेलू उद्योग को इससे कोई परिणामी क्षति नहीं होती है। वास्तव में चीन के सामान को कंटेनर लोड में भेजा जाता है। एक कंटेनर लोड मैटेरियल एक ट्रक लोड मैटेरियल की तुलना में बहुत अधिक होता है। यदि आयात पार्ट कंटेनर लोड में किया जा रहा हो तब उपभोक्ता घरेलू उद्योग से भी पार्ट ट्रक लोड में खरीद सकते थे। यह भी नोट किया जाता है कि यदि वस्तु का आयात चीन से कंटेनर लोड में किया जाता है तब परिणामी माल भंडार बहुत अधिक होगा। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति उत्पन्न करने वाले चीन के उत्पादकों द्वारा पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

16. प्राधिकारी ने सीजीसीआरआई द्वारा दिए गए पत्र पर भरोसा किया है और संगठित क्षेत्र में संबद्ध वस्तुओं के विभिन्न उत्पादकों की पहचान की है और असंगठित क्षेत्र में अनेक उत्पादकों की भी पहचान की है। अलग-अलग कंपनियों के उत्पादन से संबंधित आंकड़े यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियों को छोड़कर, सभी अन्य घरेलू उत्पादकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन के अनुपात में बहुत अधिक कम है। इसके अलावा, अन्य किसी भी भारतीय उत्पादक ने क्षति के आंकड़ों से संगत सूचना प्रदान नहीं की है बल्कि समर्थन पत्र दिया है। इस उत्पाद का कोई अन्य घरेलू उत्पादक ने इस आवेदन का विरोध भी नहीं किया है। मामले के तथ्य और स्थितियों को देखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि भारतीय उत्पादन में 31 प्रतिशत हिस्सा भारत में कुल उत्पादन के प्रमुख अनुपात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

17. इस प्रतिवाद के संबंध में कि यह याचिका केवल टेबल वेयर के लिए है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस आवेदन के साथ दिए गए पत्रों में टंकण संबंधी त्रुटि के बावजूद, यह याचिका अपने संगत भाग में स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद के निर्धारित कार्य क्षेत्र को सेरामिक टेबल वेयर अथवा किचन वेयर के रूप में उल्लेख करता है। इसके अलावा, इस जांच ने यह दर्शाया है कि भारत में इस उत्पाद के आयात, भारतीय उत्पादन, पाटन मार्जिन का आंकलन, क्षति संबंधी सूचना, इस याचिका में लागत संबंधी सूचना जैसी सभी संगत सूचना सेरामिक टेबल वेयर अथवा किचन वेयर से संबंधित थी। इस प्रकार से, केवल इस कारण से क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का अनुरोध करते हुए याचिका दायर करने वाली कंपनियों से पत्रों में केवल टेबल वेयर का उल्लेख है, यह प्रतिवाद नहीं किया जा सकता है कि यह याचिका केवल टेबल वेयर के लिए है और इसमें किचन वेयर शामिल नहीं था। खासकर यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग ने किचन वेयर की खाली मात्रा का उत्पादन किया है और उसकी आपूर्ति की है, उसे घरेलू उद्योग के विभिन्न वित्तीय और क्षति संबंधी आंकड़ों में शामिल किया गया है और उसका सत्यापन भौतिक सत्यापन के समय किया गया है। याचिकाकर्ता चार कंपनियों के परिसरों में भौतिक सत्यापन से यह दृष्टिगत हुआ है कि ये कंपनियां किचन वेयर का भी उत्पादन कर रही हैं।

18. माप की सही इकाई के संबंध में, डीजीसीआईएंडएस से आयात संबंधी आंकड़ों में प्रयुक्त एक मात्र सबसे बड़ी इकाई वजन है। सभी विश्लेषण वजन के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा, यह देखा गया है कि इस उत्पाद की लागत का 60 प्रतिशत से अधिक कच्चा माल और उपयोगिता पर हुआ है। कच्चा माल और उपयोगिताओं की लागत इस उत्पाद के वजन के प्रत्यक्ष अनुपात में है और इस कारण से उत्पादन की लागत इस उत्पाद के वजन के बिल्कुल अनुरूप है। इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना उचित है कि यूरोपीय आयोग ने पूर्व में चीन के विरुद्ध एक जांच की थी, उस जांच परिणाम के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है कि इस उत्पाद का कार्य क्षेत्र वही था जो वर्तमान जांच में था और माप की गई इकाई भी वजन के संबंध में थी। संबद्ध वस्तुओं के लिए संगत एचएस कोड में सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शुल्क के संग्रह के लिए इकाई भी वजन के मामले में है। इस कारण से प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान जांच के लिए माप की सबसे अधिक उपयुक्त इकाई वजन है।

19. संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 69 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसका आयात एचएस कोडों 6911 और 6912 के अधीन हो रहा है। तथापि, एचएस कोड केवल सांकेतिक है और उत्पाद का वर्णन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ निर्धारक कारक है।

20. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'चाकुओं और प्रसाधन मदों को छोड़कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर' है। बोन चाइना, स्टोन वेयर और पोर्सिलेन वेयर सभी सेरामिक उत्पाद होते हैं और इस कारण से इन्हें विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया है।

**समान वस्तु**

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में सामान्य मूल्य को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

22. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इन तर्कों कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद और भारत में आयातित उत्पाद की गुणवत्ता, डिजाइन अलग-अलग होने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच गुणवत्ता संबंधी कथित अंतर दर्शाने के लिए कोई तथ्यपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता में अंतर तब तक पहचाना नहीं जा सकता है जब तक अंतर के तथ्य न बताये जाएं और उनका प्रभाव न दर्शाया जाए। प्राधिकारी 2000 में सूचित ‘डीएसएम आईडेमिक्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी’ (119) ई.एल.टी. 308 के मामले में सेस्टेट के निर्णय को भी नोट करते हैं जिसमें न्यायाधिकरण ने निम्नानुसार माना था।

‘चूंकि अपीलीय काउंसेल की दलील संतोषजनक नहीं है उन्होंने विनिर्माण की प्रक्रिया के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य/तकनीकी साहित्य प्रस्तुत नहीं किया जो दर्शाता हो कि घरेलू विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद भारत में निर्यातित उत्पाद से भिन्न है.... गुणवत्ता में अंतर किसी उत्पाद को भिन्न नहीं बनाता और निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह समुक्ति सही है कि यह तथ्य कि गुणवत्ता अलग-अलग है, का यह अर्थ नहीं है कि आयातित और घरेलू उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं।’

23. रिकार्ड में सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और आयातित संबद्ध उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

24. इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

**घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति****घरेलू उद्योग के विचार**

25. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. यह याचिका भारत में पीयूसी के घरेलू उत्पादकों की ओर से ऑल इंडिया पोटर्री मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) और इंडियन सेरामिक सोसाइटी (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। कुछ भारतीय उत्पादकों अर्थात् क्लेक्राफ्ट(आई) प्राईवेट लिमिटेड, भारत पोटर्रीज लिमिटेड, सेरामिक टेबलवेयर लिमिटेड, और यूपी सेरामिक्स एंड पोटर्रीज प्राईवेट लिमिटेड (जिन्हें याचिकाकर्ता/आवेदक कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित चाकुओं और प्रसाधन मदों को छोड़कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए जांच हेतु लागत से संबंधित आवश्यक विस्तृत आंकड़े दिए हैं।

ii. याचिकाकर्ता के अलावा कुछ अन्य भारतीय उत्पादकों ने याचिका का समर्थन किया है और समर्थन के पत्र यशवी एंटरप्राइजेज, अनिल फाइन सेरामिक, सम्राट सेरामिक्स, रघुवीर (इंडिया) लिमिटेड, मारवेल सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड, शी सेल सेरामिक्स (इंडिया) प्रा.लिमिटेड, मुद्रिका सेरामिक्स (आई) लिमिटेड, शान टेबलवेयर प्राईवेट लिमिटेड, फेदर टच सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड, ओसिस सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड और टाटा सेरामिक्स लिमिटेड जैसे इन उत्पादकों द्वारा विधिवत दायर किए गए थे।

iii. सभी याचिकाकर्ता कंपनियों ने अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई है। याचिका में याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा किए गए आयात, यदि कोई हो, के संबंध में स्पष्ट रूप से सूचना निहित है। आवेदन में दिये गये उक्त कथन का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया था। यह नहीं पाया गया है कि इस आधार पर याचिका दायर करने वाली कंपनियों द्वारा दिया गया कथन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था।

iv. चार याचिकाकर्ता कंपनियों का हिस्सा 30 प्रतिशत से अधिक है। केवल यही याचिका दायर करने के लिए नियम 5(3) के अनुसार पर्याप्त नहीं है। याचिकाकर्ता का अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा समर्थन किया गया है। समर्थकों के साथ

भारतीय उत्पादकों का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक होता है। प्राधिकारी ने, जांच प्रारंभन अधिसूचना, उसका उल्लेख किया है।

v. आधार के उद्देश्य से नियमावली के अंतर्गत अपेक्षा – (क) इस याचिका को पात्र भारतीय उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, (ख) इस याचिका को उन घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए जिनका सामूहिक उत्पादन या तो आवेदन के पक्ष में अथवा उसके विरोध में, जैसा भी मामला हो, प्रकट करते हुए घरेलू उद्योग के उस भाग से उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत से अधिक होता है और (ग) याचिकाकर्ताओं का उत्पादन "एक प्रमुख अनुपात" होना चाहिए। स्पष्ट रूप से, कहीं भी नियम यह उल्लेख नहीं करता है कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन पात्र भारतीय उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस याचिका को 25 प्रतिशत से अधिक पात्र भारतीय उत्पादन का समर्थन 25 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करने वाले याचिकाकर्ताओं से स्वयं बहुत अलग है। इस प्रकार से, यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं के लिए न्यूनतम सीमा 25 प्रतिशत है, त्रुटिपूर्ण है। सीमा याचिका का समर्थन देने के संदर्भ में और न कि याचिकाकर्ता के संबंध में है। इस उद्योग में भारी संख्या में असंगठित उद्योग हैं और वे केवल वही उद्योग हैं जिन पर पाटित आयातों का बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत में लगभग 200 कंपनियां लघु स्तर पर विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रही हैं और उनका कार्यचालन संगठित क्षेत्र की तुलना में छोटा है।

vi. लघु स्तर के उद्योगों के पास वर्तमान जांच में सूचना देने अथवा विरोध करने के लिए संसाधन नहीं हैं। विगत में सल्फर ब्लैक में प्राधिकारी ने यह किया किया था कि घरेलू उत्पादकों का कुल मिलाकर बाजार हिस्सा क्षति के निर्धारण में समान रूप से महत्वपूर्ण है।

vii. प्राधिकारी को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए जो संसाधनों की कमी के कारण आपके हित की रक्षा नहीं कर सकते हैं।

viii. लघु स्तर के उत्पादक पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन दायर करने हेतु अपेक्षित सूचना नहीं रखते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने भी विशेष महत्व दिया है जिसे असंगठित क्षेत्र को दिया जाना चाहिए। डीजीएडी में संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए कोई अलग-अलग आवश्यकता नहीं है और कि वे उन्हें असंगत सूचना देने से रोक सकते थे।

ix. ऐसा मामला नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन, भारत में केवल लघु स्तर पर ही है। चीन में भी, 400 से अधिक कंपनियों ने नमूने पर प्रश्नावली के उत्तर में यूरोपीय आयोग को उत्तर दिया।

x. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आंकलित उत्पादन उससे बहुत अधिक भिन्न है जो इसे वर्तमान उद्देश्यों से होना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों की मात्रा मान्यता है कि याचिकाकर्ता के वास्तविक उत्पादन आंकड़े बहुत अधिक ज्यादा हो सकते हैं।

xi. याचिकाकर्ता ने सुरक्षित रहने के उद्देश्य से एक संकुचित दृष्टिकोण तथा अन्य उत्पादकों के अधिक अनुमानित उत्पादन को अपनाया है कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन 25 प्रतिशत की सीमा पार कर जाए। वास्तविक तथ्य यह है कि असंगठित क्षेत्र का उत्पादन उससे काफी कम है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा आंकलित किया गया है।

xii. याचिकाकर्ताओं ने कोई आयात नहीं किया है और न ही संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा न ही भारत में आयातक से (या तो प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में) जुड़े हुए हैं।

xiii. समर्थकों ने चीन जीन गण से सेरामिक किचन वेयर और टेबल वेयर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को लगाने की याचिका का समर्थन किया है जो पाटनरोधी नियमों के अनुसार अपेक्षा को पूरा करता है। नियम 5(3) के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह समर्थन याचिका को है और न कि याचिकाकर्ता जो याचिका दायर कर रहे हैं, को समर्थन पत्रों से आसानी से देखा जा सकता है कि अन्य भारतीय उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए याचिका का समर्थन किया है। इस प्रकार से नियम 5(3) के अंतर्गत निर्धारित कानूनी अपेक्षा पूरी कर ली गई है।

xiv. सीएसआईआर से पत्र में उनके द्वारा दिए गए आंकलन के अनुसार, उत्पादन का कंपनी दर कंपनी ब्यौरा शामिल है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने में अपनी असमर्थता मानी कि भारतीय उत्पादन वास्तव में उससे अलग है जिसका दावा याचिकाकर्ताओं द्वारा पहली मौखिक सुनवाई के दौरान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने याचिकाकर्ता के दावे का खंडन करने के लिए कोई प्रतिकारी सूचना, जो भी हो, उपलब्ध नहीं कराई है तथा वे बिना किसी सहायक साक्ष्य के आरोप मात्र है जिस पर विचार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का दायित्व सूचना देने के अलावा कुछ नहीं है जो नियम 5 के अनुसार उचित रूप से उपलब्ध है।

xv. सीएसआईआर के पत्र का विरोध नहीं किया जा सकता है। सीएसआईआर का पत्र इस आवेदन में किए गए दावे की पुष्टि करने के लिए ही है। याचिकाकर्ता को उनके पास उचित रूप से उपलब्ध सूचना प्रदान करने की ही जिम्मेदारी है।

हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दावे का खंडन करने के लिए कोई प्रतिकारी सूचना, जो भी हो, उपलब्ध नहीं कराई है।

xvi. यह याचिका आवेदन के प्रपत्र के अनुसार दायर किया गया था जो नियम 5 के अनुरूप है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना उनके उद्देश्य और वह उत्पाद जिन पर वे पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग कर रहे थे, को सिद्ध करता है।

xvii. सीएसआईआर से पत्र में उनके द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार उत्पादन का कंपनी दर कंपनी वार ब्यौरा निहित है। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने में अपनी असमर्थता दर्शाई कि भारतीय उत्पादन उससे वास्तव में अलग है जिसका दावा याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है।

xviii. सभी याचिकाकर्ता कंपनियों ने अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई है। याचिका में स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता कंपनियों, यदि कोई हों, द्वारा आयातों के संबंध में घोषणा शामिल है। आवेदन में दिए गए उक्त कथन का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया था। यह नहीं पाया गया है कि इस आधार पर याचिका में दिया गया कथन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

26. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को सारांश में नीचे दिया गया है:

i. उत्पादकों, जिन्हें घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है, ने आवश्यक प्रमाणीकरण दायर नहीं किया है, जो पात्रता के निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए नियम 2(ख) की पूर्व शर्तों की जांच करने के लिए सभी अन्वेषणों में दायर किया जाना अपेक्षित है।

ii. प्रमुख अनुपात की जांच उस आवेदक उद्योग के संदर्भ में की जानी है जिसने अपने आंकड़े उपलब्ध कराए हैं तथा अपने दावे के समर्थन में सूचना दी है। वर्तमान मामले में प्रमुख अनुपात की जांच का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों के कुल उत्पादन को जोड़ने के बाद की जाती है। जब आवेदन प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम अपेक्षा 25 प्रतिशत है तब भारत में कुल उत्पादन का प्रमुख अनुपात के रूप में 31 प्रतिशत नहीं कहा जा सकता है।

iii. समर्थकों ने मैसर्स भारत पोर्ट्रीज प्रा. लि., मैसर्स सेरामिक टेबल वेयर प्रा. लि. एवं मैसर्स क्ले क्राफ्ट (इंडिया) प्रा. लि. का समर्थन किया है जबकि जांच प्रारंभन अधिसूचना के अनुसार वर्तमान याचिका ऑल इंडिया पोर्ट्री मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) और द इंडिया सेरामिक सोसायटी द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से तथा वह भी टेबल वेयर के लिए ही दायर की गई है।

iv. याचिकाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक सुनवाई में यह स्वीकार किया गया था कि उनके पास असंगठित क्षेत्र के लिए कोई आंकड़े नहीं हैं। इसलिए घरेलू उद्योग का वास्तविक उत्पादन आंकड़ा उससे काफी अधिक है जिसका प्रारंभिक जांच परिणाम में उल्लेख किया गया है। यदि ऐसा ही मामला है तब याचिकाकर्ता का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक भी नहीं है।

v. पाटनरोधी आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए दायर किया गया है। विभिन्न घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर किए गए समर्थन पत्रों पर इस कारण से विश्वास नहीं किया जा सकता है कि इन पत्रों का गहराई से अध्ययन करने पर यह देखा जा सकता है कि समर्थन पत्र उत्पादकों के विभिन्न समूहों द्वारा विभिन्न पाटनरोधी जांच में दायर किया गया है। उस आधार पर आवेदकों को घरेलू उद्योग नहीं कहा जा सकता है। जांच इस तथ्य के आधार पर समाप्त की जानी चाहिए कि इसे उद्योग से कोई स्पष्ट समर्थन नहीं मिला है।

vi. आवेदक सामूहिक रूप से घरेलू उत्पादकों का केवल 30 प्रतिशत ही होते हैं। इस कारण से वे घरेलू उद्योग के लिए पात्र नहीं हैं। यदि आवेदन का कुल उत्पादन भी 25 प्रतिशत से अधिक है, परंतु वह आवेदन के आधार के संबंध में और न कि घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करने के उद्देश्य से संगत है। प्राधिकारी सम्पूर्ण रूप में भारतीय उत्पादकों की प्रवृत्ति को समझने के लिए अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादकों को जोड़ सकते थे।

vii. संपूर्ण रूप में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन सीआईएसआर द्वारा दी गई सूचना के विपरीत 30,000 मी. टन से बहुत अधिक है। सीएसआईआर पूर्ण तस्वीर को नहीं दर्शाता है और उसे ही प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान स्वीकार किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन संबंधी आंकड़े प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं हैं।

viii. सुनवाई के दौरान, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह मान लिया गया था कि सीएसआईआर द्वारा दिए गए कारण भारतीय उत्पादन का आंकड़ा केवल एक अनुमानित आंकड़ा है और भारतीय उत्पादन का कोई सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से भारतीय उत्पादन के त्रुटिपूर्ण विश्लेषण पर गहरी आपत्ति की गई है।

ix. यदि घरेलू उद्योग के उत्पादन संबंधी ब्यौरे की जानकारी नहीं है तब इसका अर्थ यह होता है कि घरेलू उद्योग के रिकार्डों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और यह घरेलू उद्योग के उत्पादन की मात्रा बताने के लिए समुचित नहीं है। यह इस तथ्य पर घोर संदेह डालता है कि किस प्रकार से याचिका दायर करने वाली कंपनियों के अन्य आंकड़ों जैसे बिक्री, क्षमता, निर्यात, उत्पादन की लागत, एसजीएंडए खर्च, क्षति रहित कीमत आदि की गणना की गई है जब ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग के पास उपर्युक्त आंकड़ों को दर्शाने के लिए विश्वसनीय अथवा समुचित रिकार्ड नहीं है।

x. आवेदक – उत्पादक तथा समर्थकों के लिए उत्पादन आंकड़े रिकार्ड पर दस्तावेजी साक्ष्य का समर्थन नहीं करते हैं। इसके ठीक विपरीत, प्रारंभिक जांच निष्कर्ष में दर्ज किए गए अनुसार, आवेदक – उत्पादक एवं समर्थकों के उत्पादन संबंधी आंकड़े आवेदनों के अगोपनीय पाठ (एनसीवी) में आवेदक – उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना अलग-अलग है।

xi. एनसीवी आवेदन में संलग्न समर्थन पत्र वर्तमान आवेदन का समर्थन नहीं करते हैं। दावा किए गए समर्थन वर्तमान आवेदन को कोई स्पष्ट समर्थन नहीं देते हैं क्योंकि वर्तमान याचिका में सभी आवेदनों को "स्पष्ट समर्थन" नहीं दिया गया है। किसी भी अन्य घरेलू उत्पादकों ने जांच प्रारंभ के पूर्व वर्तमान याचिका का समर्थन नहीं किया है तथा इस कारण से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आधार संबंधी आवश्यकता पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के संबंध में पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए, आवेदक ने वर्तमान जांच में टेबल वेयर और किचन वेयर के संबंध में वर्तमान आवेदन के लिए समर्थन का दावा करने के लिए उन्हीं पत्रों/अधिकरण (टेबल वेयर के संबंध में पूर्व के आवेदन में दायर किया गया) संलग्न कर दिया है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

27. यह याचिका भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की ओर से ऑल इंडिया पोटरी मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएमपीए) और इंडियन सेरामिक सोसाइटी (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता/एसोसिएशन कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। कुछ भारतीय उत्पादकों अर्थात् (क) क्ले क्राफ्ट(आई) प्राईवेट लिमिटेड, (ख) सेरामिक टेबलवेयर प्राईवेट लिमिटेड, (ग) भारत पोटरीज लिमिटेड और (घ) मैसर्स यूपी सेरामिक्स एंड पोटरीज प्राईवेट लिमिटेड (जिन्हें याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) ने आवश्यक लागत और वित्तीय सूचना प्रदान की है। अनेक अन्य उत्पादकों अर्थात् यशवी एंटरप्राइजेज, अनिल फाइन सेरामिक, सम्राट सेरामिक्स, रघुवीर (इंडिया) लिमिटेड, मारवेल सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड, शी सेल सेरामिक्स (इंडिया) प्रा.लिमिटेड, मुद्रिका सेरामिक्स (आई) लिमिटेड, शान टेबलवेयर प्राईवेट लिमिटेड, फेदर टच सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड, ओसिस सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड और टाटा सेरामिक्स लिमिटेड ने याचिका का समर्थन किया है।

28. याचिकाकर्ता कंपनियों के वास्तविक आंकड़े और सीएसआईआर के अंतर्गत गठित, सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीजीसीआरआई) द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। सीएसआईआर के अंतर्गत गठित, सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीजीसीआरआई) ने संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र में इस उत्पाद के उत्पादकों के ब्यौरे का उल्लेख किया है। सूचना के किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत के न होने के कारण प्राधिकारी ने एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में सीएसआईआर के अंतर्गत गठित सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीजीसीआरआई) के आंकड़ों को स्वीकार करना उपयुक्त समझा और भारत में कुल उत्पादन को दर्शाने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत का उत्पादन करने के लिए सभी प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा उचित अवसर भी दिया गया था और इस संबंध में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

विवरण	मी. टन	भारतीय उत्पादन % में हिस्सा
	जांच की अवधि	जांच की अवधि
समग्र रूप में याचिकाकर्ता	8,652	31%
समग्र रूप में समर्थक	8,650	31%
समग्र रूप में याचिकाकर्ता + समर्थक	17,302	62%
अन्य	10,700	38%
भारतीय उत्पादन	28,002	100%

29. याचिकाकर्ता कंपनियों ने संबद्ध देश से न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का भी सत्यापन किया है।

30. असंगठित क्षेत्र के उत्पादन संबंधी आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि असंगठित क्षेत्र में अलग-अलग कंपनियों के उत्पादन के संबंध में सटीक सूचना के न होने को देखते हुए, याचिकाकर्ता को कानून के अंतर्गत राहत से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह नोट किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन बहुत है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन में भी, संगठित और असंगठित क्षेत्र में इस उत्पाद के उत्पादकों की बड़ी संख्या है। प्राधिकारी द्वारा पूर्व की जांचों में जहां जांच के अधीन उत्पाद संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों में अर्थात् एए बैट्री, लेड एसिड बैट्री, सिल्क फैब्रिक और सिल्क यार्न आदि का उत्पादन किया जा रहा है, यह उत्पादन उन जांचों में सूचना के उपलब्ध विश्वसनीय संगत स्रोत के अनुसार आंकलन के आधार पर निर्धारित की गई थी। इस कारण से, इसे नियमावली के नियम 2(ख) के संबंध में पात्र घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता को स्वीकार करने के लिए उपयुक्त माना गया है।

31. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि उसकी मात्रा उपयुक्त रूप से, समुचित रूप से तथा पर्याप्त रूप से बताई गई है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का विधिवत सत्यापन घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए रिकार्डों से बिक्री, क्षमता, निर्यात, लागत और खर्चों के संबंध में कर लिया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए वित्तीय एवं उत्पाद रिकार्ड इस प्रयोजन से अपनाए गए हैं जो विश्वसनीय हैं तथा संगत सूचना का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं।

32. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, याचिकाकर्ता कंपनियों के उत्पादन का समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन में 'प्रमुख हिस्सा' बनता है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

## **इ. गोपनीयता**

### **घरेलू उद्योग के विचार:**

33. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं

i. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के मानकों के अनुसार गोपनीयता का दावा किया है और वास्तव में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उनके अनुरोध पर उचित टिप्पणी करना मुश्किल हो गया है।

ii. प्राधिकारी को किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं प्रकट किया जा सकता है। सीएसआईआर ने सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है, प्राधिकारी ने सही ढंग से उक्त सूचना को प्रकट नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ दस्तावेजों के गोपनीय होने का दावा किया है और उसे घरेलू उद्योग को प्रकट नहीं किया गया है।

iii. बहुत सामान्य आरोप हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में लगाया गया है। हितबद्ध पक्षकार किसी एक उदाहरण को प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं जहां प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता की अनुमति नहीं दी गई है तथा याचिकाकर्ता ने उस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है। केवल उच्च व्यापार मालिकाना सूचना को गोपनीय रखा गया है।

### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

34. विभिन्न प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है:

i. आवेदकों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है और उन्होंने उत्पादन मात्रा, घरेलू बिक्री मात्रा, निर्यात बिक्री मात्रा, मालसूची की मात्रा, सूचीबद्ध रूप में सीओपी प्रति इकाई, बिक्री कीमत प्रति इकाई सूचीबद्ध, लाभ/(हानि) प्रति इकाई सूचीबद्ध, रोजगार, उत्पादकता, प्रतिशत में आरओसीई, प्रारूप IV-ख, लागत संबंधी सूचना और वित्तीय परिणामों के आरओसी अंश के संबंध में सूचना नहीं बताई है।

ii. ऐसी सूचना प्रदान नहीं करना पाटनरोधी नियमावली में दिए गए गोपनीयता संबंधी प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। काफी सूचना को कोई औचित्य बताए बिना गोपनीय रखा गया है।

iii. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सीएसआईआर पत्र जिसके आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आवेदकों के आधार की जांच की है, हितबद्ध पक्षकारों को बिना किसी विलंब के दिए जाएं। यदि सीएसआईआर पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के



अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए गोपनीय रूप में सीएसआईआर द्वारा प्रस्तुत किया गया है तब पत्र का अगोपनीय पाठ हैमिल्टन को दिया जाना चाहिए।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

35. प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावों की जांच की है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को अनुरोध करने पर सभी हितवद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

36. प्राधिकारी ने इस तथ्य को नोट किया कि आयातक को भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन के संबंध में सीएसआईआर के अंतर्गत गठित सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीजीसीआरआई) के उक्त पत्र पहले से ही प्राप्त है जिसे सुनवाई के दौरान उनके द्वारा यथा उल्लिखित एक आरटीआई आवेदन से प्राप्त हुआ। इसके अलावा, प्राधिकारी ने सभी हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीजीसीआरआई) को रखने का फैसला किया है।

37. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को जहां आवश्यक हो स्वीकार किया है और अन्य हितवद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निदेश दिया गया। प्राधिकारी ने विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों का एक सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध रखा। इस अनंतिम जांच परिणाम में विभिन्न चर्चाएं गोपनीयता के पहलू के संबंध में घरेलू उद्योग की अन्य दलीलों के संबंध में स्वतःस्पष्ट हैं।

### **च. विविध मुद्दे**

#### **घरेलू उद्योग के विचार:**

38. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- i. चीन के निर्यातकों ने जांच की शुरुआत के बाद अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद कोई सूचना प्रदान करके सहयोग नहीं किया है। किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- ii. चीन के उत्पादक/निर्यातक एसोसिएशन जो पाटनरोधी मामलों में उनके मामलों में पक्ष रखने के लिए निर्यातकों की मदद करते हैं, ने भी लागत और निर्यात से संबंधित विस्तृत सूचना प्रदान करके सहयोग नहीं किया है। चीन के एसोसिएशन को असहयोगी माना जाना चाहिए।
- iii. याचिकाकर्ताओं ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आकड़ों को अपनाया है, उन्हें याचिका की एनसीवी प्रति में भी प्रदान किया गया है। आयातों का एक बड़ा हिस्सा भार के रूप में है और अन्य इकाइयां जैसे संख्या/नग/सेट को आयात आकड़ों के समग्र कारगर विश्लेषण के लिए भार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा पीयूसी का कारखाना द्वार स्तर पर भार के रूप में सौदा किया गया है। इसलिए माप की इकाई के रूप में भार को अपनाया जाना उचित है और प्रतिवादी पक्ष ने कोई वैकल्पिक पद्धति बताए बिना उसपर आपत्ति जताई है।
- iv. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा विधि के अधीन विहित आवश्यक लागत/वित्तीय सूचना प्रदान की गई है। समर्थक जो पाटन के प्रभाव के कारण नुकसान उठा रहे हैं और उन्होंने याचिका का समर्थन किया है, के लिए लागत/वित्तीय आकड़ों को देना अपेक्षित नहीं है।
- v. चीन जनवादी गणराज्यसे निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आकड़ों के अनुसार बाजार आसूचना और मानक प्रथाओं के अनुसार निर्यात कीमत में आवश्यक समायोजनों के साथ निर्धारित किया गया है।
- vi. सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई वजन है। इस कारण से, यदि अब आयातों की सूचना माप की अलग-अलग इकाइयों में दी जा रही है तब इन आयातकों की ओर से माप की निर्धारित इकाई को छोड़कर अन्य इकाइयों में सूचना देना अनुचित है। केवल यह तथ्य कि इन वस्तुओं की बिक्री बाजार में समूहों में की जा रही है अथवा टुकड़ों में की जा रही है, इस प्रयोजन से अत्यधिक अपूर्ण है। चीन सीमा शुल्क में माप की इकाई की परिभाषा केवल वजन के रूप में दी गई है।
- vii. विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की प्रकृति को देखते हुए संदर्भ कीमत प्रभावी नहीं होगी।

viii. याचिकाकर्ताओं ने आयातों की पूर्णता का विश्लेषण किया है और इसके आंकलन के आधार पर विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद में आयातों की पहचान की है। हितबद्ध पक्षकारों के लिए यह विकल्प था कि वह याचिका के संबंध में टिप्पणी अथवा रिकार्ड में संगत सूचना, जिस पर प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम को रिकार्ड करते समय विचार किया जा सकता था, को सामने लाने के लिए जांच प्रारंभन के चरण में प्रस्तुत करना विकल्प था। हालांकि, प्राधिकारी उस पर उपयुक्त रूप से विचार कर सकते हैं और अंतिम जांच परिणाम में उसे दर्ज कर सकते हैं।

ix. यह समझना बहुत मुश्किल है कि इस प्रकार से अमेरिकी डॉलर/किलोग्राम में शुल्क अनुचित है, यदि शुल्क का यही रूप इलास्टोमेरिक यार्न में उपयुक्त था, जहां अलग-अलग तरह के उत्पादों की इतनी अलग-अलग कीमतें थीं।

x. शुल्क का अमेरिकी डॉलर/किलोग्राम रूप कई अन्य पाटनरोधी मामलों में उपयुक्त था, जहां अलग-अलग उत्पादों की अलग-अलग कीमतें थीं।

xi. चूंकि, वर्तमान उद्योग एक श्रम गहन उद्योग है, अतः इस उद्योग को सतत क्षति से काफी संख्या में परिवारों पर प्रभाव पड़ रहा है जो इन उद्योगों पर दैनिक आधार पर निर्भर करते हैं।

xii. प्राधिकारी के लिए उन लोगों के हितों की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है जो अपने आप संसाधनों के अभाव के कारण अपने हित की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हैं।

### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

39. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है:-

i. घरेलू उद्योग ने वर्तमान मामले की सूचना के बावजूद अपनी सूचना प्रदान नहीं की है इसलिए उसे पाटनरोधी नियम के नियम 6(8) के अधीन असहयोगी माना जाना चाहिए।

ii. समर्थकों का सूचना प्रदान नहीं करना दर्शाता है कि उन्होंने प्राधिकारी के समक्ष क्षति के केवल असाक्ष्यांकित दावे किए हैं।

iii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 12.1 के उल्लंघन में कार्रवाई की है क्योंकि वह जांच शुरूआत से पहले हितबद्ध पक्षकारों को यह सूचित नहीं कर पाये हैं कि प्राधिकारी संतुष्ट हैं और जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

iv. याचिकाकर्ता पाटन और क्षति निर्धारण पर भरोसा की गई सूचना के स्रोत को बताने में विफल रहे हैं।

v. डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े एक्सेल प्ररूप में हैं अपरिष्कृत और शोधित रूप में अपनायी गई पद्धति उपलब्ध नहीं कराई गई है।

vi. घरेलू उद्योग ने गलत ढंग से आयात संबंधी आंकड़ों को अलग-अलग किया है। संबद्ध देश के संबंध में उच्चतर कीमत की अधिकांश प्रविष्टियां, जिसे विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा होना चाहिए था, को आवेदक द्वारा "गैर-विचाराधीन उत्पाद" के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही ऐसी भी प्रविष्टियां हैं जिन्हें "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में चिन्हित किया गया है, परंतु विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा का भाग नहीं है। गैर संबद्ध देशों की तुलना में, आयात संबंधी आंकड़ों की गलत व्याख्या इस आशय से और भी अधिक गंभीर है कि गैर संबद्ध देशों के संबंध में कारणात्मक संबंध के एक बेहतर मामले को दर्शाने के लिए, जो अन्य प्रकार से मौजूद नहीं रहता, गैर संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से की गई है।

vii. यदि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.4 में दी गई शर्त को पूरा नहीं किया जाता है तब कोई भी जांच शुरू नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, उचित अधिकरण के अभाव में किसी जांच को प्रारंभ करना कानून के अधिकार से बाहर है और इसे जारी नहीं रखा जा सकता।

viii. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लगाए गए अनंतिम शुल्क बिना कानूनी अधिकार के हैं क्योंकि अनंतिम निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9ख(1)(ख)(iii) के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। प्राधिकारी ने इस बात के लिए कोई निर्धारण नहीं दिया है कि क्यों इस प्रारंभिक शुल्क को लगाया गया था। इस प्रकार का निर्धारण अनंतिम शुल्क के लगाए जाने से पूर्व एक शर्त है।

ix. बोन चाइना, पोर्सिलेन और स्टोन वेयर, किचन वेयर और टेबल वेयर आयातों के लिए संदर्भ कीमत की सिफारिश की गई है।

x. वर्तमान जांच तथा प्रारंभिक जांच परिणाम का प्रारंभ होना सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित नहीं था और इस कारण से यह कानून की दृष्टि से गलत है क्योंकि यह मान लिया गया था और इस पर चर्चा की गई थी कि सीआईएसआर द्वारा दिए गए उत्पादन संबंधी आंकड़े जांच की पूर्व तस्वीर को नहीं दर्शाते हैं और इस पर गलत तरीके से विचार किया गया है। प्राधिकारी ने मौखिक सुनवाई के दौरान भी इसकी पुष्टि की थी कि न तो भारत सरकार और न ही अन्य एसोसिएशन संबद्ध वस्तुओं के संबंध में सही आंकड़े रखते हैं।

xi. अमेरिकी डॉलर/किलोग्राम में शुल्क निरर्थक है। इन वस्तुओं की लागत, उपयोग, उपयोग दर, विनिर्माण प्रक्रिया तथा भौतिक एवं रासायनिक संरचना के मामले में अलग-अलग श्रेणी है। अमेरिकी डॉलर/किलोग्राम से शुल्क का इनवर्स प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उच्चतर अंतिम उत्पाद पर बहुत कम शुल्क लगेगा और निम्नतर अंतिम उत्पादों पर अनुचित ढंग से अपेक्षाकृत अधिक शुल्क लगेगा।

xii. प्राधिकारी जांच की अवधि के समय पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अंतरिम सूचना अर्थात् अनंतिम शुल्क लगाए जाने तथा दूसरा क्षति की अवधि के दौरान क्षति के लिए अपेक्षित दो शर्तों को पूरा करने में असफल रहे।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

40. विविध मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए विभिन्न अनुरोधों की जांच और निम्नानुसार समाधान किया गया है:-

i. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनंतिम शुल्क इस तथ्य के कारण लगाया गया कि घरेलू उद्योग बहुत अधिक निराशा में था और अप्रैल के महीने में चीन में कैंटन फेयर के द्वारा इसे और अधिक नुकसान होने जा रहा था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार से क्रेता भाग लेते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऑर्डर दिए जाते हैं, भारत में जुलाई-अक्तूबर अवधि के आसपास आपूर्ति पहुँचती है। इस प्रकार से, यदि अंतरिम उपायों पर विचार नहीं किया जाता, तब उद्योग को उत्पाद के लिए अगले मौसम का नुकसान हुआ होता।

ii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन में जांच की शुरुआत करने के लिए समस्त संगत सूचना शामिल थी। प्राधिकारी ने उचित जांच के बाद वर्तमान जांचको शुरू करने का निर्णय लिया और जांच की अवधि को अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016 तक संशोधित करने का निर्णय लिया था। संशोधित आवेदन जांच प्रारंभ करने के पश्चात मांगे गए थे और एनसीवी सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया था।

iii. प्राधिकारी ने निर्णय लिया कि पीयूसी को भार के रूप में व्यक्त करना उचित होगा क्योंकि आयात तथा कारखाना से डीलर, दोनों ओर सौदे भार के अनुसार किए जाते हैं। कच्ची सामग्री और सुविधाओं की लागत उत्पाद के भारत के सीधे अनुपात में हैं इसलिए उत्पादन लागत उत्पाद के भार के बिल्कुल अनुरूप है। डीजीसीआईएंडएस के अधिकांश आंकड़े भार के अनुसार उपलब्ध हैं और संख्या/सेटों/नग में उपलब्ध शेष आंकड़ों को भार में परिवर्तित किया गया है और समस्त विश्लेषण किग्रा. में किया गया है।

iv. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले पाटनरोधी आवेदनपत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया। इसके अलावा, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत को अधिसूचित करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में एक अधिसूचना प्रकाशित की।

v. इस तर्क के संबंध में कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने सूचना प्रदान नहीं की है या समर्थकों ने सीमित सूचना प्रदान की है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुसार क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर करना होता है। वर्तमान मामले में, एक बार यह निर्धारित होने पर कि याचिकाकर्ता कंपनियां घरेलू उद्योग हैं, पाटनरोधी नियमावली में ऐसी कोई विधिक अपेक्षा नहीं है कि अन्य भारतीय उत्पादकों की सूचना पर भरोसा किया जाए।

vi. आयातक का कानूनी परामर्शदाता, जो पाटनरोधी महानिदेशालय की प्रक्रियाओं से पूर्ण रूप से अवगत है, प्राधिकारी से किसी भी समय, यदि वे अपरिष्कृत आंकड़े चाहते थे, संपर्क कर सकते थे। प्राधिकारी उन्हें अपनी शर्तों के अनुसार डीजीसीआईएंडएस से इन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर पाते, जैसा कि याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि के लिए किया गया था। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डीजीसीआईएंडएस का लेन-देन वार आंकड़ा एनसीवी याचिका का भाग होने के कारण सार्वजनिक फाइल में था।

vii. विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों का विधिवत सत्यापन किया गया है जिसे उचित माना गया है। इसके अलावा, एनईपी तथा पहुँच मूल्य, जिसका उल्लेख बाद के पैराओं में किया गया है, के निर्धारण के लिए विभिन्न गणना सत्यापित सूचना के आधार पर इस निदेशालय में अपनाई गई पद्धति और मानक प्रथाओं के अनुसार की गई है।

**छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**

नियम के अंतर्गत "सामान्य मूल्य" -

41. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:-

"व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

**घरेलू उद्योग के विचार:**

42. याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

i. चीन जनवादी गणराज्यको पूर्ववर्ती मामलों में प्राधिकारी द्वारा और अन्यदेशों में जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अपनायी गई स्थिति गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।

ii. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों :-

क. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में नहीं दिया जा सकता है जबकि एक प्रमुख शेयरधारक राज्य स्वामित्व/नियंत्रित कंपनी है।

ख. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी चीन के निर्यातक यह सिद्ध न करें कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती हों।

ग. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न करें कि उनकी बहियों की लेखापरीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार की जाती है।

घ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता यदि मापदंडों में से एक भी पूरा न हो।

ङ. यह दायित्व चीन के प्रतिवादी निर्यातकों का है न कि निर्दिष्टप्राधिकारी का कि वे सिद्ध करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशा में काम कर रहे हैं।

च. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह समग्र रूप से यह दावा करें।

छ. ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान शेयरधारकों ने स्वयं अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं अपितु उसे किसी अन्य पक्ष से अधिग्रहीत किया है बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक रूपांतरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी न हो और दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतः सिद्ध न हो।

iii. इन नियमों के अनुसार, चीन में सामान्य मूल्य को निम्नलिखित आधारों में से किसी एक से निर्धारित किया जा सकता है:

- बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर,
- बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में परिकलित मूल्य,
- ऐसे किसी तीसरे देश से भारत समेत अन्य देशों की कीमत
- भारत में वास्तव में प्रदत्त कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करके
- भारत में वास्तव में देय कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करके।

iv. चूंकि, प्रश्नावली का कोई उत्तर चीन की किसी कंपनियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः संबद्ध देश को गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 के प्रावधान वर्तमान मामले में पूर्ण रूप से लागू होंगे क्योंकि वर्तमान मामले में जांच की अवधि अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016 है और इस प्रकार से सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए वास्तविक स्तरों पर याचिकाकर्ता कंपनियों के उत्पादन की भारित औसत लागत के लिए निम्नलिखित पर विचार किए जाने का अनुरोध है।

v. चीन जनवादी गणराज्यसे निर्यात कीमत को बाजार आसूचना और मानक प्रथाओं के अनुसार निर्यात कीमत के लिए आवश्यक समायोजनों के साथ डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आंकड़ों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

vi. माप की इकाई पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है। उत्पाद का वजन सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद कानूनों के अंतर्गत माप की निर्धारित इकाई है। केवल यह तथ्य कि इन वस्तुओं को बाजार में समूहों में अथवा संख्या में बेचा जाता है, इस प्रयोजन से पूर्ण रूप से अवास्तविक है।

vii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मेला मिन वेयर और ओपल वेयर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश पूर्व में की है। इन उत्पादों में इन मानदंडों के आधार पर किसी अंतर के संबंध में विचार नहीं किया गया था, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अब तर्क दिया जा रहा है।

viii. चूंकि, इकाई का वजन आयात और निर्यात के लिए निर्धारित इकाई है, वास्तव में आयात की सूचना केवल वजन के आधार पर दी जानी चाहिए थी। हालांकि, गलत कारणों से आयातक सामानों को भेजते समय वजन को छोड़कर इकाईयों में आयात की सूचना देते हैं।

ix. उत्पाद के विभिन्न प्रकार को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है और अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि अलग-अलग उत्पादों की लागत में कोई ठोस अंतर नहीं है।

x. अलग-अलग उत्पाद के प्रकारों में आयात के आंकड़ों को अलग करने के लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति उपलब्ध नहीं है, पाटन मार्जिन का अलग-अलग निर्धारण कम से कम अत्यधिक भ्रामक होगा।

xi. इस तर्क के लिए कोई आधार नहीं है कि बोन चाइना की लागत पोर्सिलेन की तुलना में अधिक होती है। वास्तव में बोन चाइना की लागत उत्पादन की कुल लागत का मात्र एक छोटा हिस्सा होता है और इस कारण से यह बिना किसी आधार के है कि बोन चाइना के उत्पाद के प्रकारों की कीमत अधिक होती है।

xii. याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत और चीन से वास्तविक निर्यात कीमत में काफी अंतर है। अन्य हितबद्ध पक्षकार भी अधिकारी को इन आंकड़ों को अलग-अलग करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

xiii. याचिकाकर्ता ने चीन से निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा दिए गए आयात संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया है। आयात संबंधी आंकड़ों में सूचना दिया गया मूल्य सीआईएफ मूल्य है।

xiv. इस याचिका के आंकड़ों और प्रारंभिक जांच परिणाम में मामूली अंतर है क्योंकि साक्ष्य गुणवत्ता और मात्रा में जांच के आगे बढ़ने के साथ ही सुधार होता है।

xv. याचिकाकर्ता ने विशेष अनुरोध पर प्राप्त आयात के डीजीसीआईएंडएस के पूर्ण आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण किया है। उसकी जांच लेन-देन वार की गई थी और उसके बाद विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद की पहचान सर्वप्रथम एचएस कोड की जांच करने और उसके बाद इन उत्पादों का वर्णन करते हुए की गई थी।

**प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

43. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचारों का सारांश निम्नानुसार है :-

- i. सामान्य मूल्य के निर्धारण में याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई और निर्दिष्टप्राधिकारी द्वारा परिकल्पित पद्धति पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अधीन निर्धारित उपबंधों के उल्लंघन में है।
- ii. निर्यात कीमत का निर्धारण और निर्यात कीमत में किए गए समायोजन किसी साक्ष्य के बिना किए गए हैं।
- iii. बोन चाइना, पोर्सिलेन और स्टोन वेयर के लिए पाटन और क्षति का विश्लेषण अलग-अलग किया जाना चाहिए क्योंकि बोन चाइना, पोर्सिलेन और स्टोन वेयर उत्पाद एक दूसरे से अलग-अलग हैं और प्रत्येक क्ले पर आधारित वस्तु की उत्पादन की लागत अलग-अलग होती है और बाजार में इनकी कीमतें अलग-अलग होती हैं।
- iv. चीन 11 दिसंबर, 2016 तक एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था था और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच वर्ष 2017 तक चलती रही है। चीन को अब एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य की गणना चीन के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए।
- v. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद, दोनों को आयात की मात्रा में वृद्धि करने के लिए शामिल किया है। घरेलू उद्योग यह दर्शाने में असफल रहा है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात में जुलाई-अक्तूबर की अवधि के दौरान वृद्धि होती है। इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए कोई आंकड़े नहीं हैं कि अनंतिम शुल्क न्यायोचित था क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का आयात जुलाई-अक्तूबर की अवधि के दौरान बढ़ गया होता।
- vi. विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद के लिए इन आवेदकों द्वारा आयात संबंधी आंकड़ों को अलग-अलग करना भ्रामक है और यह सही नहीं है। विचाराधीन उत्पाद की अपेक्षाकृत अधिक कीमत की प्रविष्टियों को इन आवेदकों द्वारा गैर-विचाराधीन उत्पाद के रूप में चिह्नित किया गया है।
- vii. आयात संबंधी आंकड़ों का अवलोकन करने पर अधिकांश आयात संख्या और समूहों में किए गए हैं। प्रारंभिक जांच परिणाम यह कहता है कि 46 प्रतिशत आयात वजन के आधार पर किया गया है। स्पष्ट रूप से अधिकांश आयात वजन के आधार पर नहीं हुए हैं।
- viii. प्राधिकारी को संबद्ध वस्तुओं की मात्रा और मूल्य का निर्धारण संख्या में करना चाहिए और न कि वजन के आधार पर क्योंकि आयात का अधिकांश हिस्सा (56 प्रतिशत) संख्या में हुआ है।
- ix. संख्या और समूहों को वजन में परिवर्तित करने के लिए अपनाई गई पद्धति सही नहीं है। प्राधिकारी ने इस बात को नहीं माना है कि इकाईयों/संख्या में निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं की उप श्रेणियों के आधे का निर्यात वजन में नहीं किया गया है।
- x. आयात संबंधी आंकड़ों में टेबल वेयर और किचन वेयर की व्यापक श्रेणी शामिल है। प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद की समतुल्य किस्म पर विचार करने में असफल रहे हैं और उसके माध्यम से केवल संख्या में सूचना दी गई विचाराधीन उत्पाद की अन्य उप श्रेणियों के लिए एक वृष्टिपूर्ण मानक निर्धारित हुआ है। प्राधिकारी इस फॉर्मूले के आधार पर सही एनआईपी का निर्धारण करने में असफल रहे हैं।
- xi. इसके अलावा, प्राधिकारी को भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा दिए गए आंकड़ों पर विश्वास करना चाहिए। क्षति का दावा करते समय समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों को "घरेलू उद्योग" में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि उनको बाहर रखने के लिए कोई कानूनी तर्क नहीं है।
- xii. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित करने में असफल रहे हैं कि जांच को प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं था। अर्जेंटीना-निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क ब्राजील से पोल्ट्री पर।
- xiii. वर्तमान जांच में यथा निर्धारित सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के वृष्टिपूर्ण और गलत स्वीकारोक्ति के आधार पर है और यह पाटनरोधी करार और पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत दिए गए अधिदेश के अनुसार मानकों और साक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है।
- xiv. संबद्ध वस्तुओं की मात्रा को परिवर्तित करने की पद्धति निरर्थक है और यह पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 के मानक को पूरा नहीं करता है।
- xv. प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि यह माप की एक इकाई के रूप में वजन में संबद्ध वस्तुओं की कुल मात्रा के संबंध में भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले आंकड़ों की मांग करें और उस पर विश्वास करें।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

44. जांच प्रारंभ करने के चरण में, प्राधिकारी ने एक गैरबाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में चीन जन गण को मानने के अनुमान के साथ कार्रवाई शुरू की। जांच प्रारंभ करने पर प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच प्रारंभ होने की सूचना का उत्तर देने तथा उनकी बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के निर्धारण से संगत सूचना प्रदान करने की सलाह दी। प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी की प्रश्नावली की प्रति भेजी। प्राधिकारी ने चीन सरकार से उनके देश के उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सलाह देने का भी अनुरोध किया। हालांकि, चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादकों और निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर और बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नावली का उत्तर इस प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरू होने की सूचना के फलस्वरूप प्रस्तुत नहीं किया और न ही गैरबाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन किया। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, प्राधिकारी चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के साथ कार्रवाई शुरू करना उपयुक्त समझते हैं। चूंकि, चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने एमईटी की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः प्राधिकारी प्रस्तावित निर्धारण के उद्देश्य से चीन के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने में सक्षम नहीं हैं।

46. इस तथ्य को देखते हुए कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने एमईटी प्रश्नावली सहित निर्यातक की किसी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, एमईटी का दर्जा चीन के उत्पादकों को नहीं दिया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस प्राधिकारी को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन करने के लिए कोई ठोस तथ्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। इस कारण से प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के दूसरे परंतुक को ध्यान में रखकर अन्य उचित आधार पर चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

### **चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण**

47. उपर्युक्त को देखते हुए, चीन जन गण से भारत में आयात किए गए संबद्ध उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए तथा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ मार्जिन के लिए उचित वृद्धि करने के बाद 'किसी अन्य आधार' पर किया गया है। सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के सबसे प्रभावी घटक के लिए अनुमति दिए गए स्तरों पर प्रमुख कच्चे माल की खपत, परिवर्तन लागत, ब्याज, एसजीए आदि पर विचार करने के बाद तय किया गया है। ब्याज को छोड़कर बिक्री की लागत का 5 प्रतिशत उचित लाभ के लिए जोड़ा गया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद का एक्स-वर्क सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन तालिका में दर्शाया गया है।

### **चीन जन गण के निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण**

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी निर्यातक ने निर्धारित रूप में और तरीके से इस प्राधिकारी को सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिसका उपयोग निर्यात कीमत और अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के कारोबार-वार आंकड़ों के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

49. निर्यात कीमत का समायोजन समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन संबंधी खर्च और अंतर्देशीय भाड़ा प्रभार के कारण कारखाना-गत स्तर पर निबल निर्यात कीमत तय करने के लिए किया गया है। तदनुसार, चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात के लिए कारखाना-गत स्तर पर निबल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन तालिका में दर्शाई गई है।

### **पाटन मार्जिन का निर्धारण**

50. उपयुक्त पद्धति के आधार पर संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दिए अनुसार किया जाता है:-

विवरण	जांच की अवधि	
	रु./किग्रा.	डॉलर/किग्रा.
निर्मित सामान्य मूल्य	154.74	2.35
निबल निर्यात कीमत	86.17	1.31
पाटन मार्जिन	68.57	1.04
पाटन मार्जिन - %	79.58%	79.58%
पाटन मार्जिन % (रेंज)	75-85%	75-85%

## ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

### घरेलू उद्योग के विचार:

51. घरेलू उद्योग द्वारा संक्षेप में किए गए क्षति संबंधी अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- देश में मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग की क्षमताओं को भारत में मांग के बराबर नहीं किया जा सकता है। भारतीय क्षमता की तुलना भारतीय मांग से किया जाना अपेक्षित है।
- घरेलू उद्योग को अपनी अपर्याप्तताओं और कुप्रबंधन के कारण हानि नहीं हो रही है।
- लाभ में गिरावट, ह्रास, ब्याज और श्रम लागत के कारण नहीं होती है। उसके संबंध में एक विस्तृत अनुरोध (गोपनीय पाठ) इस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।
- क्षमता को केवल याचिकाकर्ता कंपनी अर्थात् मैसर्स भारत पोर्ट्रीज द्वारा बढ़ाया गया था क्योंकि इसे मोल भाव की कीमत पर एक मौजूदा उत्पादक का संयंत्र एवं उपकरण खरीदने का अवसर मिला था। चूंकि, इस संयंत्र को जांच की अवधि में खरीदा गया था, अतः इस क्षमता को एनआईपी की गणना करते समय शामिल नहीं किया गया था और एनआईपी का कार्य चालन परियोजना की अवधारणा के चरण में अनुमानित वित्तीय व्यय के आधार पर तय किया गया है। इसमें घरेलू उद्योग द्वारा सतत निम्न क्षमता उपयोग को ध्यान में रखा गया है।
- घरेलू उद्योग की स्थिति में प्रारंभिक जांच परिणाम लगाए जाने के बाद सुधार हुआ है और विशेषकर इस अवधि के दौरान शुल्क लगाया जाना इस उत्पाद में निहित मौसम के कारण घरेलू उद्योग के कानूनी हितों की रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा अपेक्षित था। उत्पाद की प्रकृति पर विचार करने पर उत्सव के मौसम के दौरान बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि होती है।
- प्रारंभिक जांच परिणाम को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए अन्यथा घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक क्षति हुई होती।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, उत्पादन और बिक्री की मात्रा में यह वृद्धि, देश में उपलब्ध क्षमताओं के स्तर और मांग पर विचार करने के बाद मामूली है।
- घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग क्षति की अवधि के दौरान 45 से 50 प्रतिशत के दायरे में हुआ है। यह क्षमता उपयोग का निम्न स्तर भी है।
- विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाए जा रहे अत्यधिक पाटन के कारण क्षति की अवधि में क्षमता का कम उपयोग हुआ है जिसके फलस्वरूप भारतीय उत्पादकों द्वारा अपेक्षाकृत कम मात्रा में बिक्री की गई है।
- पर्याप्त घरेलू उत्पादन क्षमता की उपलब्धता के बावजूद उपभोक्ता संबद्ध देश से पाटित आयातों के साथ अपनी मांग को पूरा करना जारी रखता है, जिसके फलस्वरूप मात्रा मानदंड के मामले में अपेक्षा से कम कार्य निष्पादन हुआ है।
- लाभ, नकदी का प्रवाह और नियोजित पूंजी पर आय में जांच की अवधि में गिरावट आई है। निम्न कीमत पर पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को 2014-15 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी कीमतों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार से, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में मंदी आ रही है।



- xii. संपूर्ण रूप में भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- xiii. घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद के माल भंडार में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग अपने उत्पादों को उस स्थिति में भी बेचने में सक्षम नहीं है जब उत्पादन का स्तर आदर्शतम स्तर से कम होता है।
- xiv. हालांकि, घरेलू उद्योग की बिक्री वर्ष दर वर्ष आधार पर लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के मामले में नकारात्मक थी।
- xv. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात प्रस्तावित जांच की अवधि के आधार वर्ष से लगभग दोगुना हो गया है। चीन से आयात में क्षति की अवधि के दौरान भारत में कुल आयात और खपत तथा उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- xvi. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में थोड़ी वृद्धि हुई है, जबकि भारतीय उत्पादकों के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है। दूसरी ओर संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि का लाभ नहीं उठा सका है।
- xvii. संबद्ध आयात घरेलू कीमतों में कटौती कर रहा है और क्षति की अवधि के दौरान कीमत की कटौती में वृद्धि हुई है। आयातों का पहुँच मूल्य क्षति की अवधि दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से बहुत अधिक कम रहा है।
- xviii. आयातों के पहुँच मूल्य में वर्ष 2013-14 में वृद्धि हुई है और तब क्षति अवधि में उसमें गिरावट आई है, जब कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वर्ष 2014-15 तक वृद्धि हुई है और तब जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है, जिससे पाटित आयातों का कीमत न्यूनीकरण प्रभावित हुआ है।
- xix. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, उत्पादन और बिक्री की मात्रा में यह वृद्धि, देश में उपलब्धक्षमताओं के स्तर और मांग पर विचार करने के बाद मामूली है।
- xx. विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाए जा रहे अत्यधिक पाटन के कारण प्रस्तावित क्षति की अवधि में क्षमता का कम उपयोग हुआ है जिसके फलस्वरूप भारतीय उत्पादकों द्वारा अपेक्षाकृत कम मात्रा में बिक्री की गई है।
- xxi. पर्याप्त घरेलू उत्पादन क्षमता की उपलब्धता के बावजूद उपभोक्ता संबद्ध देश से पाटित आयातों के साथ अपनी मांग को पूरा करना जारी रखता है, जिसके फलस्वरूप मात्रा मानदंड के मामले में अपेक्षा से कम कार्य निष्पादन हुआ है।
- xxii. क्षति की अवधि के दौरान लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अधिक गिरावट आई है। वैसी ही प्रवृत्ति घरेलू उद्योग के लाभ, नकदी के प्रवाह और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के निष्पादन में देखी गई थी। तथापि, माल भंडार में और बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग की स्थिति पर दबाव पड़ा है।
- xxiii. अन्य देशों से आयातों का बाजार का हिस्सा पूरी प्रस्तावित क्षति अवधि के दौरान बहुत कम रहा है, जबकि संबद्ध आयातों के बाजार के हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अन्य देशों से आयातों के बाजार का हिस्सा पूरी प्रस्तावित क्षति अवधि के दौरान बहुत कम रहा है।
- xxiv. प्रति कर्मचारी उत्पादन के मामले में माप की गई घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के साथ रोजगार के स्तर में वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद उसमें गिरावट आई है। वर्ष 2014-15 तक मजूदरी में वृद्धि हुई है और उसके बाद प्रस्तावित जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है।
- xxv. घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद के माल भंडार में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- xxvi. मात्रा और कीमत मानदंडों के मामले में घरेलू उद्योग की वृद्धि अपेक्षा से कम रही है। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, दोनों प्रस्तावित जांच की अवधि में सकारात्मक एवं अधिक हैं।
- xxvii. भारतीय उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है, लेकिन भारतीय उद्योग पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण क्षमता उपयोग में सुधार लाने में सक्षम नहीं है। मांग आपूर्ति का अंतर पाटन को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है। विदेशी उत्पादकों को भारतीय मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इन वस्तुओं का पाटन नहीं करना चाहिए।
- xxviii. प्रतिवादी पक्षकार मांग और आपूर्ति के अंतर का उल्लेख कर रहे हैं और दूसरी ओर क्षमता की वृद्धि पर प्रश्न उठा रहे

हैं। क्षमता में वृद्धि हुई थी, क्योंकि मांग में पूरी क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

xxix. क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है क्योंकि पाटित आयातों की मात्रा ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है, कीमत में कटौती, कीमत ह्रास, बदतर लाभ ने इस उद्योग को अपना उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग बढ़ाने से रोका है। विकास के मानदंड नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं।

xxx. संबद्ध वस्तु का विपणन माध्यम ऐसा है कि घरेलू उत्पादकों को इस उत्पाद को व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेचने की आवश्यकता है जो इसे उनके लिए इस वस्तु की कीमत को कम करना असंभव बना देता है और यदि चीन से आयात अपेक्षाकृत कम कीमत पर हो तब इसकी ओर स्पष्ट रूप से उपभोक्ता आकर्षित होंगे जिसके फलस्वरूप और अधिक आयात होगा। ये अंतिम उपभोक्ता नहीं हैं, जिन्हें इतनी अधिक कीमत पर आयात का लाभ मिल रहा है।

xxxi. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य कारकों का उल्लेख किया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते हैं।

xxxii. कीमत में वृद्धि का आरोप निराधार है। प्रश्न यह है कि कितनी बार कीमत में वृद्धि को वाल-मार्ट द्वारा स्वीकार किया जाता है। घरेलू उद्योग ने विभिन्नलागत कारकों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और कच्चे माल की कीमतों में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, जो कि एक वर्ष अथवा दो वर्ष में एक बार होता है, के आधार पर कीमत में वृद्धि होने का दावा किया है।

xxxiii. इन उत्पादों की लागत में कोई अधिक अंतर नहीं है। निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और इन आयात संबंधी आंकड़ों को अलग-अलग उत्पाद प्रकार में अलग-अलग करने के लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति उपलब्ध नहीं है। इसको देखते हुए पाटन मार्जिन का अलग-अलग निर्धारण बहुत अधिक भ्रामक होगा।

### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

52. प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं:-

i. आवेदक को मात्रा में कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि आवेदक-उत्पादक की बिक्री में जांच की अवधि में 7.5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। हालांकि, अन्य उत्पादकों की बिक्री में 23 प्रतिशत तक कमी आई है।

ii. माल भंडार, प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम में निर्धारित नियोजित पूंजी पर आय उसकी ठीक विपरीत है जो सूचना याचिकाकर्ता द्वारा दी गई थी।

iii. आयात के कारण कीमत की कोई मंदी/ह्रास नहीं हुआ है। आवेदक की निबल बिक्री वसूली संबद्ध वस्तुओं की लागत की तुलना में अधिक है।

iv. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे एनआईपी की गणना करने के लिए आय की दर और एनआईपी की गणना करने के लिए प्रयुक्त पद्धति के बारे में बताएं।

v. इस क्षमता को संबद्ध वस्तु की मांग के बावजूद बढ़ाया गया था और यह जांच की अवधि के दौरान स्थिर रही है और इसके साथ ही मौजूदा उत्पादन क्षमता (50 प्रतिशत से कम) है। आवेदक द्वारा उठाई गई क्षति का कारण लागत में वृद्धि और न कि आयात को माना जा सकता है।

vi. प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे सीसीसीएलए द्वारा दिए गए कीमत संबंधी अंडरटेकिंग को स्वीकार करें क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कीमत संबंधी अंडरटेकिंग को विधिवत अन्य मामलों में स्वीकार किया गया था।

vii. प्राधिकारी को छोटे स्तर के चीन के उत्पादकों पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा, यदि सीसीसीएलए द्वारा कीमत संबंधी अंडरटेकिंग स्वीकार नहीं की जाती है तब संदर्भ कीमत का अनुरोध किया जाता है।

viii. एनआईपी का निर्धारण गलत ढंग से किया गया है। कुल तीन उत्पाद हैं और सभी तीन उत्पाद न केवल संरचना के मामले में अलग-अलग हैं बल्कि उनकी लागत, बाजार में बिक्री की क्षमता, कीमत निर्धारण, वजन आदि के मामले में भी अंतर है। इस अंतर को इन उत्पादों के कैटेलॉग और कीमत की सूची से आसानी से देखा जा सकता है।

ix. घरेलू उद्योग को उनकी अपर्याप्तताओं और कुप्रबंधन के कारण नुकसान हो रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा बाधाओं को दूर करना गलत हो गया है और जब बाधाओं को दूर किया गया उसी अवधि में लाभ में गिरावट आई है।

x. ह्रास में वृद्धि हुई है और ब्याज तथा मजदूरी में वृद्धि 2012-13 में हुई है। तदनुसार, उपयुक्त समायोजन क्षति, कारणात्मक संबंध का आंकलन करते तथा एनआईपी की गणना करते समय ह्रास, ब्याज और श्रम की कीमत के रूप में लागतों में बहुत अधिक वृद्धि के कारण किया जाना चाहिए।

- xi. केवल आयात में वृद्धि और कीमत में कटौती क्षति का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे सिद्ध किए जाने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के आयातों पर घरेलू उद्योग का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- xii. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं उठानी पड़ रही है क्योंकि उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर अत्यधिक आय के साथ लाभप्रद बना हुआ है और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहा है।
- xiii. कीमत में कटौती और कीमत पर दबाव का घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और यह लाभप्रद रहा है।
- xiv. प्राधिकारी ने इस बात के लिए कोई निर्धारण नहीं किया है कि क्यों प्रारंभन शुल्क लगाया गया था। इस प्रकार का निर्धारण अनंतिम शुल्क लगाए जाने के पूर्व एक शर्त है।
- xv. घरेलू उद्योग आयातों में वृद्धि के बावजूद लाभ में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है और इस कारण से कोई कारणात्मक संबंध साबित नहीं होता है।
- xvi. घरेलू उद्योग को मात्रा की कोई क्षति नहीं हुई है। संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की अवधि में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। हालांकि, जांच की अवधि में बिक्री में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उद्योग का कार्य निष्पादन घरेलू बिक्री के मामले में काफी अच्छा रहा है। आवेदक जांच की अवधि में अपने पूर्ण उत्पादन के 93 प्रतिशत की बिक्री करने में सक्षम रहा है और इस कारण से क्षति के संबंध में कोई नुकसान नहीं हुआ है। घरेलू उत्पादक संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हुए हैं। संबद्ध वस्तु के आयात में उस सीमा तक वृद्धि हुई है जिस सीमा तक अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में गिरावट आई है। आयात मांग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए किया गया था। घरेलू उत्पादकों को घरेलू बाजार में मांग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर करने में असमर्थता के कारण क्षति हो रही है।
- xvii. वे उत्पादक, जिनके कार्य निष्पादन में गिरावट आई है, ने प्राधिकारी को अपेक्षित आंकड़े/सूचना नहीं उपलब्ध कराकर एक उचित निर्धारण पर पहुँचने में सहयोग नहीं किया है। घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादकों को कोई अन्य क्षति नहीं हुई है और उनका कार्य निष्पादन बहुत अच्छा हो रहा है, परंतु उन्हें घरेलू उत्पादकों की सूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
- xviii. कीमत के मामले में कोई क्षति नहीं हुई है। आवेदकों द्वारा इकाइयों/टुकड़ों में निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं का भार और पाटित सामान की परिणामी कीमत तय करने के लिए अपनाई गई पद्धति दोषपूर्ण है। आयात के कारण कीमत का कोई दमन/ह्रास नहीं हुआ है। आवेदक की निवल बिक्री वसूली संबद्ध वस्तुओं की लागत की तुलना में अधिक है।
- xix. आवेदक कीमत की लागत में वृद्धि की तुलना में अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। प्रत्येक छः महीने में कीमत में वृद्धि होती है।
- xx. आवेदकों की कार्यशील पूंजी क्षति की अवधि के दौरान लगभग दोगुनी हो गई है। कार्यशील पूंजी में इस प्रकार की वृद्धि अविश्वसनीय और काल्पनिक है।
- xxi. घरेलू उद्योग को कथित पाटन एवं क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। आवेदकों ने मांग में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हुए क्षमताओं में वृद्धि की है, लेकिन क्षति की अवधि की जांच के दौरान मांग स्थिर रही है। आवेदक यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं कि घरेलू उद्योग को कथित पाटन के कारण क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति अथवा क्षति का खतरा - आरोप, कथन अथवा अनुमान पर ही आधारित है।
- xxii. ऐसे भी उदाहरण रहे हैं जहां घरेलू आपूर्तिकर्ताओं ने आदेश दी गई मात्रा से कम वस्तु की आपूर्ति की है और वे निर्धारित अवधि के भीतर वाल-मार्ट को वस्तुओं की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं रहे हैं।
- xxiii. इस याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इस आधार पर, पाटनरोधी शुल्क की मांग करना कि मांग में वृद्धि धीमी है, पूर्ण रूप से अनावश्यक है और इसका कोई औचित्य नहीं है।
- xxiv. याचिकाकर्ताओं के उत्पादन में जांच की अवधि के दौरान धीरे-धीरे वृद्धि हुई है और घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई है। क्षमता उपयोग में थोड़ी-सी गिरावट आई है, परंतु वह बढ़ी हुई संस्थापित क्षमता के कारण हुई है और न कि कथित पाटन के कारण। याचिकाकर्ता 2012-13 में घाटा उठाने वाली कंपनी से आगे बढ़कर 2013-14 और उससे आगे जांच की अवधि तक बहुत अधिक लाभप्रद इकाई बन गई है। जांच की अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई है। ऐसा कोई आर्थिक कारक नहीं प्रतीत होता है जिसने भारत में विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के कारण प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला हो।

xxv. इन आवेदकों की स्थापित क्षमता घरेलू बाजार में मांग की तुलना में कम थी। मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए आयात किए गए थे।

xxvi. घरेलू उद्योग का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है और यह लाभ अर्जित कर रहा है। कीमत में कटौती मात्र घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। घरेलू उद्योग के लाभ में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

xxvii. प्रारंभिक जांच परिणाम में दर्ज किए गए उत्पादन और क्षमता उपयोग के आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है और ये आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़ों के विपरीत हैं।

xxviii. आवेदकों द्वारा इस जांच को शुरू करने के लिए दिए गए आंकड़े/सूचना पूर्ण रूप से सही नहीं हैं।

xxix. घरेलू उद्योग ने अपनी वाद की सुनवाई में लिखित अनुरोध में मासिक आधार पर संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में आयात संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और जुलाई-अक्टूबर के दौरान आयातों में उछाल का दावा किया है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह केवल संबद्ध वस्तुओं के मूल्य और न कि उसकी मात्रा को दर्शाता है। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का आयात मूल्य उस मूल्य से मेल नहीं खाता है जिसे प्रारंभिक जांच परिणाम में दर्ज किया गया है।

xxx. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे सीसीसीएलए द्वारा दिए गए कीमत संबंधी अंडरटेकिंग को स्वीकार करें।

xxxi. एनआईपी की उचित तुलना और गणना के लिए अपनाई गई पद्धति पूर्ण रूप से गलत है। प्राधिकारी को बोन चाइना, पोर्सिलेन और स्टोन वेयर उत्पादों के लिए अलग-अलग एनआईपी की गणना करनी चाहिए थी और उन्हें क्षति का मार्जिन तय करने के लिए आयात किए गए सदृश्य उत्पादों से तुलना करनी चाहिए थी।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

53. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों का ध्यान रखा है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान इस प्रकटन के संगत पैराओं में किया गया है।

54. इसके नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण स्वतः इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

55. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि घरेलू उद्योग के पास इस देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि इस देश में मांग और पूर्ति में अंतर है, तो विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद को लाकर इस देश में उस अंतर को निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। मांग और आपूर्ति में अंतर इस उत्पाद के पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है।

56. क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटन के प्रभाव तथा सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों, जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, पर इसके प्रभाव की जांच क्षति के मौजूद होने तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, का मूल्यांकन करने के लिए की है।

### **i. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव**

#### **क. आयात मात्रा**

57. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने माप की एक उपयुक्त इकाई के रूप में भार पर विचार किया है। डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों की जांच यह दर्शाती है कि जांच की अवधि में कुल लेन-देन का लगभग 46 प्रतिशत लेन-देन है, जहां आयात की मात्रा की सूचना भार के आधार पर दी गई है। तथापि, शेष आयात अनेक अन्य इकाईयों नामतः संख्या, समुच्चय, दर्जन, टुकड़े और किलोग्राम में हैं। भार के आधार पर आयात के लेन-देन को अपनाया गया है क्योंकि यह विश्लेषण के लिए है। प्रति इकाई औसत आयात कीमत का निर्धारण भार के आधार पर सूचित किए गए आयात के मूल्य और लेन-देन की मात्रा पर विचार करने के बाद किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित प्रति इकाई औसत आयात कीमत पर विचार किया जाता है, जबकि उन लेन-देन, जिनकी सूचना भार को छोड़ कर इकाईयों में दी गई है, भार में दी गई है, जिसके द्वारा 100 प्रतिशत सूचित किए गए आयात, लेन-देन पर विचार विश्लेषण करने के लिए किया गया है। संबद्ध देश से आयातकी मात्रा नीचे दी गई है:-

आयात	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
चीन	मी. टन	5,519	6,596	9,114	10,160
अन्य देश	मी. टन	849	972	810	836
कुल आयात	मी. टन	6,368	7,568	9,924	10,996

58. यह देखा गया है कि संबद्ध देश के आयात में क्षति की अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

**ख. मांग और बाजार हिस्सा**

59. संबद्ध वस्तुओं की मांग/स्पष्ट खपत का निर्धारण सभी देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात और घरेलू बिक्री को जोड़ कर किया गया है।

मांग	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	7,791	7,870	7,948	8,375
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	19,752	18,361	16,795	15,269
भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	27,543	26,231	24,743	23,644
चीन से आयात	मी. टन	5,519	6,596	9,114	10,160
अन्य देश- आयात	मी. टन	849	972	810	836
मांग/खपत	मी. टन	33,911	33,799	34,667	34,640
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	22.97%	23.29%	22.29%	24.18%
अन्य भारतीय उत्पादक (समर्थकों सहित)	%	58.25%	54.32%	48.45%	44.08%
समग्र रूप में भारतीय उत्पादक	%	81.22%	77.61%	71.37%	68.26%
चीन	%	16.28%	19.52%	26.29%	29.33%
अन्य देश	%	2.50%	2.87%	2.34%	2.41%

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में आधार वर्ष की तुलना में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और यह समग्र क्षति अवधि में एक समग्र सकारात्मक प्रगति का भी दर्शा रहा है, जबकि विचाराधीन उत्पाद की मांग, आधार वर्ष से 2 प्रतिशत तक बढ़ गई और उसी अवधि में चीन से आयात में 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

61. इस प्रकार से यह देखा गया है कि भारतीय मांग में संबद्ध देशों के आयातों का हिस्सा क्षति की अवधि के दौरान 16 प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया है। घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा स्थिर रहा है और भारतीय उद्योग के बाजार के हिस्से में समग्र रूप से बहुत अधिक गिरावट आई है।

**ii. उत्पादन के संबंध में पाटित आयातों का हिस्सा**

62. प्राधिकारी यह देखते हैं कि संबद्ध देश से आयातों में भारत में उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है, जिसे नीचे दर्शाया गया है:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
चीन से आयात	मी. टन	5,519	6,596	9,114	10,160
कुल आयात	मी. टन	6,368	7,568	9,924	10,996

घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी. टन	8,128	8,313	8,364	8,652
भारतीय उत्पादन	मी. टन	30,510	30,069	28,283	28,002
की तुलना में संबद्ध देश आयात का हिस्सा					
घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	68%	79%	109%	117%
भारतीय उत्पादन	%	18%	22%	32%	36%

**क. कुल आयातों के संबंध में आयात**

63. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारत में कुल आयातों की तुलना में वृद्धि हुई है।

आयात	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
चीन	मी. टन	5,519	6,596	9,114	10,160
अन्य देश	मी. टन	849	972	810	836
कुल आयात	मी. टन	6,368	7,568	9,924	10,996
कुल आयात में हिस्सा					
चीन	%	87%	87%	92%	92%
अन्य देश	%	13%	13%	8%	8%

64. इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि संबद्ध देश से आयातों के हिस्से ने बाजार के हिस्से पर कब्जा कर लिया है और यह स्वतंत्र रूप से तथा भारत में उत्पादों और खपत दोनों की तुलना में बढ़ा है।

**1. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव**

65. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-II (ii) में प्रावधान निम्नानुसार निर्धारित है:-

*“जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”*

66. यह जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा बहुत अधिक कीमत में कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक कीमतों में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हुआ होता। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत में ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

**कीमत कटौती**

67. यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या आयात इस बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने आयात की पहुंच कीमत की तुलना, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की है। इस संबंध में इस उत्पाद के पहुंच मूल्य और व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और करों को जोड़ कर घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखाना-गत के स्तर पर किया गया था।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयात की पहुँच कीमत	रु./किग्रा.	119	120	115	102
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% (रेंज)	20-30	30-40	40-50	60-70

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों का पहुँच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्रीकीमत की तुलना में कम था और इसके फलस्वरूप कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है जो क्षति की समग्र अवधि और जांच की अवधि के दौरान बढ़ रही है।

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री क्षति के आंकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। क्षति रहित कीमत तय की गई है और इसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की सीमा को तय करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के पहुँच मूल्य से की गई है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर विचार करने के बाद किया गया है।

विवरण	2015-16	
	रु./किग्रा.	डॉलर/किग्रा.
गैर क्षति कीमत (एनआईपी)	***	***
पहुँच कीमत	102.45	1.55
कम कीमत पर बिक्री	***	***
कम कीमत पर बिक्री-%	***	***
रेंज	65-75%	65-75%

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना में बहुत कम है जो कम कीमत पर बिक्री के प्रभावों को दर्शाता है।

#### क) कीमत दबाव/मंदी

##### कीमत दबाव/मंदी

71. इसका निर्धारण करने के लिए कि क्या आयातों के प्रभाव से कीमतों में काफी हद तक ह्रास होगा अथवा कीमतों में वृद्धि रुक जाएगी, जो अन्य प्रकार से हो गई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की जांच की है, जिसे नीचे दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयात की पहुँच कीमत	रु./किग्रा.	119	120	115	102
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	97	86
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	117	114
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	112	112

72. यह देखा गया है कि आयातों का पहुँच मूल्य संपूर्ण क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत के स्तर से बहुत कम रहा है। कम कीमत पर पाटित आयातों से घरेलू उद्योग सम्पूर्ण अवधि के दौरान बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद बिक्री की कीमत को लाभप्रद स्तर तक नहीं बढ़ाने के लिए बाध्य हो गया। इस प्रकार से आयातों से क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है।

### **घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड**

73. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:-

### **क. क्षमता और क्षमता उपयोग**

74. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
क्षमता	मी. टन	17,120	17,120	17,120	19,220
उत्पादन	मी. टन	8,128	8,313	8,364	8,652
क्षमता उपयोग	%	47%	49%	49%	45%
घरेलू बिक्री	मी. टन	7,791	7,870	7,948	8,375

75. यह देखा गया है कि -

(i) घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि को देखते हुए जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है। विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई, इस प्रकार से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षमताओं में वृद्धि देश में इस उत्पाद की मांग में वृद्धि के अनुपात में हुई।

(ii) क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई। तथापि, याचिकाकर्ता को पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताओं से नुकसान हुआ है।

(iii) घरेलू उद्योग के क्षमता के उपयोग को घरेलू उद्योग द्वारा अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में समर्थ नहीं होने के कारण नुकसान हुआ है।

### **ख. माल सूचियां**

76. घरेलू उद्योग के पास औसत भंडार के रूप में नोट किए गए माल भंडार की स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिटs	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
औसत माल सूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	110	125

77. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास माल भंडार में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। माल भंडार में वृद्धि की दर, उत्पादन में वृद्धि की दर से अधिक थी।

### **ग. लाभ/हानि**

78. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता नीचे तालिका में दी गई है:



विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	112	112
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	117	114
लाभ/(हानि)	रु./किग्रा.	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	500	700	100
लाभ/(हानि)	रु. लाख	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	731	1,059	106
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	265	355	217
ब्याज और कर पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	184	240	160

79. उपर्युक्त सूचना से यह देखा गया है कि -

क. संबंधित उत्पाद की घरेलू बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2014-15 तक वृद्धि हुई, लेकिन उसमें जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के लाभ में 2015-16 के दौरान गिरावट 2014-15 की तुलना में बहुत अधिक है।

ख. क्षति की समग्र अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता में वृद्धि हुई। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के बावजूद लाभप्रदता में गिरावट आई।

#### घ. नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ

80. निवेश पर आय, ब्याज और कर पूर्व लाभ और नकदी के प्रवाह की वही प्रवृत्ति रही, जो लाभप्रदता की रहा अर्थात् इसमें क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई परंतु विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई।

	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	184	211	107

#### ङ. रोजगार एवं मजदूरियां

81. रोजगार और मजदूरी नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	101	100
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	110	121
प्रति यूनिट मजदूरी	रु./मी. टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	107	111
-----------	----------	-----	-----	-----	-----

82. यह देखा गया है कि रोजगार उन्हीं स्तरों पर रहा है। दी गई मजदूरी में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

### च. वृद्धि

83. प्राधिकारी निम्नलिखित तालिका से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का विकास, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बिक्री और उत्पादन के मामले में सकारात्मक रहा था। तथापि, घरेलू उद्योग का विकास वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के मामले में नकारात्मक था।

वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16
उत्पादन	%	2%	1%	3%
घरेलू बिक्री मात्रा	%	1%	1%	5%
बिक्री की लागत	%	4%	7%	1%
बिक्री कीमत	%	8%	8%	-3%
प्रति यूनिट लाभ/हानि	%	819%	43%	-91%
नकद लाभ	%	165%	34%	-39%
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	5%	2%	-6%

### छ. पूंजीगत निवेश प्राप्त करने की क्षमता

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान क्षमताओं में वृद्धि की है और नए निवेश किए हैं। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि बाजार में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों की संख्या और इसकी मांग के स्तर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इस देश में इस उत्पाद में और आगे निवेश की पर्याप्त संभावना है। तथापि, मौजूदा उत्पादक बहुत अधिक क्षमता संवर्धन से हट रहे हैं और नए उत्पादक इस कारण से निवेश नहीं कर रहे हैं कि मौजूदा क्षमताएं स्वतः अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं।

### ज. पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

85. प्राधिकारी ने नोट किया है कि संबद्ध देशों से आयात पाटन मार्जिन के न्यूनतम स्तर से बहुत अधिक है। संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन बहुत अधिक है।

### ब. क्षति संबंधी निष्कर्ष

86. उपरोक्त के आधार पर प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत की तुलना में बिक्री हुई है। इस उत्पाद के आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इसके अतिरिक्त इन आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत पर भी दबाव पड़ रहा है। यह देखा गया है कि इस उत्पाद की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में क्षमता के उपयोग, माल भंडार, लाभ, नकदी का प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में गिरावट आई है।

87. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों की मात्रा तथा कीमत प्रभाव के कारण क्षति हुई है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। नियोजित पूंजी पर लाभ और नकद लाभ की भी वही प्रवृत्ति रही जो लाभ की प्रवृत्ति थी। अधिकांश मानदंडों जैसे लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर लाभ के मामले में घरेलू उद्योग का विकास नकारात्मक था। इस प्रकार से, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

### ब. कारणात्मक संबंध और गैर कारणात्मक विश्लेषण

88. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों का घरेलू

उद्योग को क्षति पहुँचाने में योगदान हो सकता था। संबद्ध देशों से पाटन और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच नीचे दिए अनुसार की गई है।

**(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें**

89. संबद्ध देशों को छोड़ कर अन्य देशों से आयात, मात्रा के मामले में बहुत अधिक नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सके अथवा उसे क्षति की संभावना हो सके। अन्य देशों से आयात, कुल आयातों में 3 प्रतिशत से कम और भारत में कुल मांग/खपत का 2 प्रतिशत है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अन्य देशों से आयातों से क्षति हो रही है।

**(ख) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा एवं विदेशी और स्वदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

90. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए एकमात्र बाजार है जहां संबद्ध देशों से पाटित आयातों की प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष रूप से घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तुओं से होती है। यह भी नोट किया गया है कि आयात की गई संबद्ध वस्तुएं और स्वदेश में उत्पादित वस्तुएं, समान वस्तुएं हैं और इनका उपयोग समान प्रयोजन/अंतिम उपयोग के लिए किया जाता है। व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और विदेशी उत्पादकों एवं स्वदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचती हो, का कोई साक्ष्य नहीं है।

**(ग) मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद की मांग ने क्षति अवधि के दौरान वृद्धि दर्शाई है और यह आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान ही हुई है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग की क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं हुई थी।

**(घ) प्रौद्योगिकी का विकास**

92. किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में पर्याप्त परिवर्तन, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच सकती थी, को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

**(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

93. घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में बहुत अधिक संभावित गिरावट के कारण नहीं हुई है। वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस कारण से निर्यात निष्पादन में कोई संभावित गिरावट किसी क्षति का कारण नहीं है।

**(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता**

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकता में गिरावट आने से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

**(छ) अन्य उत्पादों की तुलना में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन**

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के कार्य निष्पादन ने, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा जिस सूचना पर विचार किया गया है, वह केवल विचाराधीन उत्पाद के ही संबंध में है।

**ट. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक**

96. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान वास्तविक रूप से क्षति हुई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित किए गए हैं:-

- i. संबद्ध वस्तुओं के आयातों में जांच की समग्र अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत में क्षति की अवधि और संपूर्ण जांच अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट होती रही है।
- ii. भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।

- iii. भारत में पाटित आयातों के बाजार का हिस्सा, जांच की अवधि के दौरान लगभग 30 प्रतिशत रहा है, जो प्रतिशत के मामले में बहुत अधिक है और वह भी तब जब संबद्ध वस्तुओं की मांग भारत में बढ़ रही है। यह इस कारणवश हुआ है कि आयातों में भारत में बहुत अधिक मांग पर आक्रामक रूप से कब्जा कर लिया है।
- iv. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुपात में अपना उत्पादन और बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। घरेलू उद्योग के पास जांच की अवधि में पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता थी। यद्यपि मांग में वृद्धि हुई थी।
- v. घरेलू उद्योग का माल भंडार बढ़ता रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के बावजूद अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। आयात भारत में मांग पर आक्रामक रूप से कब्जा करता रहा है।
- vi. भारत में हो रहे कम कीमत पर पाटित आयातों के कारण कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण हो रहा है।
- vii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर लाभ पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2013-14 तक बहुत अधिक लाभ हो रहा था और उसे नियोजित पूंजी पर अधिक प्रतिलाभ प्राप्त हो रहा था। तथापि, विशेष रूप से जांच की अवधि के दौरान लाभ और प्रतिलाभ अत्यधिक घाटों और नकारात्मक स्थिति में परिवर्तित हो गए हैं।
- viii. उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते हुए पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक ठोस कारणात्मक संबंध है।

#### ठ. क्षति का आकार और क्षति मार्जिन

97. प्राधिकारी ने यथा संशोधित इस नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुँच कीमत से की गई है। इस प्रकार से निर्धारित क्षति मार्जिन बहुत अधिक है।

विवरण	रु./किग्रा.	अमेरिकी डॉलर/किग्रा.
गैर क्षति कीमत (एनआईपी)	***	***
पहुँच कीमत	102.45	1.55
क्षति मार्जिन	***	***
क्षति मार्जिन-%	***	***
क्षति मार्जिन (रेंज)	65%-75%	65%-75%

#### ड. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

98. प्रकटन पश्चात अनुरोध इन हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए हैं। उनमें उठाए गए मुद्दों को पहले ही पूर्व की जांच की अवधि के दौरान उठाया गया है और उनका उपयुक्त रूप से समाधान कर दिया गया है। हालांकि, स्पष्टता के वास्ते हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोधों की जांच नीचे दिए अनुसार की जा रही है।

#### घरेलू उद्योग के विचार

99. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद सेरामिक टेबल वेयर और किचन वेयर है। बोन चाइना, स्टोन वेयर और पोर्सिलेन वेयर सेरामिक उत्पाद होता है और इस कारण से विचाराधीन उत्पाद की श्रेणी के अंतर्गत उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। विभिन्न प्रकार के सेरामिक टेबल वेयर और किचन वेयर, केक वेयर, सर्व वेयर आदि अलग-अलग नहीं हैं और एक ही वस्तु हैं।

और यदि घरेलू उद्योग भारत में आयात किए जा रहे इस उत्पाद के समान वस्तु का आयात कर रहा है तब यह उपयुक्त नहीं होगा कि एक उत्पाद को बाहर रखा जाए।

ii. प्राधिकारी ने सही रूप में सब्लिमेशन/इमेज कप और फायर क्ले किचन वेयर को बाहर रखने को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि उसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जा रहा है।

iii. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया इस तथ्य को पूर्ण रूप से स्पष्ट करें कि बोन चाइना, पोर्सिलेन और स्टोन वेयर “सेरामिक उत्पादन” के अंतर्गत आता है और किचन वेयर, सर्व वेयर, टेबल वेयर आदि केवल अलग-अलग शब्द हैं जिनका प्रयोग कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे से बचने के उद्देश्य से व्यापार बातचीत में एक-दूसरे के साथ किया जाता है।

iv. प्राधिकारी कृपया शुल्क तालिका में इस बात का उल्लेख करें कि विचाराधीन उत्पाद पर सीमा शुल्क वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत इन वस्तुओं को आयातकों द्वारा बेचा जा रहा है, पर विचार किए बिना शुल्क लगाना चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकारी कृपया शुल्क तालिका में इस बात का भी उल्लेख करें कि सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है। यह केवल शुल्क तालिका की विषय वस्तु है जो इस संबंध में संगत है। “विचाराधीन उत्पाद” से संबंधित पैरे में उल्लिखित परंतु शुल्क तालिका में उसका उल्लेख नहीं किए जाने पर किसी तथ्य पर संभवतः वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करते समय ध्यान नहीं दिया गया होगा। इसके अलावा, बंदरगाह पर सीमा शुल्क प्राधिकारी, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर विचार तथा विश्वास करते हैं। सीमा शुल्क के प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम के रूप में पाटनरोधी महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना को नहीं मानते हैं। इस कारण से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि शुल्क तालिका अपने आप में इन सभी स्पष्टीकरण को शामिल करता है।

v. याचिकाकर्ता कंपनियों का समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन में बहुत बड़ा हिस्सा है और यह पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) के अर्थ के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है।

vi. सीजीसीआईआर द्वारा जारी पत्र सही है और इसमें संगठित और असंगठित दोनों कंपनियों के संबंध में सूचना दी गई है। असंगठित क्षेत्र के संबंध में विशिष्ट सूचना के अभाव में संगठित क्षेत्र के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है।

vii. पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन बहुत अधिक है।

viii. माप का रूप निश्चित मात्रा तथा अमेरिकी डॉलर में व्यक्त के रूप में रखा जाना अपेक्षित है।

ix. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे प्रारंभिक जांच परिणाम स्वीकार करें।

### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

**100.** विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है:-

i. कुक वेयर उत्पादों को उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह कहना सही नहीं है कि किचन वेयर, टेबल वेयर और कुक वेयर शब्दों का उपयोग व्यापारिक बातचीत में एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है। प्राधिकारी को उत्पादों की दो तरह से प्रतिस्थानापन्न होने अर्थात् सोडियम ट्रिपोली फॉस्फेट के मामले में जांच करनी चाहिए। कुक वेयर उत्पादों का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है तथा खाना परोसने और पेय पदार्थों को परोसने के लिए किया जा सकता है परंतु किचन वेयर और टेबल वेयर का उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े अपने आप में “सेरामिक कुक वेयर” का गैर विचाराधीन उत्पाद के रूप में उल्लेख करते हैं। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम और प्रकटन के लिए इस याचिका के आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है जिसमें सेरामिक कुक वेयर को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा गया है। इस याचिका में दी गई आयात संबंधी मात्रा और मूल्य से प्रारंभिक जांच परिणाम और प्रकटन विवरण में आयात संबंधी मात्रा और मूल्य में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से ऐसा कोई विश्लेषण अथवा निर्धारण नहीं है कि कुक वेयर उत्पादों को पाटित किया जा रहा है और इससे क्षति हो रही है। इस याचिका, जांच परिणाम एवं प्रकटन विवरण में सम्पूर्ण पाटन एवं क्षति विश्लेषण इस धारणा के आधार पर किया गया है कि सेरामिक कुक वेयर आयात संबंधी आंकड़ों का हिस्सा नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि जांच की अवधि के दौरान उत्पाद के क्षेत्र को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए प्राधिकारी को विशेष रूप से यह प्रावधान करना चाहिए कि कुक वेयर को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा जाए।

ii. फायर क्ले उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग केवल खाना बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। प्राधिकारी को इस तथ्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि फायर क्ले कुक वेयर उत्पादों का विनिर्माण भारत में नहीं किया जाता है। इसका उल्लेख सही रूप में नहीं किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों को इस संबंध में

कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि किस प्रकार से ये उत्पाद बाहर किए जाने के लिए अनुरोध करते समय सेरामिक्स का टेबल वेयर अथवा किचन वेयर नहीं होता है।

iii. पोर्सिलेन उत्पादों को उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता का पोर्सिलेन उत्पादों के लिए याचिका दायर करने हेतु कोई आधार नहीं है क्योंकि कोई भी याचिकाकर्ता पोर्सिलेन उत्पादों का निर्माण नहीं करता है। केवल मैसर्स अंबरटो सेरामिक्स इंटरनेशनल प्रा. लि. ने उल्लेख किया कि वे भारत में पोर्सिलेन मर्दों का निर्माण करते हैं। हालांकि, वे न तो आवेदक का हिस्सा हैं और न ही इस याचिका के एक समर्थक हैं।

iv. इसकी जांच करते समय प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए इन तथ्यों को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया है कि इस जांच में विचाराधीन उत्पाद में बोन चाइना वेयर्स, पोर्सिलेन वेयर एवं स्टोन वेयर्स की तुलना में तीन प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। तदनुसार, इन तीनों प्रकारों में इनकी संरचना बल्कि इनकी लागत, विपणन की क्षमता, कीमत निर्धारण, वजन आदि के मामले में भी बहुत अधिक अंतर है। विचाराधीन उत्पाद सजावट और गैर सजावट के मामले में भी अलग-अलग हैं। इस कारण से संबंधित सभी उत्पादों पर कोई एक पाटन अथवा क्षति मार्जिन न केवल एक पक्षीय होगा बल्कि इसका कोई अर्थ भी नहीं रह जाएगा।

v. वर्तमान जांच बिना किसी क्षेत्राधिकार के है और इसमें वास्तविक प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएं भी हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है अर्थात् उचित अधिकरण का अभाव, याचिकाकर्ता कंपनियों के आधार का निर्धारण करने के लिए उत्पादन संबंधी अविश्वसनीय आंकड़े, घरेलू उद्योग द्वारा आयात संबंधी आंकड़ों को भ्रामक रूप से अलग-अलग करना। संबद्ध देश से संबंधित अपेक्षाकृत अधिक कीमत का एक बड़ा हिस्सा, जिसे “विचाराधीन उत्पाद” का हिस्सा होना चाहिए था, को इस आवेदक द्वारा “गैर विचाराधीन उत्पाद” के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही, ऐसी भी प्रविष्टियां थीं जिन्हें “विचाराधीन उत्पाद” के रूप में चिन्हित किया गया था, परंतु वे वास्तव में विचाराधीन उत्पादन की परिभाषा का एक हिस्सा नहीं था।

vi. घरेलू उद्योग के आधार का आंकलन सही नहीं है। प्राधिकारी ने 31 प्रतिशत का एक बहुत कम हिस्सा स्वीकार किया है जो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बहुत बड़ा हिस्सा होने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारतीय उत्पादकों का असंगठित क्षेत्र का होना अपने आप में प्राधिकारी को यह अनुमति नहीं देता है कि वह बड़े हिस्से के रूप में होने के लिए 31 प्रतिशत के बहुत कम हिस्से की अनुमति दें। प्राधिकारी के पास बड़े हिस्से के रूप में होने के लिए कुल उत्पादन का एक कम हिस्से की अनुमति देने की लचीली शक्तियां हैं जब यह खंडित बाजार के होने के कारण व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करता हो। वर्तमान मामले में, कोई व्यावहारिक कठिनाईयां नहीं हैं जो अन्य भारतीय उत्पादकों की भागीदारी को रोकता हो जिन्होंने समर्थन पत्र दिया है और जिनका निश्चित हिस्सा कुल उत्पादन में 31 प्रतिशत है। इसके अलावा, सामान्य पत्र के रूप में याचिका का केवल समर्थन करना तब तक सहायता नहीं माना जा सकता है जब तक लागत एवं क्षति संबंधी अन्य मानदंडों के संबंध में पूर्ण विवरण न दिया जाए।

vii. प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रकटन विवरण में ध्यान नहीं दिया गया है। यह स्मरण किया जाए कि एक आर टी आई प्रश्न के जवाब में सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा इसकी विशिष्ट रूप से पुष्टि की गई है कि वे भारत में सेरामिक टेबल वेयर के कुल उत्पादन का कोई रिकार्ड संकलित नहीं करते हैं और न ही रखते हैं। इस कारण से यह बहुत अधिक स्पष्ट है कि जब प्रधान निकाय ने स्वयं औपचारिक रूप से इसका पुष्टि कर दी है कि इस प्रकार की कोई सूचना उनके द्वारा संकलित नहीं की जाती है और न रखी जाती है तब केवल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उसके प्रदान किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

viii. आयात संबंधी आंकड़ों का निर्धारण अनुचित रूप से और गलत तरीके से किया गया है। सबसे पहले प्राधिकारी ने पूर्व के तीन वर्षों के लिए आयात संबंधी लेन-देन का कोई आधार प्रदान नहीं किया। दूसरा, यह सही नहीं है कि आयात संबंधी लेन-देन को वजन के मामले में गुणवत्ता का निर्धारण किया जाए जिसकी सूचना वजन में सूचना दिए गए आयात संबंधी लेन-देन के मूल्य के आधार पर समूहों/टुकड़ों/संख्याओं में दी गई है। तीसरा, आयात संबंधी मात्रा का निर्धारण करने के लिए प्रयोग में लाई गई पद्धति को आंशिक रूप में प्रकट नहीं किया गया है और यह अनुचित रूप में सही नहीं है।

ix. हितबद्ध पक्षकारों के पास इन आवेदकों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बिना इसके रूप पर ध्यान दिए बिना दायर की गई सभी सूचना को प्राप्त करने का एक निहित अधिकार है जहां तक वह कार्यालयी रिकार्ड का हिस्सा हो जिसके आधार पर प्राधिकारी गोपनीयता के प्रावधानों के अध्यधीन विश्वास करने का प्रस्ताव करते हैं। रिकार्ड में पहले से आंकड़ों की सॉफ्ट प्रति (सॉफ्ट फॉर्मेट में) नहीं देना इन नियमों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन होगा। प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद न तो प्राधिकारी ने और न ही घरेलू उद्योग ने जांच के प्रारंभ किए जाने के उद्देश्य से उपयोग में लाए गए आयात के मूल आंकड़े प्रतिवादी पक्षकारों को उपलब्ध कराए। यह पुनः उल्लेख किया जाता है कि

आवेदन के साथ आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आयात संबंधी आंकड़ों मामले के रिकार्ड का हिस्सा हैं और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिए जाने से इंकार करने का कोई कारण नहीं है।

x. घरेलू उद्योग की क्षति का आंकलन सही नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है जब घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन में बहुत कम हिस्सा है तब घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का वस्तुपरक आंकलन नहीं हो सकता है। कुल घरेलू उत्पादन के बहुत बड़े हिस्से उस स्थिति में वास्तविक क्षति के निर्धारण के लिए आंकलित किया जाना अपेक्षित है जब भारतीय उत्पादन के कम हिस्से को बड़े हिस्से के आंकलन के लिए पर्याप्त के रूप में माना गया हो। इसी - फास्टर में, यह नोट किया गया था कि खंडित उद्योगों के मामले में भी जहां घरेलू उद्योग का कम हिस्से पर बड़े हिस्से के होने के रूप में विचार किया गया है, क्षति के निर्धारण के प्रयोजन से घरेलू उत्पादन का पर्याप्त रूप से बड़े हिस्से के आंकड़े प्रदान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से प्राधिकारी से यह अनुरोध किया गया है कि वे क्षति के उचित निर्धारण के लिए अन्य घरेलू उत्पादकों से पूर्ण सूचना प्राप्त करें।

xi. जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की निवल बिक्री प्राप्ति एनआईपी की तुलना में अधिक थी और इस प्रकार के परिदृश्य में किस प्रकार से कीमत ह्रास, मंदी और कम कीमत पर बिक्री के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे न्यायोचित हैं। इसका स्पष्ट मतलब यह होता है। जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता पर इन आयातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इस प्रकार से, प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे क्षति के अपने आंकलन की समीक्षा तथा जांच को रूस और ईरान के मूल के अमोनियम नाइट्रेट और यूरोपीय यूनियन से एक्सरे बैगेज का आयात और निरमा लि. बनाम संघ सरकार को ध्यान में रखकर समाप्त करें।

xii. संबद्ध देश से आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच में कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। प्राधिकारी ने गलत तरीके से बाजार हिस्से को नोट किया है जो जांच की अवधि में 29.33 प्रतिशत है और न कि लगभग 50 प्रतिशत है। जैसा कि प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है। घरेलू उद्योग की बिक्री और उत्पादन में मांग में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि हुई है। लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि इसमें आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में कुछ गिरावट के बावजूद कोई हानि नहीं हो रही है बल्कि इसे अभी भी लाभ हो रहा है। यह टिप्पणी कि घरेलू उद्योग उत्पादन की लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी बिक्री कीमत को लाभप्रद स्तर तक नहीं बढ़ा सका, का समर्थन रिकार्ड में दिए गए आंकड़ों द्वारा नहीं किया गया है। बिक्री की कीमत और बिक्री की लागत में समानुपातिक रूप में वृद्धि हुई।

xiii. घरेलू उद्योग को हानि और चीन जन गण से आयात के बीच कोई संयोग नहीं है। घरेलू उद्योग ने 2014-15 में अपनी उच्चतम लाभ वृद्धि दर्ज की है जबकि चीन के मूल के आयात में बहुत अधिक वृद्धि हुई।

xiv. प्राधिकारी ने गलत तरीके से यह नोट किया है कि क्षति मार्जिन सभी प्रतिवादी निर्यातकों और उत्पादकों के विरुद्ध वास्तविक है क्योंकि इस जांच में किसी उत्पादकों अथवा निर्यातकों ने कोई सहयोग नहीं किया है।

xv. प्राधिकारी कृपया इस पर विचार करें कि यह उपयुक्त मामला है जहां पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश सिर्फ प्रतिशत में की जानी चाहिए। अमेरिकी डॉलर/किलोग्राम के आधार पर शुल्क लगाने से शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव होगा क्योंकि उच्चतर अंतिम उत्पादों पर बहुत कम शुल्क लगेगा और निम्नतर अंतिम उत्पादों पर अनुचित रूप से बहुत अधिक शुल्क लगेगा जो केवल अनुचित ही होगा बल्कि निम्नतर अंतिम उत्पादों का उपयोग करने वाली आम जनता पर अनुचित बोझ भी डालेगा।

xvi. एनआईपी का निर्धारण अनुचित रूप से किया गया है। प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर एनआईपी का निर्धारण करें। हालांकि, प्रकटन के अनुसार प्राधिकारी द्वारा ऐसे निर्धारण का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार से प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे स्पष्ट करें और लागू नियम के आधार पर एनआईपी का संशोधित निर्धारण जारी करें।

xvii. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इन मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए एक अवसर दें जिनका प्रकटन विवरण में दुर्भाग्यवश समाधान नहीं किया गया है अथवा इसकी उपेक्षा कर दी गई है। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि विगत कई मामलों में प्राधिकारी ने वास्तव में प्रकटन पश्चात विवरण सुनवाई का अवसर दिया है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

**101.** यह नोट किया जाता है कि प्रकटन पश्चात चरण में उठाए गए मुद्दों की जांच पहले ही प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त संगत अनुच्छेदों में की गई है। हालांकि, अनुरोध की स्पष्टता के वास्ते उनका समाधान नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

- i. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में यह टिप्पणी की गई है कि प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों की चिंताओं को दूर किया है और विस्तृत जांच के पश्चात जांच परिणाम के उपर्युक्त पैराओं में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया है।
- ii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांगे गए विभिन्न बहिर्गमनों की जांच मद दर मद की गई है और उनका समाधान इस जांच परिणाम के संगत पैराओं में विस्तार से किया गया है। कुक वेयर के संबंध में इस आयातक द्वारा पुनः अनुरोध किए गए विशिष्ट बहिर्गमन की फिर से जांच की गई है और प्राधिकारी इस तथ्य को दोहराते हैं कि सेरामिक कुक वेयर का भी उपयोग सर्व वेयर के रूप में किया जा सकता है और यह तार्किक रूप से टेबल वेयर/किचन वेयर की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इस कारण से इसे वर्तमान जांच के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है।
- iii. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता को असंगठित क्षेत्र में अलग-अलग कंपनियों के उत्पादन संबंध में सटीक सूचना के उपलब्ध न होने को देखते हुए कानून के अंतर्गत राहत से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के निर्धारण के लिए, उदाहरण निदेशालय द्वारा पूर्व के कुछ निर्धारण अर्थात् एए बैट्री, लीड एसिड बैट्री, सिल्क फैब्रिक और सिल्क यार्न आदि में उपलब्ध है जहां उत्पादन का निर्धारण उन जांचों में सूचना के उपलब्ध विश्वसनीय संगत स्रोत के अनुसार आंकलन के आधार पर किया गया था। इस कारण से प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 2(ख) के संबंध में पात्र घरेलू उद्योग के रूप में इन याचिकाकर्ताओं को स्वीकार करना उपयुक्त समझा है।
- iv. सीजीसीआरआई का पत्र प्राप्त करने के संबंध में, यह दोहराया जाता है कि संबंधित पत्र को सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।
- v. आयात संबंधी आंकड़ों के संबंध में यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया है कि इसने वर्तमान जांच में डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है और उसका उल्लेख इस जांच परिणाम के उपर्युक्त संबंधित पैरा में भी किया गया है।
- vi. एनआईपी के निर्धारण के संबंध में यह देखा गया है कि एनआईपी का निर्धारण दिनांक 01 मार्च, 2011 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 15/2011-सीमा शुल्क (एन.टी) के अनुबंध-III के प्रावधानों के अनुसार किया गया है जिसमें गणना के लिए इस निदेशालय में अपनाई जा रही एक समान रीति और नियमों तथा क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए सिद्धांत दिए गए हैं।
- vii. प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी सुनवाई के संबंध में, यह देखा गया है कि नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलने के कारण सुनवाई के दो अवसर प्रदान किए गए हैं और इस कारण से प्रकटन के जारी होने के बाद एक अन्य सुनवाई का अवसर देने का तर्क बिना किसी आधार के है। इसके साथ ही यह भी नोट किया जाए कि नियम 6(6) प्राधिकारी को सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने का विवेकाधिकार देता है, यह एक अनिवार्य प्रावधान नहीं है और इस कारण से सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने दृष्टिकोण मौखिक रूप में तथा लिखित रूप में प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिला था जिसका समाधान प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच परिणाम में विधिवत कर दिया गया है। एक अन्य सुनवाई के लिए अनुरोध का कोई मतलब नहीं है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है।

### **ठ निष्कर्ष**

102. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों, जिन्हें इस जांच परिणाम में दर्ज किया गया है, की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि:

- i. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देश से भारत में इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है जिसके फलस्वरूप पाटन हुआ है।
- ii. घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- iii. संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा वास्तविक क्षति पहुँचाई गई है।

### **इ भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे:**

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से



स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। यह भी माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत के स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और परिणामस्वरूप इसका इन उत्पादों के सापेक्ष प्रतिस्पर्द्धा पर दुष्प्रभाव पड़ गया होगा। हालांकि, भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी, विशेषकर, यदि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति से बचाने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित रखा जाए। इसके प्रतिकूल पाटनरोधी उपायों को लगाने से पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जाएगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी रूप में संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से इसका उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## ६. सिफारिशें

104. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:

- विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देश से भारत में पाटित कीमतों पर किया गया है।
- घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा वास्तविक क्षति पहुँचाई गई है।

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना देने के लिए समुचित अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन स्थापित करने तथा इस प्रकार के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति स्थापित करने के बाद प्राधिकारी का मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन से बचाने तथा घरेलू उद्योग को क्षति को रोकने के लिए अपेक्षित है। इस कारण से प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर नीचे दिए गए निर्धारित रूप में और तरीके से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाए।

106. अपेक्षाकृत कम शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कम के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति होने से बचाया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर दिनांक 12.06.2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 27/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से अधिसूचित तथा दिनांक 04.05.2017 की प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना में नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम-9 में किए गए उल्लेख के अनुसार की गई सिफारिश के अनुसार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की पुष्टि करने की सिफारिश करते हैं।

## शुल्क तालिका

क्रम सं.	टैरिफ मद*	वस्तुओं का विवरण**	विशिष्टता	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि (अमेरिकी डॉलर में)	(यूओएम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6911 और 6912	सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स	कोई	चीन जन गण	चीन जन गण	कोई अन्य	कोई अन्य	1.04	किग्रा.
2	6911 और 6912	सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स	कोई	चीन जन गण	कोई अन्य	कोई अन्य	कोई अन्य	1.04	किग्रा.
3	6911 और 6912	सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स	कोई	कोई अन्य	चीन जन गण	कोई अन्य	कोई अन्य	1.04	किग्रा.

\* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।

\*\* विचाराधीन उत्पाद का विवरण "चाकू और शौचालय की मदों को छोड़कर सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स" है। बोन चाइना, स्टोन वेयर और पोर्सिलेन वेयर सभी उपर्युक्त पैरा 19 में दिए गए विवरण के अनुसार सेरामिक उत्पाद हैं।

107. इस अधिसूचना के प्रयोजन से आयातों का पहुँच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क से यथा निर्धारित आंकलनीय मूल्य होगा और यह सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।

108. इस अंतिम जांच परिणाम से उत्पन्न केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध एक अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2017

(Final Findings)

**Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items”, originating in or exported from China PR.**

**F. No. 14/05/2016-DGAD.**—Whereas, All India Pottery Manufacturers’ Association (AIPMA) and the Indian Ceramic Society (herein referred as petitioners/ petitioner associations) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and Rule *supra* for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of “Ceramic tableware and kitchenware, excluding knives and toilet items”, (hereinafter also referred to as Ceramic tableware and kitchenware or the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) alleging dumping of subject goods from subject country and consequent injury to the Domestic Industry.

2. And whereas the Authority on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a Notification 14/05/2016-DGAD dated 13<sup>th</sup> October, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject anti-dumping investigation in accordance with the sub Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the Domestic Industry.

3. The Authority vide Preliminary Findings issued vide Notification No. 14/05/2016-DGAD dated 4<sup>th</sup> May, 2017 recommended provisional anti-dumping duty in the present investigation. Subsequently vide Corrigendum Notification No 14/05/2016-DGAD dated 15<sup>th</sup> May, 2017, HS codes were corrected. Ministry of Finance issued a notification imposing provisional antidumping duty vide Customs Notification No.27/2017-Customs (ADD) dated 12th June, 2017.

### **B. PROCEDURE**

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation;

- i. The Designated Authority, under the above Rules, received a written application from the Applicants on behalf of the domestic industries, alleging dumping of Ceramic Tableware and Kitchenware products originating in or exported from China PR.
- ii. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 *supra*.
- iii. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject country. The Authority issued a public notice dated 13<sup>th</sup> October, 2016

- published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
- iv. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of China PR in India, known producers/exporters from China PR, known importers/users and the Domestic Industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
  - v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of China in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
  - vi. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
    - a. Kangfu Ceramic Manufacturing Co.
    - b. Changsha Joysaint Dishware Co. Ltd.
    - c. Zibo Timestone International Co. Ltd.
    - d. Shanghai Fine-V Homeware& Gifts Int'l Trade Co. Ltd.
    - e. BRT Industry Co. Ltd.
    - f. Hojiang Ceramic Shenzhen Co. Ltd.
    - g. Shenzhen Goldenwall Ceramic Co. Ltd.
    - h. Qinhuangdao Hdt Trading Co. Ltd.
    - i. Karosa Chinaware (Shenzhen) Co. Ltd.
    - j. Jingdezhen Amtion Porcelain Co. Ltd.
    - k. Handan FengfengShengyuan Ceramic Co. Ltd.
    - l. Leta International Group Co. Limited
    - m. Linton International Co. Ltd. (Rizhao)
    - n. Guangxi Yulin City Jiachao Ceramics Co. Ltd.
  - vii. In response to the initiation notification, none of the exporters/producers from China have responded.
  - viii. China Chamber of Commerce for Import & Export of Light Industrial Products & Arts-Crafts (CCCLA) and M/s Walmart India Pvt Ltd. sought extension of time to submit response after expiry of the original time limits which was duly granted by the Authority i.e. upto 19<sup>th</sup> December 2016. The importer filed the response in the extended period of time whereas CCCLA only filed legal submissions but none of its members filed questionnaire response within the allowed extended time.
  - ix. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules
    - a. K.S. Overseas
    - b. East Coast Distributors Pvt. Ltd.
    - c. Raj Agencies
    - d. YSR Industries Pvt. Ltd.
    - e. Wal-Mart India Private Limited
    - f. Whitegold Trading Co. Pvt. Ltd.
    - g. ICC Realty (I) Pvt. Ltd.

- h. Future Retail Limited
- i. Krishna Enterprises
- j. Karma Trading
- x. M/s Wal-Mart India Private Limited, an importer, had filed Importer Questionnaire responses & legal submissions in the allowed extended time. M/s Hamilton Housewares Pvt. Ltd. also filed the injury submission on 10<sup>th</sup> April, 2017 and Importer's questionnaire response on 2<sup>nd</sup> May, 2017, much beyond the time period given by the Authority to file responses i.e. 28<sup>th</sup> November, 2016 and extended up to 19<sup>th</sup> December, 2016. The submissions have been made available in the public file and also addressed appropriately in this finding.
- xi. Copy of initiation notification was also sent to known Indian producers/Associations of the product under consideration including the petitioners.
- xii. In response, the following have filed their letters supporting the petition
  - a. Yashvi Enterprise,
  - b. Anil Fine Ceramic,
  - c. Samrat Ceramics,
  - d. Raghuveer (India) Limited,
  - e. Marvel Ceramics Private Limited,
  - f. Sea Shell Ceramics (India) Private Limited,
  - g. Mudrika Ceramics (I) Ltd.,
  - h. Shan Tablewares Private Limited,
  - i. Feather Touch Ceramics Private Limited,
  - j. Oasis Ceramics Private Limited
  - k. Tata Ceramics Limited.
- xiii. Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in this Final Finding.
- xiv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules.
- xv. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the Domestic Industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xvi. Non-injurious price has been determined based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvii. Investigation was carried out for the period starting from 1<sup>st</sup> April 2015 to 31<sup>st</sup> March 2016 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014-March 2015 and the Period of Investigation (POI).

- xviii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the POI. The authority has relied upon import data procured from DGCI&S in the present investigation.
- xix. The Authority had issued preliminary findings on 4.05.2017 and the interested parties were asked to file their comments on preliminary findings.
- xx. Subsequent to the issuance of preliminary finding, following interested parties filed submissions to the said investigation and the recommendation thereof:
1. Blue Mountain Impex (P) Ltd.)
  2. K.S. Overseas
  3. Devnow International
  4. Raagashree Impex Pvt. Ltd
  5. Deco Pride India Pvt Ltd
  6. Vijay Exim
  7. Akshita Enterprises
  8. White Gold Trading Co. Pvt. Ltd.
  9. M/s Hamilton Houseware Pvt. Ltd.
  10. China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial products & Air Crafts
  11. Embassy of People's Republic of China in India
- xxi. China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial products & Air Crafts and Embassy of China in India filed only submissions commenting on the petition or the preliminary findings and have not provided any quantified verifiable information. Also, none of the Chinese exporters had filed any information, submissions or exporters questionnaire response.
- xxii. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority also provided opportunity to the interested parties to present their views orally in an Oral hearing held on 13<sup>th</sup> July, 2017. A second public hearing was conducted on 31<sup>st</sup> October, 2017 in view of the change of the Designated Authority as directed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs. Designated Authority, delivered in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 07-01-2011. The parties, who presented their views in the oral hearings, were requested to file written submissions of their views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xxiii. The hearing was attended by the domestic industry, other Indian producers, importers, China Chamber of Commerce and Embassy of China. None of the Chinese exporters attended the oral hearing, nor filed any information pursuant to the hearing held.
- xxiv. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this Final Finding.
- xxv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded these findings on the basis of the 'facts available'
- xxvi. A Disclosure Statement was issued on 29.11.2017 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 06.12.2017 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xxvii. \*\*\* in this Final Finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xxviii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1US\$=Rs. 65.91.

**C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

**Views of the Domestic Industry are as follows:**

5. The Domestic Industry made the following submissions:
  - i. The product under consideration is Ceramic tableware and kitchenware, excluding knives and toilet items, originating in and exported from China PR.
  - ii. Earthen ware, bone china, stoneware and porcelain-ware all constitute ceramic products and therefore the product under consideration includes kitchenware and tableware of ceramics.
  - iii. The various hard, brittle, heat-resistant and corrosion-resistant materials made by shaping and then firing a non-metallic mineral, such as clay, at a high temperature are Ceramics. Bone China is manufactured from calcium phosphate (bone ash), clay, feldspar and quartz powder.
  - iv. Tableware, kitchenware, serve ware cookware are the words used interchangeably in day to day business of this trade.
  - v. Domestic industry constituents are producing and selling different types of product under consideration. All these goods fall under the description of Ceramics. In particular, the constituents of the domestic industry produce tableware and kitchenware of bone china, porcelain and stone.
  - vi. The product has various properties such as powerful hydrophobic and oleo phobic properties, enormous non-stick properties, hygiene protection for ceramic surfaces, strong abrasion resistance, short drying period, can be stored directly after application, resistant to temperature change, drying at room temperature, chemical and abrasion resistant, high efficiency through economical use food safe, environment-friendly, completely frost proof.
  - vii. The subject good is used for the purposes of serving, eating, cooking, drinking and used as tableware, kitchenware, serve ware and cookware etc.
  - viii. Manufacturers use the terminology bone china in view of perception and awareness about it in consumers, more as a marketing gimmick. Depending on regional raw material availability, little change in raw material and its composition is done from time to time and producers and sales channels have evolved a new term as New Bone China or porcelain or even stoneware etc.
  - ix. Change in raw material is basically done to achieve similar chemical properties via available raw materials. All are similar in terms of usage, production, shelf life, and are commonly known as CERAMICS.
  - x. Ceramic tableware, kitchenware and serving ware have no difference in terms of technical properties. The only difference may be specific end use of some items (*for example, a spoon cannot be used where a saucer is required*). The name depends on the usage of the items.
  - xi. In day to day market parlance, the distinction between kitchen ware and table ware is quite blurred. Parties tend to use the word table ware synonym with various kinds of ceramic table wares and kitchen ware or serving ware.
  - xii. The difference between table ware and kitchen ware is extremely minute. It is just a perception with no commercial difference. For example, products such as casseroles, handi, bake ware, cook and serve ware etc. can both be described as table ware as well as kitchen ware.
  - xiii. Kitchenware includes all the items of cook ware which covers utensils used in kitchen such as cooking vessels, saucepans and frying pans etc. Even otherwise, there are very few selective items which could exclusively be classified as table ware or kitchen ware. Most of the products fall under a common category.
  - xiv. Fireclay cannot be excluded from the product scope because it falls under the category of ceramic wares and are imported under the name of ceramics. The domestic industry manufactures the same. A sample was also presented during the first Oral Hearing. Fireclay falls under the category of ceramic wares and imported under the name of ceramics.

- xv. As far as sublimation cup is concerned, the same is being produced by the constituents of domestic industry. The domestic industry not only manufactures plain cups but also coated cups and coated printed cups. Sales invoices of same have been submitted to the authority on confidential basis.
- xvi. The authority rightly stated at the time of (first) oral hearing that the import of alleged cookware was made by an importer calling the product as cook ware and a serve ware. Thus, if interested parties are selling a product as cook ware and serve ware, it follows that there is no scientific methodology followed by the importers or traders in describing the product.
- xvii. Bone china, stoneware and porcelain-ware all constitute ceramic products. The same view was taken by European commission in the anti-dumping investigation against China with regard to the same product scope.
- xviii. The domestic industry has analyzed the imports of the product based on available information in the import data and found that no standard, scientific or consistent methodology has been followed by importers in reporting the imports of the product in India. The import data does not show a universally accepted and objective definition for segregating different product types considering the varied descriptions used by the importers while clearing the goods. No specific features are available in the import data to segregate the imports into different types. So it concludes that all these products i.e bone china, porcelain and stone ware are captured as ceramic wares only, belong to one family of the subject goods and are not reported differently.
- xix. The same product form can be used as kitchenware, serve ware or tableware. Both kitchenware and tableware are recognised under the customs as ceramic ware falling under 6911 and 6912. Kitchenware includes all the items of cook wares which covers utensils used in kitchen such as cooking vessels, saucepans, and frying pans etc. most of the product fall under a common category.
- xx. Majority of imports have been reported without identifying whether the imported product is bone china, porcelain or stone. The domestic industry also does not many a times specify whether the product being sold is bone china, porcelain or stone, which clearly shows that the producers may sell the product without specifying whether the same is of bone china, porcelain or stone.
- xxi. The import price clearly show that the price difference between imports of porcelain ware and ceramic ware is not materially different. Similarly, as against popular perception, the import price of stone ware is also quite comparable to porcelain ware. In fact, there are imports of porcelain ware and stoneware at a price materially higher than bone china.
- xxii. Cost of production of bone China or porcelain ware or stone wares does not differ significantly. In fact, the cost on account of bone china forms so low in terms of total cost of production that the resultant difference in cost of production of different types are extremely low.
- xxiii. Mere difference in shapes, style and sizes of different ceramic products does not mean that the products have different technical properties. Therefore the PUC should not be treated differently based on styles and sizes, the end use of all the products are same.
- xxiv. Subject goods are classified under Chapter 69 of Customs Tariff Act, 1975, under various Customs sub-headings such as 6911 10, 6911 90, 6912 00 etc. However, the customs classification is indicative and is in no way binding on the scope of the proposed investigations.
- xxv. The subject goods produced by the Domestic Industry are identical to the product under consideration being imported into India and there is no difference in applicant's product and product under consideration exported from the subject country and the two are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. There is no significant difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject country and both are technically and commercially substitutable.
- xxvi. The claim of exporter regarding their quality being far superior is strongly refuted. There is no difference in the technology employed. Indian industry is fitted with best of the machines viz roller heads, auto cup plants and equipped with latest state of art, fuel efficient and environment friendly kilns. Kiln furniture, seggars, raw materials, China clay etc. of best quality is readily available. In fact, Indian produced Kiln furniture and raw material is so good in quality that it is being exported to various countries. Difference in quality is not a sufficient justification for

- exclusion of a product as has been held by the Designated Authority and upheld by the Hon'ble CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited Versus Designated Authority.
- xxvii. The scope of the Product under consideration is not broad but similar as in other investigations such as Opal Glassware, Melamine products, Ceramic Insulators. Moreover, in the EU which conducted investigations in the same product defined the PUC in the similar manner.
- xxviii. As per WTO decision the Designated Authority is free to define the Product under consideration in a manner deemed appropriate and proper.
- xxix. If the imported goods are of better colours and designs or are more innovative, it should certainly have better prices than the domestic producers, but it is not so in the present case.
- xxx. The allegation of rejection of domestic products is completely baseless. Walmart still buys Ceramic tableware from the domestic producers.
- xxxi. Domestic Industry is manufacturing and supplying STUDIO pottery to many Indian Retail chains like Future Group (Big Bazar), Lifestyle, Good earth, Shoppers Stop etc.
- xxxii. Absence of reference to kitchenware in the initial authorization letter is a mere inadvertent typographical error. The word tableware and kitchenware are used interchangeably in day to day business in this trade. It is important to look at the intention of the petitioners and data and information that has been used in compiling the petition.
- xxxiii. As far as need for authorization letter for initiation of investigation is concerned the authorization letter is not even part of the application proforma and is not mandated by the proforma. It requires correctness and completeness of all the information provided, and the domestic industry very well provided all the information with regard to the information given by the domestic industry in the application proforma.
- xxxiv. The information given by the petitioners clearly establishes their intent and the product they were seeking anti-dumping duty. The information contained in the petition with regards to imports, evidence of dumping, evidence of injury and costing information pertains to both tableware and kitchenware. The intention of Authorisation letter is to merely express request for anti-dumping duty. The defect was duly cured at the later stage and all the petitioners filed correct authorization letter.
- xxxv. Authorization letter is not the basis for initiating the investigation. Ultimately, the designated authority initiated investigation after sufficient prima facie examination of existence of dumping causing injury to the domestic industry. Moreover, the objection at such belated stage raised by the interested parties shows that the intention is merely to delay and cause impediments in completion of the present investigation.
- xxxvi. The petitioners have analysed entirety of imports (source – DGCI&S) and on the basis of its assessment have identified imports into PUC and NPUC. On specific comment made by the legal representative of the importers, the data has been relooked and rectified wherever needed. The difference is however so insignificant that the same does not lead to any material impact on the quantum of import volumes, import price, price undercutting, dumping margin, and injury margin.

#### **Views of the opposing interested parties**

6. The submissions of various opposing interested parties are summarized as follows:
- i. There is a huge quality difference between the product imported and supplied by the Domestic Industry. The quality of the PUC supplied by the domestic suppliers is not upto the mark.
  - ii. The product supplied by the Domestic Industry is very basic, whereas, imported products are all machine made and have far better finishing, there were many rejections on the goods supplied by the domestic supplier, and packing by the Domestic Industry is very poor.
  - iii. The domestic suppliers do not supply goods less than a truck which leads to increase in inventories and increases days of handling more than prescribed norms of Wal-mart.
  - iv. Reasons for importing goods from China
    - Quality concerns of the product supplied by Domestic Industry



- Domestic suppliers do not have the availability of proper machinery
  - Non availability of goods quality cordierite, saggers, setters and nitride bonded silicon carbide kiln furniture.
  - Non availability of cheaper fuel like natural gas.
- v. The Authority should provide a clarification on product scope. The product under Consideration is too broad and includes heterogeneous products. As per the transaction wise import data sanitary ware and toilet seat were considered as PUC.
  - vi. Spice mills and ceramic grinding parts should be excluded from the product scope because these mills are not used for standard tableware such as cups and plates. The domestic supplier are unable to provide "Studio Pottery" and hence should be excluded from product scope.
  - vii. Sublimation mugs, coated cup blank for heat press printing transfer ("image cup") deserve to be excluded from the scope of PUC in the present investigation as it is layered with a chemical coating and processed further before qualifying as a finished product. It becomes a finished product only after an extensive customization process. It is used more as a gift than a regular kitchenware item. The export value of the "image cup" is one-third of China's total export value, the actual value is achieved by processing in India. Therefore, the Anti-dumping duty would affect the industry.
  - viii. Cookware should be excluded from the product scope because nowhere the petition or preliminary findings talk about inclusion of cookware. Most importantly the domestic industry has marked ceramic cookware as NPUC in the import statistics.
  - ix. Certain ceramic cookware made up of fireclay should also be excluded from the list of the product under consideration because the raw material is different, product characteristics are different, end use is different and there are no manufactures of fire clay in India.
  - x. The raw material used, the product characteristics and end-use of fire clay products are different. There is no manufacturer of a like or directly substitutable article in India. The domestic industry's claim that they could manufacture fire clay products is also empty because they do not have access to the raw material required to manufacture fire clay cookware as the clay required to manufacture this product is not even available in India. The sample shown by the domestic industry during the public hearing was a terracotta cookware product and not a fire clay cookware product. In fact, both fire clay and terracotta cookware products are not part of the product scope. The domestic industry has not made fire clay cookware in the Period of investigation. It was accepted by domestic industry that they should be given 10 days' time to manufacture it. This means that they have never produced the same in past and not during the Period of investigation. Nowhere in the petition is it said that imports of ceramic cookware is causing injury to the domestic industry and it is not mentioned under the scope of product under consideration.
  - xi. Porcelain should be excluded from the scope of product under consideration because the none of the manufacturers produce porcelain. One M/s Umberto Ceramics International Pvt. Ltd stated that they manufacture porcelain but they are neither the applicants nor the supporter of the present petition.
  - xii. The domestic industry majorly makes bone China and there is very less amount of porcelain manufactured by the domestic industry. On the other hand the imports are majorly being made for porcelain.
  - xiii. Subject goods made up of any other component except bone china, stone or porcelain ought to be excluded automatically from the scope of PUC. Tableware of which the main constituents are ball clay, calcium phosphate, quartz, kaoline or mixtures should be excluded from the scope of PUC.
  - xiv. The scope of the product under consideration has been expanded beyond the specific authorization issued by the applicants since the authorization issued by the applicant producers was only for seeking an initiation for "Ceramic Table Ware" and NOT for "Kitchen Ware".
  - xv. The investigation was initiated without proper authorization letter. The product of the scope was expanded from tableware to tableware and kitchenware, beyond proper authorization of the issued by the applicants.

- xvi. Several other producers presented the identical letter and supported the initiation of tableware not kitchenware.
- xvii. This initiation was not justified even if it was for only tableware because the authorization was given for tableware and data was provided for both tableware and kitchenware.
- xviii. The consultants could not have filed petition under rule 5 for tableware and kitchenware both when the authorization pertained only to tableware. *Mis. Nibro Limited vs. National Insurance Co. Ltd.*
- xix. The claim of the petitioners, that they have filed a revised authorization letter post issuance of preliminary findings, cannot cure the problem. The law does not permit filing of authorization letter post filing of the petition because it is supposed to be filed with the petition.

### **Examination by Authority**

7. The product under consideration in the present investigation is defined as “Ceramic table wares and kitchen wares, excluding knives and toilet items” (hereinafter referred to as ‘subject goods’ or PUC).

8. It is noted that bone china, stoneware and porcelain-ware all constitute ceramic products and therefore the product under consideration includes kitchenware and tableware of bone china, stone and porcelain. Ceramic tableware and kitchenware products are used for the purpose of eating, drinking and serving food and beverages in homes and hotels.

9. The product under consideration is not produced in various specifications having any significant difference in the associated cost. Various types of the product, such as spoons, bowls, plates, etc. are produced from the mixture of calcium, quartz, feldspar and china clay. Production of different types merely implies forming this mixture into desired shape. Therefore, it is considered appropriate to classify all these items under a broad heading of “Ceramic Tableware and Kitchenware products”. There has been a similar kind of case for the product called “Opal Glassware of all types” and “Melamine Tableware and Kitchenware products”.

10. The opposing interested parties have disputed inclusion of some products and determination of volume and value of imports. It is noted that the petitioners have adopted the DGCI&S data and analysed the same. It is noted that the Chinese producers have not cooperated with the Authority. Had the Chinese producers cooperated, they would have provided more accurate information with regard to exports made to India. Govt. of China or the Chinese association or the importers have also not provided any information with regard to the total volume and price of imports of the product in India. In the absence of their cooperation, the DGCI&S data is the sole available information and the same has been adopted for the purpose.

11. As regards sublimation mugs, image cup (coated cup blank for heat press printing transfer), the authority notes that the same forms part of tableware and kitchenware. Further, the domestic industry has specifically stated that they are producing and selling these product types and the same was verified at the time of spot verification of the petitioner companies. Therefore, there is no justification for exclusion of sublimation/image cups from the scope of PUC.

12. As regards the Studio Pottery, the same are produced by the petitioner and they have submitted the evidence for supply of the same. As far as cook ware is concerned, the term cook ware could be interchangeably used as table ware or kitchen ware in trade parlance, there being no scientific methodology followed by the importers or traders in describing the product as cook ware or serve ware or kitchen ware or table ware. Therefore, the Authority decided that there is no reason to exclude Studio Pottery or cookware from the scope of PUC.

13. While demanding exclusions of some products, the interested parties have not provided any information how these products do not constitute tableware or kitchenware of ceramics. As the Chinese producers and exporters have not cooperated with the Authority, no specific technical material has been made available to segregate the products. In absence of objective scientific data for such differentiation, the Authority is not convinced with the demand of the importers, and hence request for exclusion is rejected.

14. The interested parties contended without providing any quantifiable and verifiable evidence that there is a huge difference in quality of Chinese and domestic industry product and the quality of the domestic industry product is not upto the mark. The authority notes that unless a quantified and verifiable claim is made, it cannot be established that the goods produced and sold by domestic industry are not like article to the imported product. Further, it is noted that the issue of quality has been considered by authority and CESTAT in the past and it has been held that quality is not a relevant consideration unless it is established

that the product produced and supplied by the domestic industry is a like article to the imported product. Under the rules, the domestic industry is required to offer a like article to the imported product. It is also noted that the allegation of the domestic industry is with regard to the alleged dumping of the product and considering the estimates of normal value, the goods have been sold at a price below normal value and the imports were undercutting the domestic industry prices to a significant extent. If the product is of a higher quality, the imports need not have come at a price lower than domestic industry prices and need not have undercut the domestic industry prices.

15. As regards the contention that the domestic industry does not sell the goods below a truck load, authority notes that the same does not justify dumping and consequent injury to the domestic industry. In fact, Chinese goods are shipped in a container load. A container load material is far higher than a truck load material. If imports are being made in part container load, the consumers could have bought from the domestic industry as well in part truck loads. It is also noted that if goods are imported in container loads from China, the resultant inventories shall be significantly higher. Further, it is noted that this in any case cannot justify dumping by Chinese producers causing injury to the domestic industry.

16. The Authority has relied upon the letter given by CGCRI and has identified various producers of the subject goods in the organised sector and a number of producers in the unorganised sector. The production data of individual company shows that barring the petitioner companies, production of all other domestic producers is significantly low in proportion to Indian production. Further, none of the other Indian producers have provided information relevant to assessment of injury but have given support letters. No other domestic producer of the product has opposed the application. In the facts and circumstances of the case, authority considers that 31% share in Indian production is significant enough to constitute a major proportion of the total production in India.

17. As regards the contention that the petition is only for tableware, the authority notes that notwithstanding the typographical error in the letters accompanying the application, the petition in its relevant section clearly specified scope of the product under consideration as tableware and kitchenware of ceramics. Further, the investigation has shown that all relevant information such as imports of the product in India, Indian production, assessment of dumping margin, injury information, costing information in the petition all pertained to tableware and kitchenware of ceramics. Thus, merely because the letters from the petitioning companies requesting ADD states only tableware, it cannot be contended that the petition is only for tableware and did not include kitchenware. In particular, it is found that the domestic industry has produced and supplied significant volumes of kitchenware, the same is included in the various financial and injury data of the domestic industry and the same was verified at the time of physical verification. The physical verification at the premises of four petitioning companies clearly showed that these companies are producing kitchenware also.

18. Regarding the correct unit for measurement, the single largest unit used in import data from DGCI&S is weight. All the analysis has been done on the basis of weight. Further, it has been seen that more than 60% of the cost of the product is on account of raw material and utilities. The cost of the raw material and utilities is in direct proportion to the weight of the product; therefore, the cost of production is quite linear with weight of the product. Further, it is pertinent to mention that the European Commission earlier conducted an investigation against China, the perusal of the finding clearly show that scope of the product was same as that in the present investigation and the unit of measurement was also in terms of weight. The unit for collection of duty under Customs Act in the relevant HS code for the subject goods is also in terms of weight. The Authority has therefore, decided that the weight is the most appropriate unit of measurement for the present investigation.

19. Subject goods are classified under Chapter 69 of Customs Tariff Act, 1975. It is imported under various subheadings under HS code 6911 and 6912. However, the HS codes are indicative only and product description is the determining factor for the purpose of present investigation.

20. The PUC under the present investigation is "Ceramic table wares and kitchen wares, excluding knives and toilet items". Bone china, stoneware and porcelain-ware all constitute ceramic products and therefore covered under the scope of PUC.

#### **LIKE ARTICLE**

21. Rule 2(d) of the AD Rules defines like article as follows:

*“an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has the characteristics closely resembling those of the articles under investigation”.*

22. As regards to the arguments by the opposing interested parties that the quality, design of the product manufactured by the Domestic Industry and those imported in to India being different, it is noted that there is no quantified evidence provided by interested parties to show the alleged quality difference between the domestic and imported product. The authority notes that a difference in quality cannot be recognized, unless the differences are quantified and their impact demonstrated. The authority also notes the decision of the CESTAT in the matter of “DSM Idemitsu Limited v. Designated Authority”, reported in 2000 (119) E.L.T. 308, where the Tribunal held as follows

*“As the plea of the appellants counsel is not convincing since he did not adduce any evidence/technical literature with reference to process of manufacture to show that product manufactured by the domestic manufacturers was different from that exported into India. .... Difference in quality will not make an article as different and Designated Authority was right in observing that the fact that qualities may be different, does not imply that the imported product and the domestic are not like articles.”*

23. After considering the information on record, the Authority holds that there is no material difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. Product under consideration produced by the Domestic Industry is comparable to the imported subject product in terms of physical & chemical characteristics, production technology & manufacturing process, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable.

24. Thus, the Authority holds that product under consideration produced by the applicant Domestic Industry is like article to the subject product under consideration imported from subject country in accordance with the AD Rules.

#### **D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

##### **View of the Domestic Industry**

25. The Domestic Industry made the following submissions:

- i. The petition is jointly filed by All India Pottery Manufacturers’ Association (AIPMA) and the Indian Ceramic Society (herein referred as petitioners/ petitioner associations) on behalf of domestic producers of the PUC in India. Some of the Indian Producers i.e. Clay Craft (I) Pvt. Ltd., Bharat Potteries Ltd., Ceramic Tableware Ltd. and U.P. Ceramics & Potteries P. Ltd. have the necessary detailed data relating to cost for investigation for imposition of anti-dumping duty on imports of Ceramic tableware and kitchenware, excluding knives and toilet items, originating in and exported from China PR.
- ii. Besides the petitioners, some other Indian producers have supported the petition and support letter were duly filed by the these producers such as Yashvi Enterprise, Anil fine Ceramic, Samrat Ceramics, Raghuveer (India) Limited, Marvel Ceramics Private Limited, Sea Shell Ceramics (India) Private Limited, Mudrika Ceramics (I) Ltd., Shan Tablewares Private Limited, Feather Touch Ceramics Private Limited, Oasis Ceramics Private Limited and Tata Ceramics.
- iii. All the petitioner companies have provided the required information. The petition clearly contains information with regard to imports made by petitioner companies if any. The said statement made in the application was verified by the authority. It has not been found that the statement made by the petitioning companies on this account were factually incorrect
- iv. The share of four petitioner companies is more than 30%. This alone is sufficient for filing the petition as per Rule 5(3). The petitioner is supported by the other Indian producers. The share of Indian producers, along with the supporters, constitutes more than 50%. The authority, the initiation notification, has stated the same.
- v. Requirement under the rules for the purpose of standing are – (a) the petition must be supported by 25%+ of eligible Indian production, (b) the petition must be supported by those domestic producers

- whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application and (c) petitioners production should constitute “a major proportion”. Evidently, rules nowhere specify that the production of petitioners must be more than 25% of eligible Indian production. Support to the petition for more than 25% of eligible Indian production is much different from petitioners themselves commanding more than 25% production. Thus, the argument that the minimum threshold for petitioners is 25% is flawed. The threshold is with reference to support to the petition and not with regard to petitioners. There is huge number of unorganized sector in this industry and they are the one who are badly impacted by dumped imports. About 200 companies in India are producing the product under consideration on small scale and their operation is small as compared to organized sector.
- vi. Small scale industries don't have resources to provide information or contest in the present investigation. Authority in past in Sulphur Black had considered that the market share of domestic producers as a whole is equally important in determining injury.
  - vii. The Authority ought to protect interest of those who cannot protect their interest due to lack of resources.
  - viii. The producers of small scale don't maintain information required for filing the application for anti-dumping investigation. WTO has also recognized special regard that must be had to the unorganized sector. There is no segregated requirement for organized and unorganized sector in DGAD and that might have prevented them from giving relevant information.
  - ix. It is not a case that production of product under consideration is in small scale only in India. In China too, more than 400 companies responded to the EU in response to the questionnaire on sampling.
  - x. The interested parties have not shown that the production assessed by the petitioner is significantly different from what it should be for the present purposes. It is mere assumption by the interested party that petitioners actual production figure could be much higher.
  - xi. The petitioners adopted a conservative approach and overestimated production of other producers in order to be safe that the production of petitioners crosses the 25% threshold. The real fact is that production of unorganized sector is much lower than what has been assessed by the petitioner.
  - xii. Petitioners have not made any imports and nor are related (either directly or indirectly) to any exporter of product under consideration in the subject country or importers in India.
  - xiii. The supporters have supported the petition for imposition of anti-dumping duties on imports of Ceramic kitchenware and tableware from China PR which fulfils the requirement as per AD Rules. As per Rule 5(3), it is clearly mentioned that the support is required to the petition and not the petitioners filing the petition. It could be easily seen from the support letters that the other Indian producers have supported the petition for imposition of anti-dumping duty. Thus the legal requirement stipulated under Rule5(3) is fulfilled.
  - xiv. The letter from CSIR contains company by company details of production, as assessed by them. The interested parties admitted their inability to establish that the Indian production is materially different what is claimed by the petitioners during the first Oral Hearing. The interested parties have not provided any contrary information whatsoever to rebut the claims of the petitioners and they are merely allegations without any supportive evidence which cannot be taken into consideration. The obligation of the petitioners is not beyond information that is reasonably available to the petitioners as per Rule 5.
  - xv. The CSIR letter cannot be disputed. CSIR letter is only to supplement the claim made in the application. The petitioner is obliged to only provide information reasonably available to them. The interested party has not provided any contrary information whatsoever to rebut the claims of the domestic industry
  - xvi. Petition was filed as per the application proforma, which is fully consistent with Rule 5. Moreover, the information given by the petitioners clearly establishes their intent and the product they were seeking anti-dumping duties.

- xvii. The letter from CSIR contains company by company details of production as assessed by them. During the public hearing the interested parties showed their inability to establish that the Indian production is materially different than what has been claimed by the petitioners.
- xviii. All the petitioner companies have provided the required information. The petition clearly contains declaration with regard to imports by petitioner companies if any. The said statement made in the application was verified by the authority. It has not been found that the statement made in the petition on this account were factually incorrect.

**View of the opposing interested parties**

26. The submissions of various interested parties are summarized as follows:

- i. Producers who have been treated as domestic industry, have not filed necessary certification, which is required to be filed in all the investigation to examine pre-conditions of Rule 2 (b) to reach the conclusion of eligibility.
- ii. The test of major proportion is to be done in context of the applicant industry that has provided their data and has provided information to support their claim. In the present case the test of major proportion is applied after adding total production of the supporting domestic producers. When 25% is the minimum requirement for filing application 31% cannot be called as major proportion of the total production in India.
- iii. The supporters have supported M/s. Bharat Potteries Pvt. Ltd., M/s. Ceramic Tableware Pvt. Ltd., & M/s. Clay Craft (India) Pvt. Ltd. whereas the present petition, as per the initiation notification is filed by All India Pottery Manufacturers' Association (AIPMA) and the Indian Ceramic Society, on behalf of the domestic industry and that too only for tableware.
- iv. It was accepted by the petitioners in the public hearing that they don't have data for unorganized sector. So the actual production figure of the domestic industry is much higher than what is mentioned in the preliminary findings. If that is the case the share of the petitioner is not even more than 25% of the total Indian production.
- v. The anti-dumping application is filed in clear violation of Rule 5 of the Ant Dumping rule. The support letters filed by various domestic producers cannot be relied on because on close perusal of the letters it can be seen that the support letter were filed for different anti-dumping investigation filed by different set of producers. On that account the applicants cannot be said to be the Domestic Industry. The investigation should be terminated on account of the fact that it has no express support from the industry.
- vi. The applicants collectively constitute only 30% of the domestic producers, hence not eligible for Domestic Industry. Even if the total production of the applicants is more than 25% but that is relevant with regard to standing of the application and not for the purpose of defining the scope of the Domestic Industry. The Authority could have added other known domestic producers to understand the trend of the Indian producers as a whole.
- vii. Production of PUC as a whole is considerably higher than 30,000 MT contrary to information given by CISR. CISR does not reflect the complete picture and the same was accepted by the Authority during the public hearing. Production data of PUC is not available with the Authority.
- viii. During the hearing it was admitted by the DA that the total Indian production figure given by the CSIR is only an estimated figure and no exact figure of Indian production is available. Such flawed analysis of Indian production is strongly objected.
- ix. If production details of the domestic industry are not known, it means that the records of the domestic industry are not reliable or adequate to quantify production of the domestic industry. It casts serious doubts as to how other figures of the petitioning companies such as sales, capacity, exports, cost of production, SG&A expenses, non-injurious price, etc. have been computed when the domestic industry does not seem to have reliable or adequate records demonstrating the above figures.
- x. The production figures for the Applicant-producer as well as for the supporters do not support documentary evidence on records. On the contrary, the production figures of the Applicant-producer

and the supporters as recorded in the preliminary findings differ from the information provided by the Applicant-producers in the non-confidential version ('NCV') of the Applications.

- xi. The support letters enclosed in the NCV Application do not support the present application. The claimed support is not legible support to the present application as there is no 'express support' to all applicants in the present Petition. None of the other domestic producers have supported the present application prior to the initiation and hence, the standing requirement cannot be said to be fulfilled in terms of Rule 5(3) of AD Rules. Moreover, in order to mislead the Authority, the Applicant in the present investigation has enclosed the same letters / Authorization (filed in the erstwhile application concerning tableware) for claiming support for the present application concerning tableware and kitchenware.

### **Examination by Authority**

27. The petition has been filed by All India Pottery Manufacturers' Association (AIPMA) and the Indian Ceramic Society (herein referred as petitioner associations) on behalf of domestic producers of the PUC in India. Some of the Indian Producers i.e. (a) Clay Craft (I) Pvt. Limited, (b) Ceramic Tableware Pvt. Ltd., (c) Bharat Potteries Ltd. and (d) M/s. UP Ceramics & Potteries Pvt. Ltd. (referred as petitioners/ petitioner companies) have provided the necessary costing and financial information. The petition has been supported by a number of other producers, namely, Yashvi Enterprise, Anil Fine Ceramic, Samrat Ceramics, Raghuvveer (India) Limited, Marvel Ceramics Private Limited, Sea Shell Ceramics (India) Private Limited, Mudrika Ceramics (I) Ltd., Shan Tablewares Private Limited, Feather Touch Ceramics Private Limited, Oasis Ceramics Private Limited and Tata Ceramics Limited.

28. The total Indian production has been estimated on the basis of data given by Central Glass & Ceramic Research Institute (CGCRI) set up under CSIR and the actual data of the petitioner companies. The Central Glass & Ceramic Research Institute (CGCRI) set up under CSIR have mentioned details of producers of the product in the organized sector as well as in the unorganized sector. In absence of any other credible source of information, the Authority considered it appropriate to accept Central Glass & Ceramic Research Institute (CGCRI) set up under CSIR data as a reliable source and due opportunity was also provided by the Authority to all the opposing interested parties to produce a reliable source for demonstrating the total

Particulars	MT	Share in Indian Production %
	POI	POI
Petitioner as a whole	8,652	31%
Supporters as a whole	8,650	31%
Petitioner + Supporter as a whole	17,302	62%
Others	10,700	38%
Indian Production	28,002	100%

production in India and no submissions were made by the opposing interested parties in this regard

29. The petitioning companies have not imported the product under consideration from subject country nor are they related to any exporter or to an importer in India. The Authority has also verified the information provided by the domestic industry

30. As regards production data of unorganized sector, the authority notes that in view of absence of precise information with regard to production of individual companies in the unorganized sector, the petitioners cannot be denied relief under the law. Further it is noted that the production of petitioner companies is significant. The Authority also notes that even in China, there are a large number of producers of the product in organized as well as unorganized sector. In earlier investigations by the Authority where the product under investigation were being produced both in organized and unorganized sector e.g. AA batteries, lead acid batteries, silk fabric and silk yarn etc., the production was determined based on the assessment as per the available credible relevant source of information in those investigations. Therefore, it is considered appropriate to accept the petitioners as the eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) of the Rules.

31. As regards the production of the petitioner domestic industry, it is clarified that the same has been appropriately, adequately and sufficiently quantified. The information submitted by the domestic industry was duly verified with regard to sales, capacity, exports, cost and expenses from the records maintained by the domestic industry. The financial and excise records maintained by the domestic industry have been adopted for the purpose which are reliable and adequately represent the relevant information.

32. As per the evidence available on record, the production of the petitioner companies accounts for a major proportion in the gross domestic production of the like article. The Authority, therefore, determines that the petitioner companies constitutes eligible Domestic Industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

#### **E. CONFIDENTIALITY**

##### **Views of the Domestic Industry:**

33. The Domestic Industry made the following submissions

- i. The Domestic Industry has claimed confidentiality as per the norms of the AD Rules and in fact the opposite interested parties have claimed excessive confidentiality and made it difficult to make proper comment on their submission.
- ii. The information provided by any interested party to the authority on confidential basis cannot be disclosed to other interested parties. CSIR has claimed confidentiality on the information, the Authority has rightly not disclosed the said information. The interested parties have claimed certain documents as confidential and the same has not been disclosed to the Domestic industry.
- iii. Very generic allegation has been made by the interested parties with regard to confidentiality. The interested parties have not been able to pull out any single instance where confidentiality was not allowed by the authority and the petitioners have claimed that information as confidential. Only highly business proprietary information has been kept confidential.

##### **View of the opposing interested parties**

34. The submissions of various interested parties are summarized as follows:

- i. Excessive confidentiality is claimed by the applicants and has not provided information with regard to Production volume, Domestic Sales volume, Export Sales volume, Inventory in volume, COP per unit in Indexed, Selling price per unit in Indexed (g) Profit/(Loss) per unit in Indexed (h) Employment, Productivity, ROCE in percentage, Proforma IV-B, Costing information and ROC version of financial results.
- ii. Not providing such information is completely against the confidentiality provisions provided under the Anti-Dumping Rules. Considerable information has been kept confidential without providing any justification for the same.
- iii. The CSIR letter to the Designated Authority based on which the Designated Authority has examined the standing of the applicants be provided to the interested parties without any delay. If the CSIR letter has been filed by CSIR in confidential form satisfying the requirements under Rule 7 of the AD Rules, the non-confidential version of the letter should be provided to Hamilton.

##### **Examination by Authority**

35. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

36. The Authority noted the fact that the importers are already in possession of the said letter of Central Glass & Ceramic Research Institute (CGCRI) set up under CSIR regarding total production of the subject goods in India, which was obtained against an RTI request, as stated by them during the hearing. Further, the Authority decided to keep the Central Glass & Ceramic Research Institute (CGCRI) letter in the public file for inspection by all the interested parties.

37. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed



to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. Various discussions in this provisional finding are self-explanatory on the other contentions of the Domestic Industry on confidentiality aspect.

#### **F. MISCELLANEOUS ISSUES**

##### **Views of the Domestic Industry:**

38. The Domestic Industry made the following submissions
  - i. The Chinese exporters have not cooperated by not filing any information despite given an opportunity after initiation of the investigation. None of the exporters have filled exporter questionnaire.
  - ii. Chinese producers/exporters Association, responsible for assisting the exporters in defending their case in anti-dumping matters, have also not cooperated by providing detailed information pertaining to costing and exports. The Chinese Association should be considered as non-cooperative
  - iii. The petitioners have adopted the DGCI&S import data, the same has been provided in the NCV copy of the petition. A large share of imports is in weight terms and the other units namely numbers/ pieces/sets have been converted into weight terms for effective analysis of whole of import data. Further PUC is transacted in weight terms at factory level. Therefore, the adoption of unit of measure as weight is appropriate and the opposite party has objected to the same without providing any alternative methods.
  - iv. The necessary costing/financial information has been provided by the petitioner domestic industry as prescribed under the law. The supporters who are also suffering the effects of dumping and have supported the petition are not specifically required to give their costing/financial data.
  - v. The export price from China PR has been determined as per the DGCI&S transaction wise data with due adjustments to the export price as per the market intelligence and standard practices.
  - vi. The prescribed unit of measurement for the PUC under Customs Tariff Act is weight. Therefore, if imports are now being reported in different units of measurements, it is improper on the part of these importers to report in the units other than the prescribed unit of measurement. The mere fact that the goods are sold in the market in sets or pieces is highly immaterial for the purpose. The unit of measurement defined in China Customs as weight only.
  - vii. In nature of various types of the PUC, reference price would be ineffective.
  - viii. The petitioners have analysed entirety of imports and on the basis of its assessment has identified imports into PUC and NPUC. It was open to the interested parties at the stage of initiation to bring relevant information on record or comment on the petition which could have been considered by the Authority while recording preliminary findings. However, the Authority may consider the same appropriately and record final findings.
  - ix. It is difficult to understand that how duty in USD/KG is inappropriate, if this form of duty was appropriate in elastomeric yarn, where different products had so different prices.
  - x. USD/Kg form of duty was appropriate in many other anti-dumping cases where different products had different prices.
  - xi. The present industry being a labor intensive industry, continued injury to the industry is impacting the large number of families who are dependent on these industries on day to day basis.
  - xii. It is important for the Authority to protect the interest of people who are incapable of protecting their interest themselves due to lack of resources.

##### **Views of the opposing interested parties**

39. The submissions of various interested parties are summarized as follows:
  - i. The domestic producers have failed to provide their information despite having notice of the instant investigation, should be treated as non-cooperative under Rule 6 (8) of the Anti-dumping Rule.

- ii. The supporters, who have failed to provide information, show that they have only made unsubstantiated claim of injury before the Authority.
- iii. The Authority has acted in contravention of Article 12.1 of the Anti-Dumping Agreement because it failed to inform the interested parties before initiation that the Authority is satisfied and there are sufficient evidences to justify the initiation of the investigation.
- iv. The petitioners have failed to provide the sources of information relied upon for dumping and injury determination.
- v. The DGCIS data in Excel format both in raw and refined form along with the methodology applied has not been provided.
- vi. The Domestic Industry wrongly segregated the Imports data. A major chunk of higher price entries relating to the subject country, which should have been part of the 'PUC' has been marked as 'NPUC' by the applicant. At the same time, there are entries which are marked as 'PUC' but are not a part of the definition of the product under consideration. In relation to the non-subject countries, the misrepresentation of the imports data is even more glaring the manipulation with regard to the non-subject countries has been done so as to bring down the volume of imports from the non-subject countries to project a better case of causal link, which otherwise is completely absent.
- vii. No investigation should be initiated unless the condition precedent in Article 5.4 of the Anti-dumping Agreement' is fulfilled. Moreover, the initiation of an investigation in the absence of a proper authorization is without the authority of law and cannot be continued.
- viii. The provisional duty imposed by the Authority on the subject goods is without authority of law as the provisional determination does not satisfy the requirements under Section 9B(1)(b)(iii) of the Customs Tariff Act, 1975. The Authority has not given any determination as to why this preliminary duty was imposed. Such determination is prerequisite before imposition of provisional duty.
- ix. Reference price be recommended for imports of bone china, porcelain and stoneware kitchen wares and table wares.
- x. The initiation of the present investigation as well as preliminary findings were not based on positive evidence and are therefore, bad in law since it was admitted and discussed that the production data provided by CISR does not reflect the complete picture of the investigation and has been wrongly relied upon. Authority during the course of the oral hearing also confirmed that neither the Government of India nor any other Association maintains accurate data concerning subject goods.
- xi. The duty in USD/Kg is absurd. The goods have diverse range in terms of costing, usage, application, manufacturing process as well as physical and chemical composition. USD kg would lead to inverse effect of duty, as the higher end products would attract very little duty and the lower end products would attract unreasonably higher duty.
- xii. Authority failed to fulfil the two conditions required for imposition of interim duty namely provisional duty with regard to dumping, injury and causal link at the time of period of investigation and second is injury during the injury period.

#### **Examination by Authority**

40. Various submissions have been made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- i. The Authority notes that the imposition of provisional duty were on account of the fact that Domestic Industry was in urgent despair and was going to be hit further by CANTON FAIR in China in the month of April, wherein buyers from international trade market participate and significant orders are placed, supplies arrive in India around July-October period. Thus if interim measures were not considered the industry would have lost the next season for product.
- ii. The Authority notes that the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority after due examination decided to initiate the present investigation and had decided to revise the Period of Investigation to April 15-March 16. The revised application was sought, subsequent to initiation, and NCV was made available in public file.

- iii. The Authority decided that it would be appropriate to express PUC in terms of weights because at import end as well as factory to dealer end the transactions are mainly done in weight terms. The cost of the raw material and utilities is in direct proportion to the weight of the product; therefore, the cost of production is quite linear with weight of the product. The majority of DGCIS data is available in weight terms and the balanced data available in numbers/sets/pieces has been converted into weight and all the analysis has been done in terms of Kgs.
- iv. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra. Further, the Authority has issued a notification, published in the Gazette of India, extraordinary notifying the initiation of investigation.
- v. As regards the argument that the other domestic producers have not provided the information or the supporters have filed the limited information, it is noted that as per AD Rules, the injury analysis has to be carried out on the basis of the information provided by the Domestic Industry. In the instant case, once it is determined that the petitioner companies constitute Domestic Industry, there is no legal requirements under the AD Rules to rely on the information of the other Indian producers.
- vi. The legal consultant of the importer, who is well conversant with the procedures of DGAD, could have approached the Authority any time in case they wanted raw data. The Authority would have authorised them to collect it from DGCI&S as per their terms and conditions as was done for the petitioner's legal representative. Further, the Authority notes that the DGCI&S transaction by transaction wise data was in the public file being a part of the NCV petition.
- vii. For the analysis data has been duly verified as deemed fit. Further, the various calculations for determination of NEP and landed value as mentioned in the subsequent paras has been carried out as per the methodology and standard practices followed in the Directorate on the basis of verified information.

**G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN.**

Normal Value' under the Rules-

41. According to Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975 'Normal Value' in relation to an article means: -

*comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

**Views of the Domestic Industry:**

42. The following are the submissions made by the Petitioner:

- i. China should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
- ii. Market economy status cannot be granted unless following conditions are fulfilled:
  - a. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity.
  - b. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values.
  - c. Market economy status cannot be given unless the responding exporter establish that their books are audited in line with international accounting standards.
  - d. Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied
  - e. The onus/obligations to establish market economy status is onto responding Chinese exporters and not onto the Designated Authority.
  - f. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim.
  - g. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.
- iii. According to these Rules, the normal value in China can be determined on any of the following basis:
  - the price in a market economy third country,
  - constructed value in a market economy third country,
  - the price from such a third country to other country, including India.
  - the price actually paid in India, adjusted to include a reasonable profit margin.
  - the price actually payable in India, adjusted to include a reasonable profit margin.
- iv. Since no questionnaire response has been filed by any of the Chinese companies, the subject country should be treated as non-market economy. The provisions of article 15 shall be fully applicable to the present case since the POI in the present case is April, 2015 – March, 2016, thus the normal value should be determined on the basis of Para-7 of Annexure-I. The weighted average cost of production of the petitioner companies at actual levels for determination of normal value is requested to consider.
- v. The export price from China PR has been determined as per the DGCI&S transaction wise data with due adjustments to the export price as per the market intelligence and standard practices.
- vi. The unit of measurement has been appropriately considered. Weight of the product is the prescribed unit of measurement under Custom Tariff Act and Excise laws. The mere fact that the goods are sold in the market in sets or pieces is highly immaterial for the purpose.
- vii. The Designated Authority has earlier recommended antidumping duty on imports of melamine ware and opal ware. No distinctions were considered in these products on such parameters as are being contended by interested parties now.
- viii. Since weight of the unit is the prescribed unit for imports and exports, in fact, imports should have been reported only on weight basis. The importers however for malafide reasons report the imports in units other than weight while clearing the goods.
- ix. Different product type cannot be segregated and separate dumping margin cannot be determined because there is no material difference between the cost of different products.
- x. No scientific methodology is available to segregate the import data into different product type, separate determination of dumping margin will at the least be highly misleading.

- xi. There is no basis for the argument that bone china has a higher cost as compared to porcelain. In fact, cost on account of bone china constitutes only a small portion of total cost of production and therefore it is without any basis that the bone China product types have higher costs.
- xii. There are material variations in the export price claimed by the petitioner and the actual export price from China. The other interested parties can also assist the authority to segregate the data.
- xiii. The petitioners have relied upon import data provided by DGCI&S for determination of export price from China. The values reported in import data are CIF values.
- xiv. There are marginal difference in the data of the petition and in the preliminary finding because the quality and quantity of evidence improves as an investigation progresses.
- xv. The petitioners have analyzed in detail the complete DGCI&S data of imports, obtained on specific request. The same was examined transaction by transaction and thereafter the PUC and NPUC were identified by first examining the HS code and then the description of the products..

#### **Views of the opposing interested parties**

43. The views of the opposing interested parties are summarized as follows:
- i. Methodology adopted by the petitioners and envisaged by DA to determined normal value is in contravention to the provisions laid down under Para 7 of Annexure 1 of the AD Rules.
  - ii. The determination of export price and adjustments therein, done to the export price have been made without any evidence.
  - iii. Dumping and injury analysis for bone china, porcelain and stoneware should be done separately since bone china, porcelain and stoneware products are different from each other and articles based on each clay have different cost of production and command different prices in the market.
  - iv. China was a non-market economy until 11<sup>th</sup> December 2016 is of relevance as the investigation has progressed into the year 2017. China should be regarded as a market economy now and normal value should be calculated for China based on the best facts available.
  - v. The domestic industry has included both PUC as well as NPUC to inflate the import volume. The domestic industry has failed to show that imports of the PUC increase during July-October period. Further, there is no data to show that provisional duties were justified because imports of the PUC would have increased during July-October period
  - vi. The segregation of import data by the applicants as to PUC and Non PUC are misleading and incorrect. Higher prices entries of PUC have been marked as NPUC by the applicants.
  - vii. On perusal of the import data majority of the imports are made in number and sets. The preliminary findings say that 46% of the imports are done in weight basis. Evidently majority of the imports are not on weight basis.
  - viii. The Authority should determine volume and values of subject good in pieces and not weight as a major proportion of imports (56%) are in pieces.
  - ix. The methodology adopted for converting the pieces and sets into weight is not correct. The Authority has not appreciated that half of the sub-categories of subject good exported in units/pieces are not exported in weight.
  - x. The import data includes wide range of tableware and kitchenware The Authority has failed to consider the heterogeneous variety of PUC thereby setting an erroneous benchmark for other-subcategories of product under consideration reported in pieces only. The Authority has failed to determine the correct NIP based on this formula.
  - xi. Further, the Authority should rely on data by Indian Customs Authority. The supporting domestic producers claiming injury should be included in 'domestic industry' as there is no legal reasoning for their exclusion.
  - xii. The Authority failed to notify interested parties on being satisfied that there was sufficient evidence to initiate the investigation. *Argentina-Definitive Anti-dumping Duties on Poultry from Brazil.*

- xiii. Normal Value as determined in the present investigation is based on erroneous and false assertions of the domestic industry and does not adhere to the standards and evidentiary requirements as mandated under the AD Agreement and the AD Rules.
- xiv. Methodology of converting the volume of subject goods is absurd and fails to meet the standard of Article 3 of AD Agreement.
- xv. The Authority is requested to seek and rely on the data maintained by the Indian Custom Authorities concerning total volume of subject goods in weight as a unit of measurement.

#### **Examination by the Authority**

44. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of nonmarket economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers/exporters have filed any response.

45. The Authority notes that none of the producers and exporters of the subject goods from the subject country have submitted the exporter's questionnaire response and market economy questionnaire response, consequent upon the initiation notice issued by the Authority and rebutted the non-market economy presumption. In view of the above position, the Authority considers it appropriate to proceed with para-7 of Annexure I to the Rules for determination of normal value in case of China PR. As none of the producers/exporters from China PR has submitted MET questionnaire response, the Authority is unable to grant market economy status to Chinese producers for the purpose of determination.

46. In view of the fact that none of the producers/exporters has filed any exporter's questionnaire including MET questionnaire, MET status has not been accorded to Chinese producers. Further, none of the interested parties, including the Domestic Industry, has made available any material fact to the Authority to select an appropriate market economy third country. The Authority has, therefore, determined the normal value in respect of China PR on other reasonable basis, in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

#### **Normal value determination for China PR**

47. In view of the above, the normal value for the subject products imported from China PR into India has been determined on the "any other basis" by considering best available information with regard to cost of production and after reasonable additions for selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin. The normal value has been constructed considering consumption of major raw materials conversion cost, interest, SGA, etc. at the levels allowed for the most efficient constituent of the Domestic Industry. 5% of cost of sales excluding interest has been added towards reasonable profit. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration is as shown in the dumping margin table below.

#### **Determination of Export Price for exporters from China PR**

48. The Authority notes that none of the exporters have furnished information to the authority in the form and manner prescribed which could be used for determination of the export price and individual dumping margin. Therefore, the Authority has determine the export price for producers/exporters on the basis of the DGCI&S transaction wise data.

49. The export price has been adjusted on account of Ocean Freight, Marine Insurance Commission, Bank Charges, Port Expenses and Inland Freight Charges to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from China PR is as shown in the dumping margin table below.

#### **Determination of Dumping Margin**

50. Based on the methodology explained above, the normal value, export price and dumping margin in respect of all producers/exporters of the subject country is determined as follows.

Particulars	POI	
	Rs/KG	\$/KG
Constructed Normal Value	154.74	2.35
Net Export Price	86.17	1.31
Dumping Margin	68.57	1.04
Dumping Margin - %	79.58%	79.58%
Dumping margin % (Range)	75-85%	75-85%

## H. INJURY AND CAUSAL LINK

### Views of the domestic industry

51. The following are the injury related submissions made by the Domestic Industry in brief;
- There is no demand supply gap in the country. Capacities with the domestic industry cannot be equated with demand in India. Indian capacity is required to be compared with Indian demand.
  - The domestic industry is not suffering because of their insufficiencies and mismanagement.
  - Decline in profit is not on account of depreciation, interest and labor cost. A detailed submission (Confidential version) with regard to same has been submitted to the Authority.
  - Capacity was only enhanced by one of the petitioner company namely M/s Bharat Potteries because it got an opportunity to acquire plant & equipment of an existing producer at a bargain price. Since the plant was acquired in the Period of investigation, this capacity was not taken while calculating the NIP and the working of NIP has been worked out based on projected financials at project conceptualization stage. This takes care of consistent low capacity utilisation by the Domestic Industry.
  - The situation of the domestic industry has improved after the imposition of preliminary findings and Imposition of duty, especially during this period, was very much required to protect the legitimate interests of the domestic industry due to seasonality involved in the product. Considering the nature of product, significant sale happens during festive season.
  - The preliminary findings should be finalized otherwise the domestic industry suffered material injury throughout the injury period and Period of investigation.
  - Production and sales of the domestic industry have increased over the injury period. However, this increase in production and sales volume is insignificant considering the level of capacities available and demand in the country.
  - The capacity utilization of domestic industry has been in the region of 45-50% during the injury period. This is too low level of capacity utilization.
  - Capacity has remained under-utilized in the injury period due to significant dumping being resorted by the foreign producers, resulting in lower volume of sales by Indian producers.
  - Despite availability of sufficient domestic production capacity, consumers continued to meet their demand with dumped imports from the subject country resulting in sub-optimal performance in terms of volume parameters.
  - The profit, cash flow and return on capital employed has declined in the POI. Low priced dumped imports forced the Domestic Industry to reduce its prices despite increase in cost of sales during the period of investigation as compared to 2014-15. Thus the imports are depressing the prices of the domestic industry.
  - Market share of Indian producers as a whole, has declined; whereas market share of subject imports has increased significantly over the injury period.

- xiii. Inventories of the product under consideration with the domestic industry increased significantly over the injury period. The domestic industry is unable to sell its product even when the production level is sub-optimal.
- xiv. Growth of the Domestic Industry was however negative in respect of profits, cash profit and return on investment on year to year basis.
- xv. The volume of import of the subject goods from the subject country has increased significantly over the injury period. The subject imports have almost doubled from base year to proposed POI. Imports from China have increased significantly in relation to total imports, as well as consumption and production in India over the injury period.
- xvi. Market share of Domestic Industry has increased slightly; whereas market share of Indian producers has declined. On the other hand, market share of subject imports has increased significantly over the injury period. The domestic industry could not capitalize on the increase in demand.
- xvii. The subject imports are undercutting the domestic prices and price undercutting has increased over the injury period. Landed price of imports have remained significantly below the cost of sales of the Domestic Industry over the injury period;
- xviii. Landed price of imports have increased in 2013-14 and then declined over the injury period, whereas selling price of the Domestic Industry have increased up to 2014-15 and then declined in the POI succumbing to the price depression effect of dumped imports;
- xix. Production and sales of the Domestic Industry have increased over the injury period. However, this increase in production and sales volume is insignificant considering the level of capacities available and demand in the country.
- xx. Capacity has remained under-utilized in the proposed injury period due to significant dumping being resorted by the foreign producers, resulting in lower volume of sales by Indian producers.
- xxi. Despite availability of sufficient domestic production capacity, consumers continued to meet their demand with dumped imports from the subject country resulting in sub-optimal performance in terms of volume parameters
- xxii. Profitability increased during the injury period. However, there was a significant drop in the Period of investigation as compared to the previous year. Similar trend were followed in performance of the Domestic Industry with regard to profit, cash flow and return on capital employed. However, the inventories increased and the cost of sales increased putting a pressure on the health of the domestic industry.
- xxiii. Market share of imports from other countries has remained very low throughout the proposed injury period whereas market share of subject imports has increased significantly over the injury period. Market share of imports from other countries has remained very low throughout the proposed injury period.
- xxiv. Productivity of the Domestic Industry, measured in terms of production per employee has increased. The level of employment with the Domestic Industry has increased up to 2013-14 and then declined. Wages have increased up to 2014-15 and then declined in the proposed POI.
- xxv. Inventories of the product under consideration with the Domestic Industry increased significantly over the injury period.
- xxvi. Growth of the Domestic Industry in terms of volume and price parameters has remained sub-optimal. Both dumping margin and injury margin in the proposed POI are positive and significant.
- xxvii. Indian Industry has sufficient capacity to cater to the Indian demand. But Indian industry is unable to improve capacity utilization due to presence of dumped imports. Demand supply gap cannot justify dumping. The foreign producers should not dump the goods in order to meet Indian demand.
- xxviii. The opposite party is pointing out the demand supply gap and on the other hand raising questions on enhancement of capacity. The capacity was enhanced because the demand increased throughout the injury period.
- xxix. The injury is due to dumped imports because the volume of dumped imports have captured the market share of the Domestic Industry, undercutting prices, price depression, deteriorated profit, has



prevented the industry from increasing its production, sales, capacity utilization. Growth parameters have been affected negatively.

- xxx. The marketing channel of the subject good is such that the domestic producers need to sell the product through large network which makes it impossible for them to reduce the price of the good and if the Chinese imports are cheaper then it will obviously attract more consumer resulting into more imports. It is not the eventual consumers who are getting benefitted with so significantly low priced imports.
- xxxi. The opposing interested parties have not pointed out other reasons which can cause injury to the Domestic Industry.
- xxxii. The allegation of price hike is baseless. The question is how many time price hikes are accepted by Walmart. The Domestic Industry claimed price increase based on inflationary trend of varied cost factors and exchange rate fluctuations in prices of raw material, that too, once in a year or two years.
- xxxiii. There are no material differences in the cost of the products. The exports have not filed questionnaire responses and no scientific methodology is available to segregate the import data into different product type, in view of this, separate determination of dumping margin will be highly misleading.

#### **Views of the opposing interested parties**

52. The submissions of various interested parties considered relevant by the Authority are summarized as follows;

- i. There is no volume injury to the applicant as the sale of applicant-producer has increased over POI by 7.5% however, the sale of other producers have decreased by 23%.
- ii. The inventory, ROCE determined by the Authority in the preliminary findings is contrary to what information was provided by the petitioner.
- iii. There is no price suppression/depression on account of imports as net sale realisation is higher in comparison to cost of sale of a subject good.
- iv. Authority is requested to disclose the methodology used to calculate NIP and rate of return for calculating NIP.
- v. The capacity was expanded despite the demand for the subject good has remained constant during the Period of investigation, also the existing production capacity (below 50%). The injury suffered by the applicant is to be attributed towards an escalation of cost and not due to imports.
- vi. Authority is requested to accept price-undertaking given by CCCLA, as price undertaking by interested parties were duly accepted in other cases.
- vii. Authority should consider small scale Chinese producers. Also, the reference price is requested in case price undertaking by CCCLA is not accepted.
- viii. The NIP is determined incorrectly. There are three products and all three are not only different in terms of composition but also in terms of their costing, marketability, pricing, weight etc. the difference can be easily seen from the catalogue and price list of the products.
- ix. The domestic industry is suffering losses on account of their insufficiencies and mismanagement. Debottlenecking done by the domestic industry has gone wrong and there is decrease in profit in the same period when debottlenecking was acclaimed.
- x. Depreciation increased and interest and wages have increased in 2012-13, accordingly appropriate adjustments should be made due to significant increase in the costs in the form of depreciation, interest and labor cost while assessing the injury, causal link as well as for the computation of NIP.
- xi. Mere increase in imports and price undercutting is not sufficient to determine injury. It needs to be proved that such imports have negative impact on the domestic industry.
- xii. The domestic industry is not suffering any injury as there is increase in production and sales. The domestic industry remains profitable with high ROCE and market share of the domestic industry has remained stable throughout the injury period.

- xiii. Price undercutting and price suppression has no adverse impact on the domestic industry and it has remained profitable.
- xiv. The Authority has not given any determination as to why this preliminary duty was imposed. Such determination is prerequisite before imposition of provisional duty.
- xv. The domestic industry had been able to increase its profit despite increase in imports, hence proves no causal link.
- xvi. There is no volume injury to the Domestic Industry. The demand of the subject goods have increased by 3% in the Period of investigation however the sale has increased by 12% in the Period of investigation. The industry has performed exceptionally well in terms of domestic sales. The applicants have been able to sell 93% of their total production in Period of investigation. Hence suffering no injury. The domestic producers are unable to meet the domestic demand for the subject good. The import of the subject good has increased to the extent of decrease of sale of the other domestic producers. Imports were made to bridge the demand supply gap. The domestic producers are suffering injury due to inefficiency of filling the demand supply gap in the domestic market.
- xvii. The producer whose performance has deteriorated has not assisted the Authority in arriving at a fair determination by not providing the requisite data/information. There is no injury to the other producers of the domestic market and they are performing exceptionally well but they have not been included under the list of domestic producers.
- xviii. There is no price injury. The methodology adopted by the applicants to arrive at the weight of the subject good exported in units/pieces and the consequent price of the dumped article is flawed. There is no price suppression or depression on account of imports. The net sales realization of the applicant is higher in comparison to the cost of the subject good.
- xix. The applicants have been able to increase their selling price as compare to the increase in the cost of the price. There is a price hike every six months
- xx. Working capitals of the applicants have almost doubled during the injury period. Such increase in working capital is unreliable and unsubstantiated.
- xxi. There is no causal link between the alleged dumping and injury to the domestic market. The applicants have enhanced capacities anticipating increase in demand but the demand remained constant during the examination of injury period. The applicants have failed to provide any evidence to show that the Domestic Industry is suffering injury due to alleged dumping. The material injury or threat of injury to the domestic injury is based only on allegation, statement or conjuncture
- xxii. There have been instances where domestic suppliers have delivered good less than what was ordered and were not able to supply goods to Wal-mart within the prescribed period.
- xxiii. As per the information provided by the DI in the petition the market shares of the Domestic Industry increased by 24% in the Period of investigation. Demanding anti-dumping duty on the ground that increase in demand is slow is completely unwarranted and unjustified.
- xxiv. The production of the petitioners has increased steadily during the Period of investigation and domestic sale has also increased. There is slight decline in the capacity utilization but that is not due to the alleged dumping but on account of increased installed capacity. Petitioners have moved from being loss making in 2012-13 to being hugely profitable units from 2013-14 onwards to the Period of investigation. The wages have increased during the Period of investigation. There are none of economic factors appear to have been adversely affected directly on account of alleged dumping of the PUC in India.
- xxv. The installed capacity of the applicants was low as compare to the demand in the domestic market. Imports were made to meet the deficit arising out of demand supply gap.
- xxvi. The domestic industry is performing well and earning profits. Mere price undercutting is not sufficient to determine injury to the domestic industry. The profits of the domestic industry have increased during POI as compared to base year. There is no causal link between the alleged dumped imports and injury to the domestic industry.
- xxvii. The production and capacity utilization figures recorded in the preliminary findings are unsubstantiated and contrary to the figures / data provided by the applicants.

- xxviii. The data/information provided by the Applicants for the initiation of the investigation was grossly incorrect.
- xxix. Domestic Industry in its post hearing written submissions has provided import data concerning imports of subject goods on monthly basis and claimed surge in imports during July-October which cannot be relied upon as it only reflects the value of imports of the subject goods and not the volume. Furthermore, the import value of subject goods during the POI as per the domestic industry does not reconcile with the value as is recorded in the preliminary findings.
- xxx. The Authority is requested to accept the price undertaking as furnished by CCCLA.
- xxxi. The methodology adopted for fair comparison and the computation of the NIP is wholly incorrect. The Authority ought to have computed separate NIPs for bone china, porcelain and stoneware products and compared them to the corresponding imported products for arriving at the injury margin

### **Examination by the Authority**

53. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties on injury. The issues raised by various interested parties have been dealt with in the relevant paras of this Final Finding.

54. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.

55. As regards the contention that the Domestic Industry does not have sufficient capacity to meet the demand of product under consideration in the country, the authority notes if there is a demand supply gap in the country, the foreign producers can certainly fill the gap in the country by bringing the product at a fair price. Demand supply gap does not justify dumping of the product.

56. For the purpose of injury analysis the Authority has examined effect of dumped imports of the subject goods on the Domestic Industry and its effect on all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of industry to evaluate the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

### **i. Volume Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry**

#### **a. Import volumes**

57. The authority has relied upon import data procured from DGCI&S in the present investigation. The Authority has considered weight as an appropriate unit of measurement. The examination of data received from DGCIS revealed that about 46% of the total transactions in POI are those where import volumes have been reported on weight basis. However, the balance imports are in various other units namely numbers, sets, dozens, pieces and Kgs. The import transactions on weight basis have been adopted as it is for analysis. The per unit average import price has been determined by considering the import value and volume of the transactions reported on weight basis. The per unit average import price, so determined is considered while converting those transactions which are reported in units other than weight, into weight thereby 100% of the reported import transactions have been considered for analysis. Imports volume from subject country were as under:-

Imports	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
China	MT	5,519	6,596	9,114	10,160
Other Countries	MT	849	972	810	836
Total Imports	MT	6,368	7,568	9,924	10,996

58. It is seen that imports from subject country have increased consistently and significantly in absolute terms over the injury period.

#### **b. Demand and market share**

59. The demand/apparent consumption of subject goods has been determined by adding domestic sales and import of subject goods from all countries.

Demand	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Sales of Domestic Industry	MT	7,791	7,870	7,948	8,375
Sales of Other Indian Producers	MT	19,752	18,361	16,795	15,269
Sales of Indian Producers	MT	27,543	26,231	24,743	23,644
Imports from China	MT	5,519	6,596	9,114	10,160
Other Countries – Imports	MT	849	972	810	836
Demand/consumption	MT	33,911	33,799	34,667	34,640
Market Share in Demand					
Domestic Industry	%	22.97%	23.29%	22.29%	24.18%
Other Indian Producers (including supporters)	%	58.25%	54.32%	48.45%	44.08%
Indian producers as a whole	%	81.22%	77.61%	71.37%	68.26%
China	%	16.28%	19.52%	26.29%	29.33%
Other Countries	%	2.50%	2.87%	2.34%	2.41%

60. The Authority notes that the demand for the product under consideration has remained consistent and has marginally increased during POI as compared to the base year and also showing an overall positive trend over the entire injury period. Whereas the demand for the product under consideration increased by 2% from base year, imports from China increased by 84% over the same period.

61. The statistics show that share of imports from subject country in Indian demand increased from 16% to 29% over the injury period. The market share of Domestic Industry has remained almost consistent but the market share of the Indian industry as a whole has declined significantly.

ii. **Share of dumped imports in relation to production**

62. Authority observes that the imports from subject country have increased in relation to production in India as shown below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Imports from China	MT	5,519	6,596	9,114	10,160
Total Imports	MT	6,368	7,568	9,924	10,996
Production of the Domestic Industry	MT	8,128	8,313	8,364	8,652
Indian Production	MT	30,510	30,069	28,283	28,002
Share of subject country imports in relation to					
Domestic Industry Production	%	68%	79%	109%	117%
Indian Production	%	18%	22%	32%	36%

a. **Imports in relation to total imports**

63. Imports of the product under consideration from subject country have increased in relation to total imports into India.

Imports	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
China	MT	5,519	6,596	9,114	10,160

Other Countries	MT	849	972	810	836
Total Imports	MT	6,368	7,568	9,924	10,996
Share in Total Imports					
China	%	87%	87%	92%	92%
Other Countries	%	13%	13%	8%	8%

64. It is, thus, concluded that the share of imports from subject country have captured the market share and increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India

#### **I. PRICE EFFECT OF DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY**

65. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

*"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."*

66. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the Domestic Industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

#### **Price Undercutting**

67. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the Domestic Industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the Domestic Industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the Domestic Industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the Domestic Industry were determined at the ex-factory level.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Landed price of imports	Rs./KG	119	120	115	102
Net Sales Realization	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price undercutting (Range)	%	20-30	30-40	40-50	60-70

68. The Authority notes that the landed price of imports from the subject country was lower than the selling price of the Domestic Industry, thus resulting in significant price undercutting, which is increasing during the entire injury period and POI.

#### **Price Underselling**

69. Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the Domestic Industry for the product under consideration during the POI, in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules.

Particular	2015-16	
	Rs/KG	\$/KG
Non Injurious Price (NIP)	***	***
Landed Price	102.45	1.55

Price underselling	***	***
Price underselling-%	***	***
Range	65-75%	65-75%

70. The Authority notes that the landed price of the subject goods from the subject country is significantly lower than the NIP determined for the Domestic Industry showing significant price underselling effects.

**a) Price suppression/depression**

**Price suppression/depression**

71. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority examined the changes in the costs and prices over the injury period as below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Landed price of imports	Rs./KG	119	120	115	102
Trend	Indexed	100	101	97	86
Net Sales Realization	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	117	114
Cost of Sales	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	112	112

72. It is seen that landed value of imports have remained significantly below the level of cost of sales and selling price of the Domestic Industry throughout the injury period. Low priced dumped imports forced the Domestic Industry to not increase the selling price to remunerative levels despite increase in cost of sales during the entire period. Thus the imports are depressing the prices of the Domestic Industry throughout the injury period

**Economic parameters of the Domestic Industry**

73. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the Domestic Industry are discussed below.

**a. Capacity & Capacity Utilization**

74. Capacity and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the following table:-

Particulars	Units	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Capacity	MT	17,120	17,120	17,120	19,220
Production	MT	8,128	8,313	8,364	8,652
Capacity Utilization	%	47%	49%	49%	45%
Domestic Sales	MT	7,791	7,870	7,948	8,375

75. It is observed that:

- i. Domestic Industry has enhanced its capacity during period of investigation, in view of the increase in demand. Demand for the product under consideration increased over the injury

period. It is thus seen that the enhancement in capacities by the Domestic Industry was commensurate with the increase in demand for the product in the Country.

- ii. Production and sales of the Domestic Industry increased over the injury period, however, the petitioner is suffering significant unutilized capacities.
- iii. Capacity utilization of the Domestic Industry has suffered as a result of the inability of the Domestic Industry to increase its market share.

**b. Inventories**

76. The position of inventories noted as average stock with the Domestic Industry moved as follows;

Particulars	Units	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	110	125

77. It is noted that inventories with the Domestic Industry have increased significantly over the injury period. The rate of increase in inventories was more than the rate of increase in production.

**c. Profit/Loss**

78. The profitability of the Domestic Industry is given in the following table:

Particulars	Units	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Cost of sales	Rs/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	112	112
Selling price	Rs/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	117	114
Profit/( Loss)	Rs/KG	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	500	700	100
Profit/( Loss)	Rs.Lacs	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	731	1,059	106
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	265	355	217
Profit before Interest and Tax	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	184	240	160

79. It is seen from the above information that:

- a. The profitability of the Domestic Industry with respect to domestic sales of the product concerned increased till 2014-15 but deteriorated significantly during POI. The decline in profits of the Domestic Industry during 2015-16 is very significant as compared to 2014-15.
- b. The production, sales and profitability increased over the entire injury period, however, during POI profitability declined in spite of an increase in production and sales.

**d. Return on capital employed**

80. The returns on investment, PBIT and cash flow have followed the same trend as that of profitability i.e. it increased during the injury period but declined in POI as compared to the previous year.

	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	184	211	107

**e. Employment and Wages**

81. The employment and wages are below:

Particulars	Units	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
No of Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	101	100
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	110	121
Wage per unit	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	107	111

82. It is seen that the employment has generally remained at the same levels. Wages paid have increased during period of investigation.

**f. Growth**

83. The growth of various factors was worked for the injury period and POI with 2012-13 as the base year for this comparison. The Authority notes that the growth of Domestic Industry was positive in terms of sales and production on year to year basis. However, growth of the Domestic Industry was however negative in respect of profits, cash profit and return on investment on year to year basis.

Growth (Year by Year)	Units	2013-14	2014-15	2015-16
Production	%	2%	1%	3%
Domestic Sales Volume	%	1%	1%	5%
Cost of sales	%	4%	7%	1%
Selling price	%	8%	8%	-3%
Profit/Loss per unit	%	819%	43%	-91%
Cash Profits	%	165%	34%	-39%
Return on Capital Employed	%	5%	2%	-6%

**g. Ability to raise capital investment**

84. The Authority notes that the Domestic Industry enhanced capacities during period of investigation and made fresh investments. The Domestic Industry contended that given the level of demand and number of producers of the product under consideration in the market, it is evident that there is significant scope for further investment in the product in the Country. However, the existing producers are staying away from significant capacity addition and new players are not joining for the reason that the existing capacities itself are remaining unutilized.

**h. Level of dumping & dumping margin**

85. The Authority notes that the imports from the subject country are far above the de minimis level of dumping margin. The dumping margin for subject country is quite significant.

**J. CONCLUSIONS ON INJURY**

86. Based on the above, the Authority concludes that the dumped imports of the subject goods from the subject country have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption of the subject goods in India. Imports of the product are undercutting the prices of the Domestic Industry in the market. Further, the imports were depressing the price of the Domestic Industry. It is observed that the demand for the product increased significantly and consequently production and sales of the Domestic Industry also increased, however, performance of the Domestic Industry deteriorated in respect of capacity utilization, inventories, profits, cash flows and return on investments.



87. The Authority noted that the Domestic Industry has suffered injury on account of volume as well as price effect of dumped imports, as a result of which the profitability of the Domestic Industry has declined. Return on capital employed and cash profits followed the same trend as that of profits. Growth of the Domestic Industry in respect of most of the parameters such as profits, cash profits, returns on capital employed, etc. was negative. Thus, Authority concludes that the Domestic Industry has suffered material injury.

#### **K. CAUSAL LINK AND NON ATTRIBUTION ANALYSIS**

88. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the Domestic Industry. The examination of causal link between dumping from subject country and material injury to the Domestic Industry has been done as follows:

##### **(a) Volume and prices of imports from third countries**

89. The imports from the countries other than the subject country are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the Domestic Industry. Imports from other countries accounted for less than 3% in total imports and 2% of total demand/consumption in India. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury.

##### **(b) Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers**

90. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject country compete directly with the subject goods supplied by the Domestic Industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like article and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the Domestic Industry.

##### **(c) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption**

91. The Authority notes that demand for the product showed increase during the injury period and also during the POI as compared to base year. Thus, it can be concluded that the injury to the Domestic Industry was not due to contraction in demand.

##### **(d) Development in Technology**

92. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the Domestic Industry.

##### **(e) Export performance of Domestic Industry;**

93. The Domestic Industry is primarily for sale of goods in the domestic market. However, the domestic sales and export performance has been separately analysed. It is clear that claimed injury to the Domestic Industry is not on account of any significant change in export performance of the Domestic Industry.

##### **(f) Productivity of the Domestic Industry**

94. The Authority notes that the deterioration in productivity has not caused injury to the Domestic Industry.

##### **(g) Performance of the Domestic Industry with respect to other products**

95. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry has not affected the Domestic Industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

#### **L. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK**

96. Analysis of the performance of the Domestic Industry over the injury period shows that the performance of the Domestic Industry has materially injured over the injury period and during the POI. The causal link between dumped imports and the injury to the Domestic Industry is established on the following grounds:

- i. Imports of the subject goods have increased in absolute terms over the entire period of investigation. Imports of the PUC from the subject country have increased in absolute terms. Also, the landed price of imports has been declining significantly over the injury period and through the POI.

- ii. Imports of the subject goods have increased relative to production and consumption in India.
- iii. Market share of dumped imports in total demand in India remained at about 30% during the Period of investigation which is a significant percentage. The Indian producers could capture only 68% of the demand in spite of having sufficient capacities. This is due to the reason that imports have aggressively captured the robust demand in India.
- iv. The Domestic Industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand. The Domestic Industry had significant unutilised capacity in the POI even though the demand had increased.
- v. Inventories of the Domestic Industry have been on the rise, as the Domestic Industry has not been able to increase its sales despite increase in demand. Imports have been aggressively capturing the demand in India.
- vi. There is significant price suppression and depression due to low priced dumped imports coming in to India.
- vii. The Domestic Industry's profitability and return on capital employed have been drastically affected. This is evident from the fact that the Domestic Industry was earning decent profits and return on capital employed till 2013-14. However, especially during the POI, the profits and returns have turned into huge losses and negative situations.
- viii. The above analysis indicates that the Domestic Industry is suffering material injury due to increasing dumped imports of PUC into India from subject country. There exists a strong causal relation between the increase in dumped imports of the subject goods originating in or exported from subject country and the material injury suffered by the Domestic Industry.

#### **M. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN**

97. The Authority has determined non-injurious price for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in the Rules, as amended. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject country. The injury margin so determined is significant.

Particulars	Rs/Kg	USD/Kg
Non Injurious Price (NIP)	***	***
Landed Price	102.45	1.55
Injury Margin	***	***
Injury Margin-%	***	***
Injury Margin (Range)	65%-75%	65%-75%

#### **N. POST DISCLOSURE COMMENTS**

98. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties are being examined as below:

##### **Views of the Domestic industry**

99. The Domestic Industry made the following submissions:

- i. The PUC is ceramic tableware and kitchenware. Bone china, stoneware and porcelain-ware constitute ceramic product and therefore appropriately covered under the scope of Product under consideration. Different types of ceramic tableware, kitchenware, cookware, serve ware etc. are not different and constitute one article; and it would not be appropriate to exclude a product type, if the domestic industry is manufacturing like article to the product being imported into India;
- ii. The Authority has rightly rejected exclusion of Sublimation/image cup and fire clay kitchenware as the same are being produced by the domestic industry.
- iii. The authority is requested to kindly give complete clarity on the fact that bone china, porcelain and stone ware fall under "ceramics product" and kitchenware, serve ware, table ware, etc. are merely

different terms used interchangeably in the trade parlance in order to avoid any issue in implementation.

- iv. Authority may kindly specify in duty table that the product under consideration should attract duty regardless of the customs classifications under which goods are being cleared by the importers. Further, the authority may kindly specify in duty table that the customs classification is indicative only. It is only the duty table contents that are relevant in this regard. Anything mentioned in the para relating to "product under consideration" but not stated in duty table is likely to get ignored while issuing notification by the Ministry of Finance. Further, the Customs authorities at the port consider and rely upon the notifications issued by the MOF. The customs authorities do not take cognizance of the notification issued by the DGAD as final findings. It is, therefore, utmost important that the duty table itself includes all these clarifications.
- v. The petitioner companies account for a major proportion in the gross domestic production of the like article and constitutes eligible Domestic Industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules.
- vi. The letter issued by CGCIR holds good and contained information with regard to both organized and unorganized companies. In the absence of specific information with regard to unorganized sector, the right of the organized sectors cannot be defeated.
- vii. The dumping margin and injury margin is quite significant.
- viii. The form of measure is required to be kept as fixed quantum and expressed in US Dollar.
- ix. The Authority is requested to affirm the preliminary finding.

#### **Views of the opposing interested parties**

100. The submissions of various opposing interested parties are summarized as follows:

- i. Cookware products should be excluded from the product scope since it is incorrect to say that terms kitchenware, tableware and cookware are used interchangeably in trade parlance. The authority should examine two-way substitutability of products i.e. in case of *Sodium Tripoly Phosphate*. Cookware products can be used for cooking and may be used for serving food and beverages but kitchenware and tableware cannot be used for cooking. Moreover, DGCI&S data provided by the petitioners itself specifically 'ceramic cookware' as NPUC. The Authority has relied upon the import data of the petition for preliminary findings and for disclosure, which excludes ceramic cookware from PUC. There is no change in import volume or value in the preliminary findings and disclosure statement from the import volume and value provided in the petition. Thus there is no analysis or determination that cookware products are being dumped or causing injury. The entire dumping and injury analysis in the petition, preliminary findings and the disclosure statement has been done based on the understanding that ceramic cookware was not a part of the import data. It is clear that once a scope of the product should not be expanded during the course of investigation. Therefore, the Authority should specifically provide that cookware products are excluded from PUC.
- ii. Fire clay products should be excluded from the PUC since it is used solely for the purpose cooking. The Authority cannot ignore the fact that fire clay cookware products are not manufactured in India. It is also incorrectly stated that the interested parties have not provided any information how these products do not constitute tableware or kitchenware of ceramics while requesting for exclusion.
- iii. Porcelain products should be excluded from the product scope since the petitioners do not have standing to file a petition for porcelain products as none of them manufacture porcelain products. Only M/s Umberto Ceramics International Pvt. Ltd. stated that they manufacture porcelain items in India, however, they are neither a part of the applicant nor a supporter to the petition.
- iv. The Authority, while doing its examination has completely overlooked the facts presented by the interested parties that the product under consideration in the investigation includes three types of products vis-a-vis Bone China wares, Porcelain wares, & Stoneware. Accordingly, there is a huge difference between the three types not only in terms of their composition but also on account of their costing, marketability, pricing, weight etc. The product under consideration also varies in terms of decoration and non-decoration. Therefore, any single dumping or injury margin on all the products concerned would not only be arbitrary but would lead to absurdity.

- v. The current investigation is without jurisdiction, suffer from material procedural irregularities which are incurable i.e. absence of proper authorization, unreliable data on production for determining the standing of the petitioner companies, misleading segregation of import data by the domestic industry. A major chunk of higher price entries relating to the subject country, which should have been part of the 'PUC' had been marked as 'NPUC' by the applicant. At the same time, there were entries which were marked as 'PUC' but were not actually a part of the definition of the product under consideration.
- vi. The assessment of standing of the domestic industry is incorrect. The Authority has accepted a very low share of 31% as sufficient to constitute major proportion in the facts and circumstances of the case. Existence of unorganized sector of Indian producers in itself does not allow the Authority to allow very low share of 31% to constitute as major proportion. The Authority can have flexibility to permit a low share of total production to constitute as major proportion when it faces practical difficulties due to existence of fragment market. In the present case, there are no practical difficulties that prevents participation of other Indian producers who have provided support letters and whose combined share is 31% in the total production. Moreover, mere supporting the petition by way of simple letter does not constitute support unless the complete details with regard to cost and other injury parameters is provided.
- vii. The documentary evidence submitted by the respondents, has been ignored in the disclosure statement. It may be recalled that in response to an RTI query, it has specifically been confirmed by the CSIR head office that they do not collect or maintain any record of total production of Ceramic tableware in India. It is, therefore, abundantly clear that when the principal body itself has formally confirmed that no such information is collected or maintained by them, the question of the same being provided by the regional office simply does not arise
- viii. The import statistics are improperly and incorrectly determined. Firstly, the authority did not provide any basis for import transaction for the preceding three years. Secondly it is incorrect to determine quality in weight terms of import transactions that are reported in sets/pieces/numbers etc based on the value of the import transactions reported in weight. Thirdly, the methodology used to determine import volume is not disclosed in part and is incorrect in part.
- ix. The interested parties have a vested right to get access to all the information filed by the applicants and the interested parties, irrespective of its form, as long as the same is a part of the official record on the basis of which the Authority proposes to rely upon, subject to the provisions of confidentiality. Denial of the soft copy of the data already on record (in soft format) would be a clear violation of the rules and the principles of natural justice. Despite repeated requests by the responding parties, neither the Authority nor the domestic industry provided the responding parties with the original import data used for the purpose of initiation of the investigation. It is reiterated that the import data filed by the applicants along with the application forms a part of the case record and there is no reason for denying access to the same to other interested parties.
- x. Assessment of injury to the Domestic Industry is incorrect. It is submitted that there cannot be an objective assessment of material injury to the Domestic Industry when the Domestic Industry has low share in total production. Large enough proportion of total domestic production is required to be assessed for determination of material injury when low share of Indian production is considered as sufficient for assessment of major proportion. In *EC-Fasteners*, it was noted that even in case of fragmented industries where low share of Domestic Industry is considered as constituting major proportion, there is a requirement to provide data of sufficiently large enough proportion of domestic production for the purpose of injury determination. Thus, the Authority is requested for complete information from other domestic producers for proper injury determination.
- xi. The petitioner's net sales realization during the POI was higher than NIP, in such scenario how the claims of petitioners regarding price suppression, depression and underselling is justified. This clearly means that imports had no impact on the petitioner during the POI. Thus the Authority is requested in terms of *Ammonium Nitrate originating from Russia and Iran, X-ray baggage imports from the EU and Nirma Ltd v. UOI*, to review its assessment of injury and terminate the investigation.
- xii. There is no causal link between the imports from the subject country and injury to the Domestic Industry. The Authority has wrongly noted market share which is 29.33% in POI and not about 50% as noted by the Authority. Sales & production of DI increased commensurately with increase in

- demand. Profitability, return on capital employed cannot be said to have affected drastically since it increased in POI as compared to the base year. Moreover, the DI is not suffering any losses, despite some decline in the POI it is still making profits. The observation that the DI could not increase selling price to remunerative level despite increase in cost of production is not supported by the data on record. The selling price and cost of sales increased commensurately.
- xiii. There is no co-incidence between the losses to the DI and the imports from China PR. The DI reported its highest profit increase in 2014-15 while the imports originating in China increases the most.
  - xiv. The Authority has wrongly noted that injury margin is substantial against all responding exporters and producers, since no producers or exporters have co-operated in the investigation.
  - xv. The Authority to kindly consider that this is a fit case where the anti-dumping duties should be recommended in percent terms only. The duty on the basis of USD/KG would lead to inverse effect of duty, as the higher end products would attract very little duty and the lower end products would attract unreasonably higher duty which would not only be unfair but would also cast unreasonable burden on the general public using lower end products.
  - xvi. The NIP has been improperly determined. The Authority is required to determine NIP based on Annexure III of anti-dumping rules, however as per the disclosure there is no mention s such determination by the Authority. Thus the Authority is requested to clarify and issue revised determination of NIP based on applicable rule.
  - xvii. The Authority is requested for an opportunity to explain the issues which have unfortunately not been addressed or overlooked in the disclosure statement. It may be pertinent to mention that in the past many cases, the Authority has indeed given post-disclosure statement hearings.

#### **Examination by the Authority**

101. It is noted that the issues raised at post disclosure stage have already been examined by the Authority in above relevant paragraphs, however for the sake of the clarity of the submissions they are addressed as below:

- i. As regards the scope of PUC, it has been observed that the Authority had addressed the concerns of all the interested parties and after detailed examination clearly determined the scope of the PUC in the above paras of the findings.
- ii. The various exclusions sought by the interested parties have been examined item by item and addressed in detail in relevant paras of this finding. The specific exclusion again requested by the importer pertaining to Cookwares was re-examined, and the Authority reiterates that Ceramic Cookwares can also be used as Servewares and would logically fall under the category of tableware/kitchenware and hence covered within the scope of the PUC under the present investigation.
- iii. As regards the standing of the Domestic Industry, the Authority has relied upon the best available information. Further, it is noted that the petitioners cannot be denied relief under the law in view of absence of precise information with regard to production of individual companies in the unorganized sector. The precedent for such determination is available in some of the earlier determination by the Directorate e.g. AA batteries, lead acid batteries, silk fabric and silk yarn etc., where the production was determined based on the assessment as per the available credible relevant source of information in those investigations. Therefore, the Authority has considered appropriate to accept the petitioners as the eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) of the Rules.
- iv. As regards the procurement of CGCRI letter, it is reiterated that the concerned letter is kept in the public file for inspection by all the interested parties.
- v. As regards the import data, it has been observed that the Authority had clearly stated that it has relied upon import data procured from DGCI&S in the present investigation; the same has also been mentioned in the above concerned para of the finding.
- vi. As regards the determination of NIP, it has been observed that NIP has been determined as per the provisions of Annexure III of Custom Notification No. 15/2011-customs (N.T) dated 1<sup>st</sup> March,

2011, which laid down the principles for determination of Non-injurious Price and the rules and the uniform practice followed in the Directorate for the calculations.

- vii. As regards the post-disclosure statement hearing, it has been observed that, as per Rule 6(6), the Authority has provided the opportunity of hearing to all the interested parties to present their views orally in front of the Designated Authority. Here it is pertinent to mention that in the present case, all the interested parties have been provided two opportunities of hearings on account of the changed Designated Authority, hence the argument of providing another hearing post the issuance of Disclosure is redundant, also it must be noted that the Rule 6(6) gives discretion to the Authority to provide hearing to all the interested parties, it is not a mandatory provision, hence all the interested parties had enough opportunity to present their views orally as well as in written, which have been duly addressed by the Authority in the present finding. Request for another hearing is redundant and without any substantial grounds.

#### **O. CONCLUSIONS**

102. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:

- i. The product under consideration has been exported to India from the subject country below its normal value, resulting in dumping.
- ii. The Domestic Industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject country.
- iii. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject country.

#### **P. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES:**

103. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the downstream products and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the antidumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the Domestic Industry. On the contrary, imposition of antidumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the Domestic Industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

#### **Q. RECOMMENDATION**

104. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- i. The product under consideration has been exported to India from subject country at dumped prices.
- ii. The Domestic Industry has suffered material injury.
- iii. Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from subject country.

105. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the Domestic Industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

106. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. Accordingly, the Authority recommends confirmation of provisional anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR as was recommended in the preliminary finding notification dated 4.5.2017 and notified vide Customs Notification No..27/2017-Customs (ADD) dated 12.6.2017, as mentioned in Column 9 of the duty table as below.

**DUTY TABLE**

Sl. No.	Tariff Item*	Description of Goods**	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount (in USD)	UOM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6911 and 6912	Ceramic Tablewares and Kitchenwares	Any	China PR	China PR	Any	Any	1.04	KG
2	6911 and 6912	Ceramic Tablewares and Kitchenwares	Any	China PR	Any	Any	Any	1.04	KG
3	6911 and 6912	Ceramic Tablewares and Kitchenwares	Any	Any	China PR	Any	Any	1.04	KG

\* Custom classification is only indicative;

\*\* Description of the Product under consideration is “Ceramic table wares and kitchen wares, excluding knives and toilet items”. Bone china, stoneware and porcelain-ware all constitute ceramic products as detailed in para 20 above.

107. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

108. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority